R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 19 । अंक : 23
01 से 15 सितंबर 2021
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

साम्राज्यों का कब्रिस्तान

अफगानिस्तान में अब तालिबानी राज

लहूलुहान अफगानिस्तान
कैसे चलेगा तालिबान राज?

अमेरिकी सैनिकों का
काबुल को अलविदा...

WHERE EFFECTIVE DIABETES AND THALASSEMIA TREATMENT BEGINS

Because completing multiple tests in fewer steps supports more than just your workflow—it's a big part of delivering timely, effective care.

Flexible

- Easy switching between HbA1c and B-thalassemia testing without changing reagents or cartridge
- Rapid 3 minute HbA1c program
- Complete B-thalassemia program including HbA1c results
- Expandable for higher volumes with the D-10™ Rack Loader

Comprehensive Testing

- B-thalassemia and diabetes testing
- Simultaneous quantitative HbA2, HbF and HbA1c determination
- Accurate HbA2 and Hbf results in just 6.5 minutes
- Detection of common hemoglobin variants
- HbA1c reportability in the presence of Hb S, C, D and E

Easy to Use

- Touchscreen operation
- One-step cartridge switching
- Fully automated with bar code reading and primary tube sampling
- Simplified user maintenance

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Anu Sales Corporation

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M.: 9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजकाज

9 | ओबीसी की सियासत

मप्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच बिना चुनाव के शह-मात का खेल चरम पर है। इस खेल की वजह है प्रदेश की 52 फीसदी ओबीसी आबादी। मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में विधेयक संसद के दोनों सदन...

लालफीताशाही

15 | बिजली कंपनियों का खेल

मप्र देश में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। लेकिन विसंगति यह है कि इसके बावजूद यहां के लोगों को देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है। इसकी वजह यह है कि बिजली कंपनियां हर साल घाटा दिखाकर बिजली की दरें...

चौसर

16-17 | मिशन-4 की कसौटी

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक पैंतरेबाजी कब क्या गुल खिला दे इसका आंकलन कोई नहीं कर सकता है। मप्र की राजनीति में भी इन दिनों नया गुल खिलाया जा रहा है। यानी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ज्योतिरादित्य...

आर्थिकी

18 | 10 हजार एकड़ का बनेगा लैंडबैंक

मप्र को इंडस्ट्रीयल हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए प्रदेश के हर क्षेत्र में लैंड बैंक बनाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक निवेशक यहां उद्योग-धंधे स्थापित कर सकें। मप्र औद्योगिक विकास निगम को लगातार निवेशकों के अच्छे प्रस्ताव...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

साम्राज्यों के कब्रिस्तान के नाम से ख्यात अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी राज कायम हो गया है। करीब दो दशक तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। 30-31 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजते ही आखिरी अमेरिकी सैनिक ने काबुल की धरती को अलविदा कहा। इसी के बाद अब तालिबान का अफगानिस्तान पर एकछत्र राज स्थापित हो गया है। अब देखना यह है कि वैश्विक ताकतों की हसरतों से लहूलुहान अफगानिस्तान में तालिबान किस तरह राज कर पाता है।

राजनीति

30-31 | विकल्प की तलाश

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जितने भी आंकलन किए गए हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज हुई है। विपक्ष इसे बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। इसके लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट भी होने लगी हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि विश्व की सबसे...

महाराष्ट्र

35 | राणे महज एक मोहरा

नारायण राणे भाजपा-शिवसेना के झगड़े में महज एक मोहरा हैं। राणे को केंद्रीय मंत्री बनाकर भाजपा नेतृत्व ने एक सोची समझी चाल चली थी। फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पलटवार में शह देने की कोशिश की है, लेकिन अब ये एक नए खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है।

बिहार

38 | जातीय जनगणना सियासी शस्त्र

जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अब यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं। जहां तक देश में जनगणना...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

कहीं 2003 वाली स्थिति तो नहीं बन रही

शायर शफीक जौनपुरी का एक शेर है...

फरेब-ए-रौशनी में आने वालो मैं न कहता था
कि बिजली आशियाने की निगहबां हो नहीं सकती

ऐसी ही कुछ स्थिति मप्र में बिजली की हो गई है। सरकार के दावे के अनुसार प्रदेश में जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन आलम यह है कि हर रोज शहरी क्षेत्रों में 3 से 5 घंटे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 15 घंटे बिजली गुल हो रही है। बिजली कटौती की 3 वजह सामने आई हैं। बिजली कंपनियों की देनदारियां, बांधों में कम पानी और सरकार से कंपनियों को सब्सिडी नहीं मिलना। प्रदेश के 3 थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन बंद हो गया है। सरकार फिलहाल निजी क्षेत्र से बिजली खरीदकर सप्लाई कर रही है। लेकिन फिर भी आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका तो मिल ही गया है, साथ ही अपने भी मुखर हो गए हैं। वर्तमान समय में जो हालात नजर आ रहे हैं वे 2003 की याद दिला रहे हैं। 2003 में प्रदेश में सड़क और बिजली की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। उस समय विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सड़क और बिजली को मुद्दा बनाकर जनता के बीच कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जिससे दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल पर ग्रहण लग गया। वर्तमान में ग्वालियर-चंबल संभाग को छोड़ भी दें तो पूरे प्रदेश में सड़कें छलनी बन गई हैं। आलम यह है कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, वहीं बिजली की कटौती ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। आलम यह है कि अब तो भाजपा के विधायक ही बिजली कटौती का राग अलापने लगे हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय विश्नोई, नारायण त्रिपाठी और राकेश गिरी ने बिजली कटौती पर अपनी ही सरकार को घेरा है। इन नेताओं का कहना है कि हर रोज 12 से 15 घंटे बिजली बंद होने से किसान परेशान हैं। किसान फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में रबी का सीजन आने वाला है। इसके चलते अक्टूबर से बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी। प्रदेश में रबी सीजन में यह डिमांड बढ़कर 16 से 17 हजार मेगावाट हो जाएगी। ऐसे में बिजली का उत्पादन कम हुआ तो बिजली संकट गहराने के पूरे आसार हैं। फिलहाल सरकार निजी क्षेत्र से बिजली खरीदकर आपूर्ति कर रही है। उधर, कांग्रेस ने भी बिजली कटौती को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का कहना है कि मप्र में बिजली का संकट दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों व कृषि क्षेत्रों में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। कई-कई घंटों की अघोषित कटौती की जा रही है। कोयले की कमी के कारण उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। कई ताप विद्युत परियोजनाएं बंद होने की कगार पर हैं। मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर सामने आ रहा है। सरकार इन सब मामलों से बेखबर बनी हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि बिजली कटौती का समाधान ढूंढने की बजाय सरकार में बैठे कुछ लोग इसकी वजह कमलनाथ सरकार को बताते हैं। प्रदेश में आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं और उसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी होंगे। ऐसे में बिजली कटौती और खराब सड़कें सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। हालांकि सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन कर्ज में डूबी सरकार इन समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएगी इसको लेकर सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 23, पृष्ठ-48, 1 से 15 सितंबर, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो

- मुंबई : ऋतेन्द्र माथुर
- नई दिल्ली : जगदीश प्रसाद
- कोलकाता : इंद्रकुमार
- जयपुर : आर.के. बिन्नानी
- रायपुर : संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी
- भिलाई : टी.पी. सिंह
- लखनऊ : मधु आलोक निगम

प्रदेश संवाददाता

- विकास दुबे 094251 25096 (इंदौर)
- धर्मेन्द्र कथूरिया 098276 18400 (जबलपुर)
- श्यामसिंह सिकरवार 094259 85070, (उज्जैन)
- ज्योत्सना अनूप यादव 098934 77156, (विदिशा)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

किसानों का हाल बुरा

प्रदेश में किसानों का हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। यहां के किसान अपनी फसलों को अच्छे दामों में बेच नहीं पा रहे हैं। रही सही कसर बाढ़ ने निकाल दी है। किसानों के फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब वे अपनी बर्बाद फसलों के मुआवजे के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं।

● **निशा राठी,** इंदौर (म.प्र.)

राशन में भ्रष्टाचार

गरीबों के राशन वितरण में हर सरकार में भ्रष्टाचार होता रहा है। थैले की खरीदी प्रक्रिया में भी ऐसा ही वाकया सामने आ गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश के हर गरीब की भूख मिटाने के अभियान में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के ही लोग उस पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं।

● **प्रशांत वर्मा,** सीहोर (म.प्र.)

चुनावी तैयारी में भाजपा

भाजपा में शिवराज ऐसा चेहरा हैं जिसे प्रदेश की जनता अपना मानती है। इसलिए पार्टी हर चुनावी मोर्चे पर उन्हें आगे रखती है। वहीं वीडी शर्मा मप्र भाजपा के लिए शुभंकर बन गए हैं। आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार चुकी है।

● **शब्बीर खान,** जबलपुर (म.प्र.)

बाढ़ से प्रभावित हुए हजारों परिवार

मप्र के ग्वालियर–चंबल में आई बाढ़ ने हजारों लोगों को प्रभावित किया है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को फिलहाल 6-6 हजार रुपए की राहत राशि दी है। सरकार बाढ़ से राहत के लिए रास्ते निकाल रही है। जो लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उन्हें ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। जिनके मकान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए नए आवास ऊंचे स्थानों पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी बाढ़ प्रभावितों पर नजर रखे हुए है। कई परिवारों के सिलेंडर बाढ़ में बह गए। उन्हें दोबारा सिलेंडर दिलाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया है।

● **प्रभु माणिक,** ग्वालियर (म.प्र.)

मजबूत हो विपक्ष

देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। आज सत्ता के सामने कोई भी मजबूत विपक्ष नहीं है। अपनी राजनीतिक गति और रणनीति से चमक रही भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना चाहता है, लेकिन उसे इतिहास भी याद है और आज के दिन विचारधारा से लेकर रणनीति तक के स्तर पर आपसी टकराव की जानकारी भी। विपक्ष का संख्याबल कमजोर नहीं कहा जा सकता, न लोकसभा में और न ही राज्यसभा में। वह जमाना बीत गया जब सदन की कार्यवाही बाधित होना बड़ी खबर बनती थी।

● **स्वप्निल मिश्रा,** नई दिल्ली

मप्र फिर टाइगर स्टेटर

मप्र फिर से टाइगर स्टेट बनने की राह पर है। वर्ष 2018 में पन्ना से बाघों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। वन विभाग द्वारा बाघ संरक्षण के लिए सक्रिय पहल की गई, जिसमें बाघों को अन्य संरक्षित क्षेत्रों से लाकर पन्ना टाइगर रिजर्व में पुनर्स्थापित किया गया। पिछले 9 वर्ष की सतत प्रक्रिया के कारण आज पन्ना टाइगर रिजर्व पुराने वैभव की ओर लौट चुका है। यहां 20 से ज्यादा वयस्क बाघ और 15 अवयस्क बाघ–शावक मौजूद हैं।

● **केशव शर्मा,** रायसेन (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

सिलसिला-ए-संकट

लगता है कि कांग्रेस में आलाकमान का अब क्षत्रपों को कोई खौफ नहीं रह गया है। पंजाब में पार्टी का अंदरूनी संकट अभी पूरी तरह टला भी नहीं कि छत्तीसगढ़ में असंतोष और गुटबाजी अचानक सतह पर आ गई है। शुरुआत हालांकि पिछले साल मप्र से हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आलाकमान ने समय रहते तवज्जो दी होती और कमलनाथ को बाध्य किया होता कि वे सबको साथ लेकर चलें तो सरकार क्यों गिरती? राजस्थान में भी यही अध्याय दोहराया था सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मूंछ की लड़ाई ने। गहलोत लाख डींगे मारते रहे कि वे सियासत से पहले जादूगरी करते थे और अपनी सियासी जादूगरी से उन्होंने सचिन पायलट को चारों खाने चित कर दिया। पर हकीकत यह है कि भाजपा के अंतरविरोध व वसुंधरा राजे के रुख से बची है गहलोत सरकार। पंजाब में चूंकि भाजपा के लिए खेल करने लायक मैदान था नहीं सो वहां प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने गुटबाजी को कम से कम पार्टी के विभाजन की स्थिति तक पहुंचने से बचा लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में संकट बरकरार है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आलाकमान को उसका वादा याद दिलाकर उसकी नींद उड़ा दी है। सूबे में 2018 में कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीतकर भाजपा की हवा निकाल दी थी।

दिन बहुरेंगे आजाद के

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलामनबी आजाद एक बार फिर से गांधी परिवार की 'गुड बुक्स' में आते दिख रहे हैं। चर्चा जोरों पर है कि असंतुष्ट कांग्रेसियों में शामिल आजाद इन दिनों कपिल सिब्बल सरीखे असंतुष्टों संग दूरी बरत रहे हैं। इसके ईनाम बतौर कांग्रेस उन्हें तमिलनाडु से राज्यसभा भेज सकती है। अन्नाद्रमुक नेता ए मोहम्मदजान की मृत्यु के चलते खाली हुई राज्यसभा सीट का अभी पौने पांच साल का कार्यकाल बाकी है। सूत्रों की मानें तो द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एके स्टालिन इस सीट को कांग्रेस के लिए देने की हामी भर चुके हैं। चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस आलाकमान इस सीट से गुलामनबी को दोबारा राज्यसभा में भेजने का मन बना चुका है। खबर यह भी गर्म है कि आजाद को एक बार फिर से राज्यसभा में नेता विरोधी दल बनाया जा सकता है। इस सबके बीच वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के तेवर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ तेजी से बढ़ने का एक बड़ा कारण सिब्बल को पार्टी के भीतर पूरी तरह हाशिए में डाल दिया जाना है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सिब्बल जल्द ही पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं।

पंजाब से परेशान रावत

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रांत के प्रभारी हरीश रावत इन दिनों कई मोर्चों पर एक साथ युद्धरत हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के एक धड़े के लाख प्रयास करने के बाद भी अंतत: पार्टी आलाकमान ने अगले वर्ष होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनावों की कमान रावत के हाथों में सौंप तो दी लेकिन रावत के कट्टर विरोधी पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना हरीश रावत के लिए घर के भीतर ही संकट पैदा कर डाला है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की कमान रावत के अति करीबी गणेश गोदियाल को जरूर मिल गई है लेकिन उनके साथ चार कार्यकारी अध्यक्षों में से तीन रावत विरोधी गुट के बना डाले हैं। ऐसे में टीम रावत खुद को अपमानित महसूस तो कर ही रही है। टिकट वितरण को लेकर भी भारी घमासान की उसे आशंका सता रही है। हर कीमत पर कांग्रेस की सरकार वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे रावत का एक अन्य संकट पंजाब का प्रभार है। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को राजी करवाने में रावत की सबसे अहम भूमिका रही। इस कार्य को अंजाम देने के तुरंत बाद ही पार्टी आलाकमान ने रावत को उत्तराखंड चुनाव की कमान सौंप यह संकेत दिया था कि अब उन्हें पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा।

बेकाबू मंत्री सांसद में धामी

उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सरकार को एक काम करने वाली सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता संभालने के साथ ही उन्होंने प्रदेश की बेलगाम हो चली नौकरशाही पर नकेल डालने की नीयत से ताकतवर कहलाए जाने वाले अफसरों के पर कतर डाले। इससे आमजन में अच्छा संदेश गया। राज्य की ब्यूरोक्रेसी में एक प्रदेश विशेष से ताल्लुक रखने वाले अफसरों का गठजोड़ बन चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में इस गठजोड़ ने पूरे सिस्टम को हलकान कर रखा था। धामी ने पद संभालने के साथ ही मुख्य सचिव पद से ओम प्रकाश की विदाई कर इस गठजोड़ को बैकफुट पर लाने का काम किया। इसके बाद त्रिवेंद्र काल के दौरान समांतर सरकार का पर्याय बन चुके एक आईएएस दंपति को मुख्यमंत्री सचिवालय से बाहर कर धामी ने अपनी नो नॉनसेन्स छवि को चमकाया। केंद्र सरकार से कई सौ करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटन कराने में भी उन्होंने सफलता पाई है।

ममता का मिशन नॉर्थ ईस्ट

वर्ष 2024 के आम चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की पुरजोर कोशिश में जुटीं ममता बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस का तेजी से विस्तार करने में जुट गई हैं। जानकारों की मानें तो ममता का फोकस पश्चिम बंगाल से सटे त्रिपुरा के साथ-साथ उत्तर-पूर्व के दो अन्य राज्यों मेघालय और असम में भी पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने पर है। तृणमूल रणनीतिकारों का मानना है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्व. पीए संगमा की खासी करीबी रहीं ममता आसानी से उनके पुत्र और मेघालय के मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा को अपनी तरफ खींच सकती हैं। वर्तमान में संगमा की पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। इन रणनीतिकारों की मानें तो 2022 और 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहेगा और कई राज्यों में वह सत्ता से बाहर हो जाएगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन में टूट के आसार तेज होंगे। इसी प्रकार असम में भी एंटी भाजपा ताकतों संग ममता इन दिनों लगातार संपर्क में बताई जा रही हैं।

पैसे और नशे का गुरूर

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिस जिले को मॉडल मानकर प्रदेश में विकास करने की कल्पना की थी इन दिनों उस जिले के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया पर पैसे और नशे का सुरूर और गुरूर इस कदर सवार है कि वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। सूत्रों की माने तो यह जोड़ी जिले में खूब कमाई कर रही है। अथाह कमाई के सागर में डूबे दोनों साहेबानों पर नशा भी सवार हो गया है। एक तो करैला और उस पर नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ होने लगी है। यानी काली कमाई कर रहे दोनों साहब पर सुरा का नशा कभी-कभी ऐसा चढ़ जाता है कि वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। लेकिन इन दिनों दोनों साहब एक मीडियाकर्मी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई की किसी रोज नशे में दोनों साहेबान ने सारी हदे पार करते हुए यह कह दिया कि हमारे आगे किसी और की कोई औकात नहीं है। हम तो हर माह मंत्रालय की चौथी मंजिल पर 10... और 5... पहुंचाते हैं। उनकी इस बात को एक मीडियाकर्मी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब आलम यह है कि उक्त मीडियाकर्मी उनके उस बयान को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। जिले में अच्छे-अच्छों को परेशान करने वाले प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया जब उक्त पत्रकार को देखते हैं तो उन पर चढ़ा पैसे और नशे का सुरूर और गुरूर उतर जाता है। अब देखना यह है कि यह खेल किस मुकाम पर खत्म होता है।

मैडम का सोना प्रेम

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक प्रमोटी आईपीएस अफसर की पत्नी का सोने से लगाव चर्चा का केंद्र बना हुआ है। साहब इन दिनों अफीम उत्पादक एक जिले में एसपी हैं। बताया जा रहा है कि साहब अपनी ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैडम उनके विपरीत हैं। विगत दिनों साहब के साहबजादे का बर्थ डे था। जिले के व्यवसायी से लेकर उनके मातहत अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार बर्थ डे गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे थे। तभी सभी के पास मैडम का संदेश पहुंचा कि गिफ्ट में वे लोग सोने से बने आभूषण ही लेकर आएं। मजबूरी में लोगों को ऐसा करना पड़ा। लेकिन साहब की मैडम की यह हरकत जिले से निकलकर अब मुख्यालय होते हुए पुलिस के मुखिया तक पहुंच गई है। यहां यह बता दें कि आईपीएस अफसरों का गोल्ड प्रेम किसी से छुपा नहीं है। जब भी मौका मिलता है वे सोना बटोरने का मौका नहीं चूकते हैं। विगत दिनों एक जिले में एक जब्ती के दौरान उक्त जिले के एसपी साहब ने जब्ती के गोल्ड में डंडी मार ली थी। इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। अब देखना यह है कि अफीम उत्पादक जिले के एसपी साहब की मैडम का सोना प्रेम क्या गुल खिलाता है।

दिलजले का जलजला

प्रदेश के सबसे कमाऊ विभाग में इन दिनों एक दिलजले का शिकायती पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। 22 पेज के इस शिकायती पत्र की चर्चा पूरी प्रशासनिक वीथिका में भी हो रही है। दरअसल, विभाग के कमिश्नर का टारगेट करके लिए गए इस पत्र में विभाग की कारगुजारिया नमक-मिर्च लगाकर लिखी गई हैं। विभाग के लोग तो जानते हैं कि पत्र में अधिकांश बातें असत्य पर आधारित हैं, लेकिन दूसरे लोग उसे सत्य मान रहे हैं। वैसे विभाग में क्या चलता है और क्या चल रहा है इसे राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में तो लगभग सभी जानते हैं। लेकिन जिस दिलजले ने यह पत्र लिखा है उसने अधिकतर असत्य ही लिखा है। माना जा रहा है कि इस कमाऊ विभाग में अपनी दाल नहीं गलने पर किसी ने साहब को बदनाम करने के लिए यह पत्र लिखवाया होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम से यह पत्र लिखा गया है उसने एफिडेविट देकर स्पष्टीकरण दिया है कि मैंने यह शिकायती पत्र नहीं लिखा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि साहब की छवि खराब करने के लिए किसी दिलजले ने असत्य का सहारा लेकर यह पत्र लिखा है। वैसे यह बता दें कि यह विभाग अपनी काली करतूतों के लिए हमेशा से कुख्यात रहा है। साहब के आने के बाद से विभाग में बहुत कुछ बदलाव आया है। लेकिन विभाग के मंत्री के एक कांग्रेसी दोस्त विभाग पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं और तथाकथित तौर पर वे मंत्रीजी के लिए मनमानी कमाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण साहब की ईमानदारी पर दाग लगाया जा रहा है।

मंत्री जी की नहीं गली दाल

प्रदेश के एक सबसे बड़े और विख्यात जिले का प्रभार मिलने के बाद एक मंत्रीजी उस जिले में अपने हिसाब से जमावट करने में जुटे हुए हैं, ताकि उन पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। लेकिन विगत दिनों मंत्री जी को उन्हीं के विभाग के बड़े अफसर ने ठेंगा दिखा दिया। दरअसल, मंत्री जी मालवा क्षेत्र के इस बड़े महानगर में अपने कलेक्शन मास्टर के तौर पर एक इंस्पेक्टर को मनपसंद थाना दिलवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जोन के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को निर्देशित भी किया था। बताया जाता है कि जब जिले में पुलिस की जमावट की गई तो मंत्रीजी के चहेते को उसकी पसंद का थाना नहीं मिला। ये भी बताया जाता है कि अपनी ईमानदार छवि के लिए ख्यात साहब ने उन अफसरों को महत्व दिया जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर दिखे। वहीं सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी के कलेक्शन मास्टर के रूप में पहले से एक सीएसपी काम कर रहे हैं। मंत्रीजी की इच्छा है कि जिले में पग-पग पर ऐसे लोग पदस्थ रहें जो उनके लिए लक्ष्मीजी की व्यवस्था करते रहें। गौरतलब है कि मंत्रीजी लक्ष्मी के बड़े भक्त हैं।

चौथी मंजिल के सहारे

कहा जाता है कि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में चौथी मंजिल का साथ जिसको मिल जाता है, वह कुछ भी कर सकता है। इस बात को चरितार्थ किया है मालवा क्षेत्र के एक आबकारी अधिकारी ने। मालवा क्षेत्र में उपायुक्त के पद पर पदस्थ उक्त अधिकारी चौथी मंजिल के सहारे अपनों को मनमानी जगह दिलाने में जुट गए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने साले को राजधानी में आबकारी विभाग का सहायक आयुक्त बनवाया है। अब सहायक आयुक्त बने महोदय अपने जीजा के सहारे अपने भाई को मालवा के एक बड़े जोन का पुलिस मुखिया बनवाना चाह रहे हैं। वर्तमान में बुंदेलखंड के एक जोन में पुलिस मुखिया के पद पर पदस्थ ये साहब मालवा के एक जोन का पुलिस मुखिया बनना चाह रहे हैं। हालांकि पुलिस विभाग के मुखिया ने इसके लिए मना कर दिया है। लेकिन भरी अटैची के दम पर साहब हर हाल में मालवा के उक्त जोन का मुखिया बनना चाह रहे हैं। ऐसे में मालवा में उपायुक्त पद पर पदस्थ साहब अब चौथी मंजिल में जुगाड़ लगा रहे हैं। देखना यह है कि उनकी दाल गल पाती है या नहीं।

मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ होता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार होंगे। मैंने जो कुछ भी कहा है, उसके लिए मुझे तनिक भी अफसोस नहीं है। मुझे सिद्धू का सलाहकार बनना कई लोगों को पसंद नहीं था। उसमें कैप्टन भी शामिल हैं।

● **मालविंदर सिंह माली**

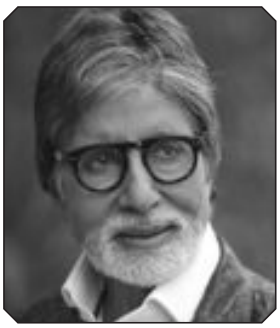

अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने यह डिसाइड कर लिया है कि इस फिल्म को बनाने में यह प्रोटोकॉल होगा, तो हमें उसे फोलो करना चाहिए। यही कारण है कि मैं बार-बार तैयारी करता हूं। मेरी उम्र में, हम जल्दी लाइंस को याद नहीं रख सकते हैं। मैं रिहर्सल करता हूं, ताकि मेरे दिमाग में कहीं लाइनें रह न जाएं। मेरे कई को-स्टार कहते हैं, आप बहुत रिहर्सल करते हो।

● **अमिताभ बच्चन**

काबुल में फिर से खून बह रहा है। अफगानियों को मारना बंद करो प्लीज। अफगानिस्तान लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में बाधा खड़ी करना ठीक नहीं है। अफगानिस्तान में सरकार कोई भी बनाए, लेकिन अमन-चैन बरकरार रखना चाहिए। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और वर्तमान स्थिति दर्दनाक है। इसे सहन करना तकलीफदायक है।

● **राशिद खान**

हमें आईएसआई के उन नेताओं के बारे में पता है, जिन्होंने काबुल में हमले का आदेश दिया था। हम बिना किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के उन्हें ढूंढ निकालने के रास्ते खोज लेंगे, चाहे वे कहीं भी हों। हम काबुल हमले का बदला जरूर लेंगे।

● **जो बाइडेन**

हम अपनी जिंदगी को तब तक इंट्रेस्टिंग नहीं बना सकते जब तक इधर-उधर छोटी-मोटी गलतियां ना करें। हां ये खतरनाक गलतियां ना हों जिससे दूसरी भावनाओं को ठेस पहुंचे लेकिन गलतियां होती रहनी चाहिए। हम गलतियों को चाहे तो उन चीजों की तरह देख सकते हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं या फिर इन्हें दिलचस्प होने की वजह से याद रखना चाहते हैं। मैं गलतियां करती रहूंगी, खुद को माफ करती रहूंगी और उनसे सीखती रहूंगी। मैंने गलती की लेकिन ठीक है।

● **शिल्पा शेट्टी**

वाक्युद्ध

देश में बेरोजगारी और गरीबी लगातार बढ़ रही है। इसका समाधान करने की बजाय सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में पिछले 70 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वे उन्हीं संस्थानों को बेचने जा रहे हैं, जिन्होंने विकास की मिसाल पेश की है।

● **रणदीप सुरजेवाला**

देश की अर्थव्यवस्था को बदहाल करने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। कांग्रेस ने देश पर जो बोझ डाल रखा था, उसे अब भाजपा सरकार उतार रही है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपने घर को दुरुस्त करे, वरना सबकुछ बिखर जाएगा।

● **संबित पात्रा**

ओबीसी की सियासत

मप्र में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है। इस बड़े वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने पासे फेंक रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस के दांव पर अपना दांव चला है। जहां केंद्र ने ओबीसी की सूची में अन्य जातियों को जोड़ने का अधिकार राज्यों को दे दिया है, वहीं मप्र में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलवाने पार्टी हाईकोर्ट में चली गई है।

मप्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच बिना चुनाव के शह-मात का खेल चरम पर है। इस खेल की वजह है प्रदेश की 52 फीसदी ओबीसी आबादी। मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में विधेयक संसद के दोनों सदन से पारित करा लिया है, जिसका असर भविष्य में पूरे देश में सामाजिक, और आर्थिक क्षेत्र के साथ सियासत पर भी गहराई से पड़ना तय है। इसकी बानगी उस मप्र में जारी सियासी सरगर्मी को लेकर देखी जा सकती है, जो आमतौर पर जातिगत समीकरणों के भरोसे सियासत की पहचान नहीं रखता। यहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने को लेकर मामला हाईकोर्ट में है। ये बढ़ोतरी कमलनाथ सरकार की कैबिनेट पास कर चुकी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर एक सितंबर को आने वाले फैसले का इंतजार है। सियासी पहलू देखें तो आरक्षण का मामला बेहद पेंचीदा है, साथ ही सियासी नफे-नुकसान के साथ सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाला है। आने वाले फैसले के संदर्भ में देखें तो कई परिस्थितियां बन सकती हैं, जिस पर यहां चर्चा की जाएगी।

एक स्थिति बन सकती है, जब आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दी जाए। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों इसे अपने प्रयासों का सुफल बताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार ने ही इसे कैबिनेट से पारित कर लागू करवाया था। हालांकि भाजपा पहले से इस मामले पर हमलावर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि कांग्रेस सरकार ने अधूरी तैयारियों से इसे पास किया था। इसकी जरूरत को लेकर न कमेटी बनी, न आयोग और सीधे लागू करने की कोशिश हुई, बाद में भाजपा सरकार ने मजबूती से पक्ष रखकर जीत हासिल की।

दूसरी स्थिति बन सकती है, जब आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत ही रह जाए। ऐसे में कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर भाजपा सरकार पर कमजोर पैरवी का आरोप लगाएगी, जिसे बीते दिनों कमलनाथ के बयानों में सुना जा चुका है। इधर, भाजपा इसे कमलनाथ सरकार की खामियों का नतीजा बताएगी ही। चूंकि चौहान खुद ओबीसी हैं और उनकी कैबिनेट में भी **एक-तिहाई मंत्री** इसी वर्ग से हैं, तो उन्हें इस वर्ग के बीच बात रखने का मौका कांग्रेस की अपेक्षा अधिक बेहतर मिल सकेगा।

इन दोनों परिस्थितियों के सियासी संदर्भ का अनुमान लगाना भी कठिन नहीं है। इसमें कांग्रेस के मुकाबले भाजपा का फायदा अधिक अनुमानित है। वजह है भाजपा में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का ओबीसी होना और दोनों की कैबिनेट में इस वर्ग को महत्व मिलना। चौहान की 31 सदस्यीय कैबिनेट में 10 मंत्री ओबीसी से आते हैं, जबकि कमलनाथ सरकार की 29 सदस्यीय कैबिनेट में ये आंकड़ा 8 था। मोदी की कैबिनेट में 27 मंत्री इसी वर्ग से आते हैं। मप्र में कांग्रेस के साथ मुश्किल है कि उसके पास ओबीसी वर्ग से गिने-चुने चेहरे हैं, लेकिन आपसी खींचतान में वह संगठन में ही अस्तित्व का संघर्ष करते नजर आ रहे हैं।

उधर, प्रदेश में ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण देने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बीच महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सरकार को महत्वपूर्ण अभिमत दिया है। कौरव ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर बताया है कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामले में सरकार स्वतंत्र है। ओबीसी आरक्षण के मामले में महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने सिर्फ पीसी नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है।

● **कुमार विनोद**

दिल्ली में बनाई रणनीति

पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए सरकार उच्च न्यायालय में देश के बड़े वकीलों को पक्ष रखने के लिए खड़ा करेगी। इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव भी मौजूद थे। पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सरकार की ओर से इस संबंध में सभी स्थगन हटाने के लिए अंतरिम आवेदन दायर किया गया। मामले की सुनवाई सितंबर में होनी है। सरकार का प्रयास है कि इस मामले में अगली सुनवाई अंतिम हो। इसके मद्देनजर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री भोपाल में महाधिवक्ता सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ इस मामले में विचार-विमर्श कर चुके हैं। इसमें निर्णय लिया गया है कि देश के बड़े वकीलों को सरकार का पक्ष दमदारी से उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए खड़ा किया जाएगा। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात में इस मामले को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी इस मामले में विचार-विमर्श किया। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं चुनाव आयोग से संबंधित कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाने का दिखावा कर रही है।

खंडवा लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। मिशन-4 की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दोनों पार्टियों ने चौसर बिछानी शुरु कर दी है। भाजपा ने जहां अपने मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौगातों की बौछार शुरु कर दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस अंदर ही अंदर रणनीति बना रही है। कांग्रेस दमोह उपचुनाव की तर्ज पर चारों उपचुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है।

मिशन-4 की कसौटी

मप्र में होने वाले उपचुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस इन उपचुनावों पर है। मिशन-4 की कसौटी पर अपने आपको कसने के लिए दोनों पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों पार्टियां उपचुनाव के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गई हैं। इसलिए माना जा रहा है कि ये उपचुनाव विगत वर्ष हुए 28 सीटों के उपचुनाव से भी रोचक होंगे। कांग्रेस जहां दमोह उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, वहीं भाजपा उस हार से सबक लेकर जीत की रणनीति पर काम कर रही है।

भाजपा ने जहां उपचुनाव वाले क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सौगातों का पिटारा लेकर मैदान में उतर चुके हैं। उधर, कांग्रेस भाजपा की एक-एक चाल पर नजर रखे हुए है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों से बेहाल जनता उपचुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार है। वे कहते हैं कि कांग्रेस जनता के लिए, जनता के साथ चुनाव लड़ेगी। हमें उम्मीद है कि दमोह की तरह कांग्रेस चारों सीटों पर भाजपा को मात देगी।

सत्ता-संगठन जिलों में एक साथ करेंगे काम

मिशन 2023-24 के लिए सत्ता और संगठन को एकसाथ मिलकर काम करना होगा और जहां-जहां भाजपा कमजोर है, वहां विशेष ध्यान देना होगा। इसको लेकर जिले के प्रभारी मंत्री और संगठन की ओर से बनाए गए प्रभारी के साथ-साथ जिलाध्यक्षों की तीन सदस्यीय समिति काम करेगी। वहीं प्रभारी मंत्री को अपने प्रभार वाले जिलों में दो दिन कम से कम रुकना होगा और कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करनी होगी। भाजपा मिशन 2023 और 24 के लिए अपना रोडमैप अभी से तैयार कर रही है। इसके लिए पार्टी के रणनीतिकारों ने यह रणनीति बनाई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा में समन्वय की कमी महसूस की जा रही है। इसको देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब सत्ता और संगठन जिलों में भी एक साथ मिलकर काम करेंगे।

मप्र का भाजपा संगठन पार्टी में देश का सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। इसके बाद भी संगठन को और अधिक मजबूती देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पार्टी के जनाधार को भी और बढ़ाया जा सके। नई रणनीति के तहत प्रदेश में हर बूथ पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिससे कि हर बूथ पर पार्टी को कम से कम 50 फीसदी मत मिल सकें। दरअसल पार्टी के दोनों केंद्रीय नेता मानते हैं कि सरकार बनने के साथ ही पार्टी के वोट प्रतिशत में भी वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए पार्टी ने युवा कार्यकर्ताओं को बूथ का जिम्मा देकर उन्हें और अधिक सक्रिय करने की रणनीति तैयार की है।

मप्र की सता और संगठन में होने वाली नई नियुक्तियों के नामों को तय करने का काम भी अब प्रदेश के चारों नेताओं द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा। इसके बाद उन पर सहमति की अंतिम मुहर शिवप्रकाश और मुरलीधर राव द्वारा लगाई जाएगी। यह निर्णय करने के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वह है इस तरह के मामलों में संभागीय संगठन मंत्रियों की बढ़ती रुचि। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि अब भाजपा प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के कामों का भी मूल्यांकन किया जाए। इससे उनके कामकाज में सुधार होने के साथ ही जवाबदेही तय की जा सकेगी। इसी तरह का

मूल्यांकन पार्टी में मंडल स्तर तक करने की योजना तैयार की गई है। इससे संगठन को अपने हर नेता की कार्यक्षमता का पता चल सकेगा। दरअसल, भाजपा की यह तैयारी उपचुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है। उधर, कांग्रेस भी उपचुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उपचुनाव में दोनों पार्टियों का पूरा फोकस खंडवा लोकसभा उपचुनाव पर है। अघोषित तौर पर खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तैयारियों का आगाज हो गया है। कांग्रेस की ओर से अरुण यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है, वहीं भाजपा में अंदर ही अंदर रस्साकशी शुरू हो गई है। भाजपा यहां से दमदार उम्मीदवार के नाम पर विचार कर रही है। यहां पर टिकट के लिए मुख्य मुकाबला पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, वरिष्ठ नेता कृष्णमुरारी मोघे और दिवंगत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष चौहान के बीच है। वहीं पार्टी किसी नए चेहरे की तलाश में है। इसके लिए पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है।

हालांकि भाजपा सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हर्ष चौहान को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में हैं। मोघे जैसे **कद्दावर नेता संघ के भरोसे** यहां से दावेदारी कर रहे हैं। मोघे पहले खरगोन से सांसद रह चुके हैं, इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। चिटनीस दिल्ली में हाईकमान से अपने संबंधों के आधार पर टिकट मिलने का दावा कर रही हैं। चिटनीस की बुरहानपुर, नेपानगर में अच्छी पैठ है और वे नंदू भैया के दिवंगत होने के बाद से सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रही हैं।

मप्र में खंडवा लोकसभा सीट के अलावा तीन विधानसभा सीटों जोबट (अलीराजपुर), पृथ्वीपुर (निवाड़ी) और रैगांव (सतना) पर उपचुनाव होना है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस खंडवा पर है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में जहां चिटनीस, मोघे और हर्ष अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, वहीं हरसूद विधायक और मंत्री विजय शाह भी लोकसभा उपचुनाव में पत्नी पूर्व महापौर भावना शाह को टिकट दिलाने के प्रयास में जुटे हैं जबकि लोकसभा उपचुनाव में टिकट मांगने वालों में भाजपा से टिकट पर विभिन्न चुनाव में हारे व संगठन में सक्रिय नेताओं की लंबी लिस्ट है। इधर पार्टी जिन नए चेहरों पर विचार कर रही है, उनमें बुरहानपुर निवासी ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम सामने आया है। पिछड़ा वर्ग के पाटिल जिला पंचायत खंडवा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके अलावा राजपाल सिंह तोमर की भी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। ये जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। कृषि मंडी के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम संगठन के पास आया है। दरअसल, यहां कांग्रेस से पूर्व सांसद अरुण यादव की दावेदारी काफी मजबूत है। भाजपा इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कोई मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहती है।

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव की खंडवा लोकसभा में होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। पार्टी ने उन्हें इसके संकेत दे दिए हैं। इसके साथ ही उनके अनुसार क्षेत्र के संगठन में नियुक्तियां शुरू कर दी गई है। जल्द ही निचले स्तर पर भी उनके समर्थकों को नियुक्तियां दिए जाने की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो खंडवा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर सर्वे हो चुका है। इसमें अरुण यादव का नाम उभरकर सामने आया है। इस सर्वे के बाद यादव को यहां से उम्मीदवार बनाए जाने का पार्टी के आला नेताओं ने मन बना लिया है। इस संबंध में कुछ दिनों पूर्व अरुण यादव की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद अब अरुण यादव को खंडवा उपचुनाव लड़ने को लेकर हरी झंडी मिल गई है।

हाल ही में अरुण यादव के समर्थक असदउद्दीन को खंडवा लोकसभा के लिए सोशल मीडिया विभाग का प्रभारी बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि अब अरुण यादव के अनुसार ही मंडलम और सेक्टर में कुछ पदाधिकारियों की भी नियुक्तियां की जाना है। यादव ने भी प्रदेशभर से अपने समर्थकों को क्षेत्र में सक्रिय करने की तैयारी कर ली है। अब देखना यह है कि उपचुनाव में किसकी रणनीति कारगर होती है।

● **कुमार राजेन्द्र**

'बीएसपी' को मुद्दा बना सरकार पर होगा वार

मप्र में भले अभी चुनाव न हों, 4 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान न हुआ हो, लेकिन चुनावी मुद्दों की गर्माहट अभी से महसूस होने लगी है। 2003 के विधानसभा चुनाव में जिस 'बीएसपी' के मुद्दों के सहारे भाजपा कांग्रेस को घेरकर सत्ता तक पहुंची थी, अब उन्हीं मुद्दों के सहारे कांग्रेस ने भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 2003 में भाजपा ने 'बीएसपी' यानी बिजली, सड़क और पानी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। इस साल प्रदेश में हुई बारिश के बाद खस्ताहाल सड़कें एक बार फिर मुद्दा बन गई हैं। इनके अलावा ग्वालियर-चंबल में बाढ़ और बारिश से पुल, पुलियों के बह जाने, बिजली के भारी भरकम बिल और बढ़ती महंगाई को कांग्रेस ने जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर पार्टी से जुड़े संगठन भी सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं कि प्रदेश में 2003 से ज्यादा हालात खराब हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, बिजली के भारी-भरकम बिल और सड़कों में हुए गड्ढों ने सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है। इधर, विपक्ष के तेवरों को लेकर भाजपा ने भी जवाबी हमलों की तैयारी तेज कर दी है। भाजपा ने लोगों से जुड़ने के लिए पूरे एक साल के कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के 2003 से पहले के शासन में बिजली और सड़क के हालातों और अब के हालातों के तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि खराब सड़कों को तत्काल सुधारा जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेस 18 साल में बूढ़ी हो गई है और अब उसे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस सरकार की तुलना में आज प्रदेश के स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और एमडीआर रोड बेहतर हालत में हैं। परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों के खराब होने पर उनके सुधारने का प्रावधान है।

मप्र में सत्ता और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों नेताओं ने विगत दिनों मप्र में विभिन्न स्रोतों से फीडबैक लेकर एक नीति तैयार की है, जिसके आधार पर सत्ता और संगठन काम करेगा। इस नीति के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को और मजबूती मिलेगी। यानी प्रदेश में सत्ता और संगठन का नीति निर्धारण शिवप्रकाश, मुरलीधर राव, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा मिलकर करेंगे। दरअसल, पिछले महीनों में शिवप्रकाश और मुरलीधर राव को जो फीडबैक मिला है, उसके अनुसार प्रदेश में शिवराज और वीडी शर्मा को कमजोर करने के कई प्रयास हुए हैं। जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इन दोनों नेताओं की अच्छी पैठ है। इस पैठ को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी की नई नीति के अनुसार अब प्रदेश के हर छोटे-बड़े नेता की भूमिका तय होगी। सूत्रों के अनुसार जहां शिवराज सिंह चौहान सत्ता और वीडी शर्मा संगठन के सर्वेसर्वा बने रहेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता सत्ता और **संगठन के सारथी** की भूमिका में रहेंगे। शिवप्रकाश और मुरलीधर की कोशिश है कि मप्र में सत्ता और संगठन का सामंजस्य ऐसा हो जिसे देशभर में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। भाजपा में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की एक डायरी में प्रदेश संगठन और सत्ता की सारी हकीकत है। सूत्रों का कहना है कि विगत दिनों जब शिवप्रकाश मप्र के दौरे पर थे तो उन्होंने एक अनजान शख्स की तरह भाजपा कार्यालय में घूम-घूमकर हर एक गतिविधि का जायजा लिया और उसे डायरी में नोट किया। उसके बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में आने वाले हर नेता की चर्चा सुनी और उसे भी सूचीबद्ध किया। यही नहीं प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के कक्ष में भी बैठकर उन्होंने एक अनजान व्यक्ति की तरह प्रदेशभर से आए हुए लोगों की बातें सुनीं और उन्हें डायरी में दर्ज किया।

2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा अब इस कोशिश में लगी हुई है कि प्रदेश में फिरसे ऐसी स्थिति निर्मित न हो। इसलिए भाजपा के रणनीतिकारों ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं को सत्ता और संगठन का मुख्य चेहरा बनाने का निर्णय लिया है। यानी आगामी दिनों में इन्हीं चेहरों को आगे करके सत्ता और संगठन की नीति और रणनीति तैयार होगी। सूत्रों का कहना है कि सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने केंद्रीय नेतृत्व को नई रणनीति का खाका भेज दिया है।

नई रणनीति

काम का होगा मूल्यांकन

नई नीति के अनुसार अब भाजपा प्रदेश इकाई जल्द ही अपने पदाधिकारियों के काम का मूल्यांकन शुरू करेगी। पार्टी नेतृत्व को लगता है कि इससे कामकाज में सुधार होगा और कैडर के बीच जवाबदेही तय होगी। प्रदेश संगठन से लेकर ब्लॉक तक मूल्यांकन किया जाएगा। इस अभ्यास से पार्टी को प्रत्येक नेता की कार्य क्षमता को जानने में मदद मिलेगी। यह पूरी कवायद जवाबदेही तय करने के लिए की जाएगी जो नीचे से ऊपर तक पार्टी की स्थिति के साथ आती है। मूल्यांकन के आधार पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा।

मप्र की सत्ता और संगठन की टोह लेने के बाद शिवप्रकाश और मुरलीधर राव ने जो नीति बनाई है उसके अनुसार अब सांगठनिक और राजनीतिक नियुक्तियों का फैसला चौकड़ी करेगी। यानी मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी आपसी समन्वय से तय करेंगे कि किसे नियुक्त किया जाए। सूत्रों का कहना है कि विगत दिनों शिवप्रकाश जब भाजपा कार्यालय आए थे तो उन्होंने यह पाया कि संभागीय संगठन मंत्री भी नियुक्तियों की सिफारिश लेकर पहुंच रहे हैं। वैसे तो मप्र का भाजपा संगठन देश में सबसे मजबूत स्थिति में है। फिर भी संगठन को और मजबूत करने की कवायद शुरू की जाएगी। साथ ही प्रदेश में भाजपा के जनाधार को और मजबूत किया जाएगा। नई नीति के तहत प्रदेश में हर बूथ पर 51 से 52 फीसदी वोट का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी का मानना है कि केवल सरकार बनाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि वोट का प्रतिशत भी बढ़ाना होगा। इसलिए अब हर बूथ पर अधिक से अधिक यूथ को तैनात किया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी ने आलाकमान को रिपोर्ट दी है कि 2023 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाए। यही कारण है कि इन दोनों नेताओं ने प्रदेश में सत्ता और संगठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। इन दिनों खुद प्रदेश अध्यक्ष उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा कार्यालय से लेकर संगठन तक में अंगद के पांव बने नेता यानी दशकों से विराजमान नेताओं को बाहर करने की तैयारी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि अपनी भोपाल यात्रा के दौरान शिवप्रकाश ने पाया कि मठाधीश बने ये नेता अन्य नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यही नहीं इनके कारण संगठन की गतिविधियों को गति नहीं मिल पा रही है। इस कारण अब इन नेताओं को हटाकर तेज तर्रार और युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने भाजपा कार्यालय में चल रहे हर एक विभाग का बारीकी से निरीक्षण किया है। चरैवैति, कमल संदेश कार्यालय का भी जायजा लिया है और भाजपा कार्यालय में हुए 30-35 करोड़ के घोटाले को भी संज्ञान में लिया है।

● **अरविंद नारद**

संक्रमण के बीच स्कूल चले हम

कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच 1 सितंबर से मप्र में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल भी खोले जा रहे हैं। स्कूल खोलना सरकार की मजबूरी भी बन गया है। देखना यह है कि सरकार का यह कदम कितना कारगर होता है।

अभी कई बड़े और छोटे देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। मौत के इस खतरनाक वायरस ने हर जगह दहशत फैला दी है। जबकि दुनिया भर में लाखों लोग कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित हैं। और दूसरी तरफ, मप्र सहित देश के कई राज्यों में स्कूल या तो खोल दिए गए या खुलने जा रहे हैं। संक्रमण के बीच बच्चों का स्कूल जाना किसी खतरे से कम नहीं है। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट स्कूलों को खोलने की एक अलग चेतावनी है।

मप्र में महीनों बाद 1 सितंबर से सभी निजी व सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया था। जबकि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले से चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों को भी निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना होगा। कक्षा में छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत ही रखनी होगी। साथ ही किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन नहीं होगा। न असेंबली होगी और न ही खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। फिलहाल पालक बच्चों को भेजने को लेकर पसोपेश में हैं। वहीं स्कूल संचालक भी पहले दिन कितने बच्चे स्कूल आते हैं, उसको लेकर असमंजस में हैं। तीसरी लहर को देखते हुए पालक स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित भी हैं। इस बीच, अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ की रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए, तो भारत में स्कूल खोलना खतरनाक हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के अनुसार, भारत में तीन में से केवल एक स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में भारत के स्कूलों में कोविड-19 महामारी की स्थिति खतरनाक हो सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि पानी की अनुपस्थिति में बार-बार हाथ धोने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हाथ धोने की सुविधा पहले की तुलना में तेज दर से बढ़ी है, लेकिन देश के कई इलाके अभी भी उन इलाकों में हैं जहां स्कूलों में साबुन की कमी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि विश्व स्तर पर 469 मिलियन से अधिक बच्चों के पास 2019 में कोई स्कूल स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। इन बच्चों में से 244 मिलियन अफ्रीका से हैं। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 में लगभग 60 देशों में स्वास्थ्य और मानवीय संकटों का सबसे अधिक जोखिम है। आधे से अधिक देशों में बुनियादी स्वच्छता सेवाओं का भी अभाव है। रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया है कि ज्यादातर स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। ऐसे में भारत में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच में स्कूल खोलना खतरनाक साबित हो सकता है। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि हमें बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता बनाना चाहिए, लेकिन बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए।

कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए स्कूलों को न खोलना भी कमोबेश उतना ही खतरनाक है जितना कि उनको खोलना। स्कूलों के न खुलने से न केवल परिवार के भीतर का वातावरण बिगड़ रहा है बल्कि बच्चों की घरेलू कामकाज में भागीदारी भी बढ़ रही है। इसके चलते वे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। यह बात विनय पी सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, युवा, बच्चों और खेल पर गठित संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल से ज्यादा समय से स्कूलों की बंदी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाला है। बड़े बच्चों का घर की चारदीवारी के भीतर लगातार रहना माता-पिता के साथ उनके रिश्तों पर असर डाल रहा है। माता-पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि खासकर लड़कियों की कम उम्र में शादी हो रही है या उन पर घर के कामकाज की जिम्मेदारी बढ़ रही है। इससे लड़कियों की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट रही है या फिर वे पढ़ाई में कमजोर हो रही हैं। आमतौर पर ऐसा निम्न मध्यमवर्गीय और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में देखने को मिल रहा है। इसलिए स्कूलों को खोलने के लिए होने वाली चर्चा में इन स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। अब देखना यह है कि सरकार द्वारा स्कूल तो खुलवाए जा रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन का कितना पालन होता है। अगर स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है।

● **जितेंद्र तिवारी**

प्रदेश में 18 लाख बच्चों तक नहीं पहुंचा शिक्षा का उजियारा

उधर, स्कूल शिक्षा विभाग ने इस सत्र में शाला त्यागी और अप्रवेशित बच्चों का सर्वे कराया। इसमें पांच से आठ साल के 22 लाख 62 हजार बच्चे स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए चुने गए। इनमें से अब तक सिर्फ चार लाख 17 हजार बच्चों का स्कूल में प्रवेश हुआ। यानी करीब 18 लाख बच्चे स्कूल जाने की उम्र में शिक्षा से वंचित हैं। यह खुलासा विभाग द्वारा शिक्षा पोर्टल पर जारी किए गए आंकड़ों से हुआ है। इनमें करीब एक लाख 83 हजार ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता कोरोनाकाल के दौरान दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। एक लाख 38 हजार ऐसे बच्चे हैं, जिनका अब तक स्कूल में दाखिला ही नहीं हुआ है। करीब 22 हजार से अधिक 18 वर्ष से अधिक उम्र के पाए गए, जिन्होंने बहुत पहले ही स्कूल जाना छोड़ दिया है। इस सर्वे के आधार पर विभाग ने अधिकारियों को लक्षित बच्चों के घर-घर संपर्क कर स्कूलों में प्रवेश कराने की जिम्मेदारी दी है। बता, दें कि राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षकों को अप्रवेशित व शाला त्यागी बच्चों के सर्वे कार्य में लगाया था, जिसमें शिक्षकों को बच्चों के घर-घर जाकर संपर्क करना था और सेल्फी अपलोड करना था।

सोम का साम्राज्य खत्म!

कभी प्रदेश में रसूख का साम्राज्य रही सोम डिस्टलरी आज अपने ही फर्जीवाड़े के कारण बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है। अगर यह कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सोम का साम्राज्य अब खत्म हो चला है। अभी हाल ही में आबकारी आयुक्त ने सोम डिस्टलरीज, रायसेन द्वारा डिस्टलरी में स्प्रिट के भंडारण के लिए सक्षम अनुमति बिना टंकी के निर्माण पर कंपनी का नवीनीकरण आवेदन निरस्त कर दिया है। साथ ही डिस्टलरी को वित्तीय वर्ष के लिए कार्य अनुमति को भी निरस्त कर दिया गया है। कंपनी के विरूद्ध यह कार्रवाई डिस्टलरी के जीरो डिस्चार्ज बाबत आधुनिकीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान टंकी निर्माण की जानकारी मिलने पर जारी किए गए नोटिस का समाधानकारक उत्तर न देने पर की गई है।

गौरतलब है कि प्रदेश में अपने राजनीतिक पहुंच के आधार पर सोम ने दशकों तक शराब के कारोबार में अपना रसूख कायम रखा। लेकिन अब आबकारी विभाग ने कुख्यात शराब तथा बीयर निर्माता समूह सोम डिस्टलरीज के सेहतगंज स्थित प्लांट में शराब के उत्पादन पर रोक लगा दी है। यह समूह अब शराब का उत्पादन नहीं कर सकेगा। उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सोम समूह ने हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। वह ऐसा पहले भी कई बार सफलता हासिल कर चुका है।

सोम पर आरोप है कि उसने रायसेन के सेहतगंज में बनी अपनी आसवनी में नियमों का उल्लंघन कर 19 टैंक बना दिए। इन टैंकों में देशी शराब बनाने के लिए स्प्रिट का भंडारण किया जाता है। जबकि इस गड़बड़ी के बीच भी वर्ष 2016 से लेकर अब तक सोम का लाइसेंस लगातार रिन्यू किया जाता रहा। इस महाभूल के पीछे राज्य सरकार के अफसर गजब हास्यास्पद दलील दे रहे हैं। लाइसेंस निरस्त के लिए जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में सोम ने लगातार रिन्यू वाली प्रक्रिया का अपने पक्ष में हवाला दिया था। इस पर आबकारी विभाग ने लाइसेंस निरस्त करने वाले नोटिस में लिखा है, 'इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि 28.09.2020 को इकाई की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के उपरांत प्रकाश में आए नए तथ्यों के आधार पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण किए जाने के उपरांत यह कार्यवाही प्रचलित की गई है।' तो क्या जिन अफसरों में लाइसेंस रिन्यू करने से पहले सोम की इस डिस्टलरी का निरीक्षण किया होगा, वे इस बात को देख ही नहीं सके कि उस कारखाने के परिसर में ही एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 19 टैंक धड़ल्ले से काम कर रहे हैं? जब नियम साफ कहते हैं कि किसी आसवनी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए आबकारी आयुक्त की पूर्व मंजूरी जरूरी है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस मंजूरी के न होने के बावजूद टैंक बनाने वाले सोम ग्रुप का लाइसेंस एक बार फिर रिन्यू कर दिया गया?

दरअसल सोम पर सरकारी मेहरबानियों का सिलसिला पुराना है। यहां भी वही बात साफ दिख रही है। नियम स्पष्ट कहते हैं कि हर साल लाइसेंस को रिन्यू करने से पहले आबकारी विभाग द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है तथा टैंक का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो फिर 2021 के लिए भी सोम का लाइसेंस रिन्यू करने के पहले 'सूक्ष्म निरीक्षण' तथा 'टैंक के रिकॉर्ड' वाली प्रक्रियाओं को विभाग का संबंधित स्टाफ भूल गया था? मामला जरूर शराब वाला है, लेकिन स्थिति 'पूरे कुएं में भांग घुली' वाली ही है। आबकारी विभाग ने सोम को दिए आदेश में स्वयं लिखा है कि विभाग के प्रभारी अधिकारी ने टैंकों की गेजिंग अपने ही विवेक से करवा दी और इस संबंध में उसने आबकारी आयुक्त से कोई अनुमति नहीं ली।

इसी तरह वर्ष 2018-19 में इस डिस्टलरी के लाइसेंस के नवीनीकरण से पहले भी जिला आबकारी अधिकारी ने यहां के निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार की। इसमें उसने नियम विरुद्ध टैंक बनाए जाने की बात को ही गोलमोल कर दिया। सोम को दिए नोटिस में विभाग लिखता है, 'जिला आबकारी अधिकारी, सोम आसवनी के प्रतिवेदनों में आसवनी में नवीन निर्माण कार्य किए जाने संक्षिप्त औपचारिक उल्लेख मात्र किया गया है, जिसमें स्टोरेज-रिसीवर टैंकों की स्पष्ट जानकारी नहीं है।' एक सवाल यह भी उठता है कि यदि सोम ने अपने कागजों में इन टैंकों को 'एल्कोहल स्टोरेज सेक्शन' बताकर आबकारी विभाग की आंखों में धूल झोंकी तो वो अफसर क्या कर रहे थे, जिन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का मुआयना किया और जिनकी ओके रिपोर्ट सोम का लाइसेंस रिन्यू करने का प्रमुख आधार बनी?

यह सब घनघोर लापरवाहियां उस सोम समूह के मामले में की गईं, जो अपने गलत कामों के लिए हमेशा से कुख्यात है। इसलिए यह शक बेमानी नहीं लगता कि सोम ने यदि गड़बड़ी की है तो उसे इन गड़बड़ियों के लिए आबकारी विभाग के अंदर से ही संरक्षण भी मिलता रहा है। लेकिन लगता है अब सोम के दिन लद गए हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

आबकारी विभाग में गड़बड़ियों को रोकने के लिए कई प्रयोग

आबकारी विभाग भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के लिए जाना जाता है, लेकिन जबसे राजीव चंद्र दुबे विभाग के आयुक्त बने हैं, वहां गड़बड़ियों को रोकने के लिए कई प्रयोग किए गए। सबसे

क्रांतिकारी प्रयोग है शराब खरीदी पर बिल मिलना। आबकारी एक्ट के 106 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब मप्र में 1 सितंबर से शराब दुकानों से शराब की बोतल खरीदने पर बिल मिलेगा। वहीं प्रदेश की सारी डिस्टलरी में ई-लॉक की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ई-परमिट दिया जा रहा है। यानी हाथ से लिखने की प्रथा बंद कर दी गई है। वहीं शराब परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगा ही है, सरकार की आय में बढ़ोत्तरी के द्वार भी खुले हैं। आबकारी विभाग में 1 साल 3 माह में आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने वह कर दिखाया है जिसके बारे में कभी किसी आयुक्त ने सोचा भी नहीं। दुबे के इस कदम से ठेकेदार और डिस्टलरी वाले काफी नाराज हैं। क्योंकि अपने पैसे के बलबूते वे विभाग में जो करते आ रहे हैं, वे इस बार वैसा नहीं कर पा रहे हैं।

- 5341 करोड़ का घाटा पूरा करने के लिए ईमानदार उपभोक्ताओं से वसूली की तैयारी
- बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 336.6 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली खरीदी, लेकिन इसका एक रुपए नहीं मिला

बिजली कंपनियों का खेल

मप्र देश में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। लेकिन विसंगति यह है कि इसके बावजूद यहां के लोगों को देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है। इसकी वजह यह है कि बिजली कंपनियां हर साल घाटा दिखाकर बिजली की दरें बढ़वा लेती हैं। कंपनियों के इस खेल का भार ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ता है। दरअसल, मप्र में बिजली खरीदी और बिजली चोरी दो बड़ी वजह है जिसके कारण यहां उपभोक्ताओं को महंगी बिजली पड़ती है।

नीति आयोग ने सिफारिश की है कि मप्र में 36 प्रतिशत से अधिक बिजली चोरी हो रही है, जो उप्र, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान की तुलना में ज्यादा है। मप्र में पुराने पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली की खरीदी की जा रही है, जो संचालन लागत की 77 प्रतिशत है। वर्तमान में मप्र की विद्युत वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 1515 करोड़ रुपए बकाया है। बिजली कंपनियों के इस खेल का खामियाजा ईमानदार उपभोक्ता को उठाना पड़ रहा है। अनाप-शनाप बिजली खरीदी और बिजली चोरी से 5341 करोड़ रुपए के घाटे को ईमानदार उपभोक्ताओं से वसूलने की तैयारी की जा रही है।

पावर मैनेजमेंट कंपनी और वितरण कंपनियों ने 2019-20 में 5341.13 करोड़ का घाटा बताया है। इसकी भरपाई उपभोक्ताओं से अगले टैरिफ आदेश में वसूलने की एक सत्यापन याचिका मप्र विद्युत नियामक आयोग में पेश की है। आयोग ने इस पर 20 अगस्त तक आपत्तियां आमंत्रित की थीं। 24 अगस्त को जनसुनवाई में आपत्तियों पर सुनवाई भी हुई। हैरानी की बात ये है कि सत्यापन याचिका में बिजली कंपनियों ने घाटे के दो मुख्य वजह पहला प्रदेश में सरप्लस बिजली और दूसरा बिजली चोरी बताया है। इसका भार आम उपभोक्ताओं को वहन करने को कहा है। टैरिफ आदेश 2019-20 में कंपनियों ने बिजली खरीदी पर 26003.63 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था, पर कंपनियों ने इसकी अपेक्षा बिजली खरीदी पर 32231.42 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब अनुमान से 6227.79 करोड़ रुपए की अधिक बिजली खरीदी गई।

विद्युत मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने इस सत्यापन याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी आपत्ति में कहा कि अनाप-शनाप बिजली अनुबंध की समीक्षा और बिजली चोरी रोकने में नाकामयाब बिजली कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी बजाय ईमानदार उपभोक्ता से राशि के वसूली का प्रयास, अन्यायपूर्वक व अस्वीकृत करने योग्य है। बिजली हानि रोकने में सिर्फ पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रयास किए हैं। यही कारण रहा कि आयोग द्वारा निर्धारित मात्र से भी कम बिजली हानि हुई है।

बिजली कंपनियों की ओर से हर वित्तीय वर्ष के लिए पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से अनुमान आधारित टैरिफ याचिका नियामक आयोग में पेश की जाती है। पर उस वित्तीय वर्ष में वास्तविक व्यय आंकलित व्यय से अधिक होने पर उसकी भरपाई के लिए कंपनियां सत्यापन याचिका पेश करती हैं। इस सत्यापन याचिका में बताती हैं कि अमुक कारण से उनका खर्च आंकलन से अधिक हुआ। यदि आयोग ने उनकी सत्यापन याचिका स्वीकार कर ली तो इसकी वसूली उपभोक्ताओं से अगले टैरिफ याचिका में बिजली की दरें बढ़ाकर की जाती हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

अधिक बिजली हो गई चोरी

बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 336.6 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली खरीदी गई, लेकिन इसका एक रुपया नहीं मिला। कंपनी के मुताबिक सारी बिजली चोरी चली गई। प्रदेश में 13 प्रतिशत से अधिक बिजली चोरी चली गई, जबकि बिजली चोरी रोकने की जवाबदारी बिजली कंपनियों की है। प्लाट से उपभोक्ताओं के घरों तक बिजली पहुंचने में तकनीकि हानि होती है, पर इसकी मात्रा नियमानुसार 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयोग ने कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से इस स्तर पर आने की छूट दे रखी है। बावजूद कंपनियों के क्षेत्र में इस छूट से भी अधिक बिजली की हानि दर्शायी जाती है। बड़ी चालाकी से बिजली चोरी को इसी हानि में दर्शा दिया जाता है। उधर, सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसे देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय में लागू किया जाएगा। प्रदेश के सभी निकायों में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की समय सीमा दिसंबर 2023 तय की गई है। इसके अंतर्गत सभी शासकीय विभाग, 10 किलोवाट से अधिक खपत वाले एलटी लाइन के उपभोक्ता और सभी व्यावसायिक व औद्योगिक संस्थानों के मीटर प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बदले जाएंगे। करीब 23 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बदलने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक है। फिलहाल किसानों को प्रीपेड मीटर के दायरे से बाहर रखा जा रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में 100 प्रतिशत प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बढ़ते सियासी कद और स्टारडम के चलते अब मूल भाजपा कैडर के नेता भी उनसे जुड़ने लगे हैं। लिहाजा भाजपा में सिंधिया खेमा नया आकार ले रहा है। इस बार केवल कांग्रेस से भाजपा में आए नेता ही नहीं, बल्कि मूल भाजपाई भी इस खेमे का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें भाजपा में हाशिए पर पड़े नेताओं के अलावा बड़े नेताओं के गुट के भाजपाई भी सिंधिया में अपना उज्जवल भविष्य तलाश रहे हैं। कोई दबे पैर सिंधिया खेमे से एंट्री के रास्ते देख रहा है तो कोई जैसे-तैसे सिंधिया तक पहुंच बनाकर करीबी बनने की जुगत में है।

सिंधियामय हो रही मप्र भाजपा

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक पैतरेबाजी कब क्या गुल खिला दे इसका आंकलन कोई नहीं कर सकता है। मप्र की राजनीति में भी इन दिनों नया गुल खिलाया जा रहा है। यानी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को महिमा मंडित किया जा रहा है। इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि अब मप्र भाजपा सिंधियामय होने लगी है। पार्टी का हर नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसे सिंधिया का सानिध्य मिल जाए। यह नजारा सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा में भी देखा गया। केंद्रीय नेतृत्व ने अपने नवागत मंत्रियों की जनआशीर्वाद यात्राएं धूमधाम से निकलवाई है, जिसके चलते नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन भी प्रदेश में किया गया। 584 किलोमीटर की इस यात्रा का इंदौर में समापन हुआ। राजनीति के जानकारों का कहना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा के जरिए रिहर्सल भी हो गई और आगामी विधानसभा चुनाव के चेहरे सिंधिया हो सकते हैं।

मप्र में अच्छी-भली बनी कांग्रेस की सरकार को गिराने भाजपा की सरकार बनाने का पूरा सेहरा सिंधिया के माथे ही बंधा और इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पूरा वरदहस्त उन पर रहा। इसके चलते सिंधिया समर्थकों को जहां उपचुनावों में टिकट मिली, वहीं अब सत्ता, संगठन से लेकर निगम, मंडल, प्राधिकरण में भी प्रवेश मिलेगा। इसका सबूत है जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता। यह पहला मौका है जब भाजपा के सारे गुटों ने एकजुटता दिखाई और बड़े नेता-पदाधिकारियों से लेकर खाटी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरकर स्वागत-सत्कार में पीछे नहीं रहा। सिंधिया खुद अपने इस स्वागत समारोह से अभिभूत नजर आए और उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लंबे समय से चलती रही है कि सिंधिया को आगामी चुनावों की बागडोर सौंपी जा सकती है और वे मप्र के अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। दरअसल, सभी गुटों में उनकी स्वीकार्यता भी है और पब्लिक फेस तो वे पहले से हैं ही। युवाओं, महिलाओं से लेकर शहरी और ग्रामीण जनता में भी उनकी अच्छी पैठ है।

महाराज की छवि से निकलने लगे बाहर

ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब उनकी आलोचना इस बात को लेकर होती रही कि वे महाराज की छवि से बाहर नहीं आ पाते और सबसे मेल-मुलाकात भी नहीं करते। लेकिन भाजपा में आने के बाद उन्होंने यह मिथक तोड़ा और जब भी इंदौर आए वे हर विधायक से लेकर पदाधिकारियों के घर मिलने गए और कल भी उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा कि महाराज होना मेरा अतीत था, अब मैं जनता का सेवक हूं। इस जनआशीर्वाद यात्रा की खास बात यह है कि भाजपा में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहला अनुभव है, जब वह अकेले निकले हैं और उन्हें अपने समर्थकों के अलावा भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है। ये दृश्य संकेत करते हैं कि भाजपा में सिंधिया का सियासी कद लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में वह पार्टी का प्रमुख चेहरा होंगे। सिंधिया की बड़ी सफलता पार्टी में उनकी ऐसी स्वीकार्यता है, जो पहले शायद ही किसी बाहरी नेता को मिली हो।

पार्टी नेतृत्व को यह स्पष्ट लगता है कि 2023 का विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता। क्योंकि पिछले चुनावों में भाजपा को इसीलिए हार का मुंह देखना पड़ा और सत्ता से भी बाहर हो गई और अभी उपचुनावों में भी पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं गुटबाजी भी पहले की तुलना में बढ़ गई। इसके चलते संभव है कि सिंधिया को ही विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए और जनआशीर्वाद यात्रा उसकी रिहर्सल है, जिसमें किसी तरह की गुटबाजी भी नजर नहीं आई, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की मंशा को प्रदेश भाजपा के सभी दिग्गजों ने महसूस कर लिया और यही संदेश अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया, जिसके चलते यात्रा अत्यंत साबित हुई।

जनआशीर्वाद यात्रा के बहाने अभी तक जो एक अदृश्य दूरी पुराने कांग्रेसी और भाजपाइयों के बीच थी वह भी लगभग खत्म हो गई। दरअसल, सिंधिया के साथ उनके समर्थक भी भाजपा में आ गए, जिनमें इंदौर के कई नेताओं के साथ उनके कार्यकर्ता भी शामिल रहे। यह पहला मौका था जब भाजपा में शामिल हुए पुराने कांग्रेसी और लंबे समय से पार्टी में मौजूद नेताओं-कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल

नजर आया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र आमतौर पर ग्वालियर-चंबल माना जाता रहा है, लेकिन जनआशीर्वाद यात्रा को मालवा-निमाड़ में मिल रहे जनसमर्थन से स्पष्ट संकेत है कि सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। इस यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ रहा है, वह उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर तो मजबूत कर ही रहा है, साथ ही भाजपा को भी एक ऐसा नेता देने की शुरुआत है, जिसे कांग्रेस के खिलाफ पूरे प्रदेश में कहीं भी भेजकर चुनावी मुकाबले को जीत में बदलने की कोशिश की जा सकती है। आमतौर पर भाजपा में आए बाहरी नेता को कार्यकर्ताओं का इतना जबरदस्त समर्थन मिलते नहीं देखा गया है, जितना सिंधिया को मिल रहा है।

सिंधिया को कांग्रेस के मुकाबले उतारने के खास मायने हैं, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस का प्रमुख चेहरा थे। वे कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी थे। अब वही कांग्रेस के खिलाफ मैदान में होंगे, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकें। दरअसल, मालवा-निमाड़ मूल रूप से भाजपा का गढ़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस क्षेत्र से पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का प्रभाव भी इंदौर तक सीमित रहा, लेकिन अब वह भी चुनावी राजनीति से दूर हो चुकी हैं। ऐसे में पहला मौका है जब इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री चौहान या विजयवर्गीय के अलावा किसी अन्य भाजपा नेता को भारी जनसमर्थन मिला। इस यात्रा की खास बात है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता सिंधिया के स्वागत से लेकर कदम-कदम साथ चले, जो इस कयास को बीती बात साबित करता है कि अभी भी पार्टी में सिंधिया और उनके समर्थक नेता घुल-मिल नहीं सके हैं। भाजपा में शामिल होने के समय से ही सिंधिया की मुख्यमंत्री के साथ बेहतर जुगलबंदी रही है, वहीं संघ के पदाधिकारियों से मेल-मुलाकात भी होती रहती है।

ग्वालियर राजघराने से पिता की राजनीतिक विरासत लेकर सियासत के मैदान में उतरे सिंधिया ने मप्र की सत्ता पर खुद के दबदबे को बीते ढाई वर्षों में तीन-तीन बार साबित करके दिखाया है। उन्होंने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनवाने में अहम रोल तो निभाया ही, पिछले

साल मार्च में कांग्रेस से 20 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर भाजपा की सरकार भी बनवा दी। लेकिन, जब उन्होंने कांग्रेस के उन बागी विधायकों में से अधिकतर को उपचुनाव में जितवाकर विधानसभा तक पहुंचाने का दम दिखाया तो राजनीति के धुरंधर भी मान गए कि 50 साल का यह युवा नेता सिर्फ खानदान की बदौलत राजनीति नहीं करता, उसने ग्वालियर-चंबल संभाग में धरातल पर अपना एक जनाधार भी खड़ा किया है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मप्र में भाजपा की सरकार बनवाने में जो योगदान दिया था, उसका पुरस्कार मिलने देर जरूर हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार उन्हें जो रोल दिया है उससे उन्हें वो सम्मान मिल गया है, जिससे वह दिल्ली की राजनीति से लेकर मप्र की सियासत तक में अपनी धाक जमा सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बढ़ते सियासी कद और स्टारडम के चलते अब मूल भाजपा कैडर के नेता भी उनसे जुड़ने लगे हैं। लिहाजा भाजपा में सिंधिया खेमा नया आकार ले रहा है। इस बार केवल कांग्रेस से भाजपा में आए नेता ही नहीं, बल्कि मूल भाजपाई भी इस खेमे का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें भाजपा में हाशिए पर पड़े नेताओं के अलावा बड़े नेताओं के गुट के भाजपाई भी सिंधिया में अपना उज्जवल भविष्य तलाश रहे हैं। कोई दबे पैर सिंधिया खेमे से एंट्री के रास्ते देख रहा है तो कोई जैसे-तैसे सिंधिया तक पहुंच बनाकर करीबी बनने की जुगत में है। मालूम हो कि मप्र भाजपा में ऐसे नेताओं की अच्छी खासी संख्या है जो मौजूदा छत्रपों द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने से नाराज है। इनमें नई टीम में हाशिए पर धकेले जाने से लेकर सत्ता में भागीदारी से चूक गए नेता तक शामिल हैं। इसके अलावा उभरते नेताओं की एक बड़ी युवा टीम भी सिंधिया का साथ पाने के लिए प्रयासरत है।

दरअसल वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा के नेताओं की एक पूरी फौज हाशिए पर धकेल दी गई है। इनमें से कई नेता लगातार नाराज चल रहे हैं, पर सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में सिंधिया खेमे से उम्मीद रखी जा रही है। ग्वालियर-चंबल संभाग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के वो नेता जो खुद को उपेक्षित मान रहे हैं, वे अब सिंधिया की ओर देख रहे हैं। इस खेमे में फिलहाल सबसे ज्यादा टशन की स्थिति है, लेकिन सिंधिया इसमें भी आसान राह बना रहे हैं। आमतौर पर बाहरी नेताओं को भाजपा इतने कम समय में इस कदर न मौका देती है, न कार्यकर्ता स्वीकार कर पाते हैं।

● **सुनील सिंह**

नए सियासी अंदाज ने बढ़ाई उम्मीदें

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा में आने के बाद नए सियासी अंदाज से संतुलन की राजनीति की है। सिंधिया हर क्षेत्र में हर खेमे के क्षत्रपों से घर जाकर मिले। साथ ही छोटे कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंचे। इस अंदाज से दूसरे खेमे के नेताओं के लिए सिंधिया के द्वार खुले होने का अप्रत्यक्ष संदेश मिला है। भाजपा में आने के बाद सबसे बड़े सदस्यता अभियान, भोपाल आने पर भव्य स्वागत और अब जन आशीर्वाद यात्रा में सिंधिया का दबदबा दिखा। तीन केंद्रीय मंत्रियों में सबसे ज्यादा सिंधिया का क्रेज देखा गया। मालवा में सिंधिया की सक्रियता ने गुटीय संतुलन में भी हलचल की है। मालवांचल में भी बड़ी संख्या में मूल भाजपाई सिंधिया से जुड़ने लगे हैं। कई अन्य नेता धीरे-धीरे सिंधिया तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इससे आगामी विधानसभा चुनाव तक सिंधिया खेमे का नया स्वरूप दिखने लगेगा।

10 हजार एकड़ का बनेगा लैंडबैंक

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमते ही प्रदेश में उद्योग-धंधे पटरी पर उतरने लगे हैं। उधर, बड़ी संख्या में देसी और विदेशी निवेशक भी मप्र का रुख करने लगे हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

मप्र को इंडस्ट्रीयल हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए प्रदेश के हर क्षेत्र में लैंड बैंक बनाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक निवेशक यहां उद्योग-धंधे स्थापित कर सकें। मप्र औद्योगिक विकास निगम को लगातार निवेशकों के अच्छे प्रस्ताव मिल रहे हैं। भोपाल, इंदौर, पीथमपुर, रतलाम, उज्जैन, खरगोन, बुरहानपुर से लेकर आसपास के जिलों में भी निगम लगातार नए औद्योगिक बेल्ट विकसित कर रहा है और पीथमपुर में भी सेक्टर-7 में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास कार्य जल्द शुरू होगा। इसके साथ ही भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। 50 कपड़ा और गारमेंट उद्योग भी निवेश के लिए तैयार हैं, जिनके माध्यम से डेढ़ हजार करोड़ से अधिक का निवेश होगा। लिहाजा विकास निगम लगभग 10 हजार एकड़ का लैंडबैंक भी तैयार कर रहा है, ताकि सभी छोटे-बड़े इच्छुक उद्योगों-निवेशकों को जमीनें आवंटित की जा सके।

एमपीएसआईडीसी के कार्यकारी निदेशक रोहन सक्सेना के मुताबिक बड़ी संख्या में टेक्सटाइल यूनिट, यानी कपड़ा उद्योग भी आने को तैयार हैं। इंदौर क्षेत्र में ही यह उद्योग जमीनें चाहते हैं। कपड़ा और गारमेंट उद्योग से जुड़े इन निवेशकों को जमीनें उपलब्ध भी कराई जा रही हैं। कुछ दिनों पूर्व ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर-उज्जैन रोड पर 2 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली तिरूपुर के एक गारमेंट उद्योग की भूमि का भूमिपूजन भी किया। अभी लगभग 50 कपड़ा और गारमेंट उद्योग समूह में जमीनों के लिए बुकिंग भी कर दी है, जिनमें मुख्य रूप से बेस्ट लाइफ स्टाइल, बायो कॉटन, स्पीनिंग मिल, केयरफीट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, महिमा फाइबर्स, इनवायरो फायबर्स के अलावा अन्य छोटे और मध्यम आकार के उद्योग भी शामिल हैं।

सक्सेना के मुताबिक एक दर्जन कपड़ा और गारमेंट उद्योग को जमीनें आवंटित भी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ पीथमपुर में सेक्टर-7 में स्मार्ट इंडस्ट्रीयल टाउनशिप का भी विकास शुरू किया जा रहा है। 550 करोड़ की राशि दो हजार एकड़ के इस मल्टी प्रोजेक्ट जोन को विकसित करने पर खर्च की जाएगी। 25 एकड़ से लेकर दस हजार स्क्वेयर फीट तक के 425 औद्योगिक भूखंड विकसित होंगे, जो आने वाले औद्योगिक समूह को आवंटित किए जाएंगे। अभी शुरुआत में ही कई समूहों के आवेदन प्राप्त हो गए हैं। 10 हजार करोड़ से अधिक का निवेश यहां पर आने वाले कुछ वर्षों में भी हो जाएगा।

हर तरह के उद्योंगो के लिए अलग-अलग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। नमकीन, गारमेंट, मिठाई, फर्नीचर से लेकर टॉय यानी खिलौना बनाने वाले छोटे-बड़े उद्योगों को भी जमीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। रंगवासा में बनाए जा रहे इस टॉय क्लस्टर में स्थानीय 20 से अधिक खिलौना बनाने वाले निर्माताओं ने उद्योग डालने के प्रस्ताव सौंपे हैं, जिनमें 60 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी किया जाएगा। इससे 4 हजार से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं बेटमा में 154 हैक्टेयर में फर्नीचर क्लस्टर विकसित हो रहा है, उसमें भी कई फर्नीचर निर्माताओं ने रुचि दिखाई है। वहीं पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का पहली बार मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया पिछले कुछ समय से चल रही है। कल इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई है। प्राप्त दावे-आपत्तियों की सुनवाई से लेकर आगामी प्रक्रिया इस बैठक में तय की जाएगी।

इंदौर जिले के 18 और धार जिले के 26 गांवों को पीथमपुर के पहले औद्योगिक मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। लगभग साढ़े 12 हजार हैक्टेयर निजी जमीनें इस मास्टर प्लान में शामिल की जा रही हैं और मप्र औद्योगिक केंद्र विकास निगम ने इसका प्रारूप तैयार किया और नगर तथा ग्राम निवेश ने दावे-आपत्तियों के लिए प्रकाशन कुछ समय पूर्व कर दिया था। संयुक्त संचालक एसके मुद्गल के मुताबिक 121 दावे-आपत्तियां प्राप्त हुई है। वहीं गत दिनों पीथमपुर मास्टर प्लान को लेकर बैठक भी रखी गई थी, जिसमें सुनवाई से लेकर आगे की प्रक्रिया निर्धारित की गई। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले के अम्बापुरा, बजरंगपुरा, काली बिल्लौद, बदीपुरा, बेटमाखास, बेटमाखुर्द, भंवरगढ़, बीजेपुर, धन्नड़, घाटाबिल्लौद, करवासा, किशनपुरा, मेठवाड़ा, रणमल बिल्लौद, सांगवी, सलमपुर, बंजारी और भांटखेड़ी गांवों की जमीनें भी इस पीथमपुर के मास्टर प्लान में शामिल की गई है। दूसरी तरफ राऊ-रंगवासा में टॉय क्लस्टर का विकास भी किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 20 से अधिक स्थानीय टॉय यानी खिलौना निर्माताओं ने भी जमीन ली है, जिसमें 60 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। इंदौर में बनने वाले कई खिलौने विदेश तक जाते हैं और इस टॉय क्लस्टर से चीनी खिलौना उद्योग पर निर्भरता भी घट जाएगी।

● **प्रवीण कुमार**

हर जिले में किया जा रहा लैंडबैंक तैयार

प्रदेश में औद्योगिक विस्तार तेजी से हो रहा है। खासकर प्रदेश के बड़े जिलों और शहरों के आसपास निवेश की मांग बढ़ रही है। निवेशकों की रूचि को देखते हुए लगातार जमीनों की बढ़ती मांग के मद्देनजर 10 हजार एकड़ का लैंडबैंक भी तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले उद्योगों, निवेशकों को उनकी इच्छानुसार जमीनों, भूखंडों का आवंटन किया जा सके। यह लैंडबैंक भोपाल के साथ-साथ इंदौर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद, सीहोर, सतना, राजगढ़, कटनी, बुरहानपुर, खरगोन, पन्ना, दमोह, सागर जैसे जिलों की जमीनों को लेकर बनाया जाएगा। इन क्षेत्रों में ही सबसे अधिक जमीनों की मांग है। इसमें सबसे अव्वल इंदौर क्षेत्र है। वहां अधिकांश उद्योगपति-निवेशक आना चाहते हैं। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के हर जिले में लैंडबैंक तैयार रहे, ताकि उद्योग स्थापित करने में देर और दिक्कत न हो।

बच्चों पर बरसने वाला है कोरोना का कहर...?

कोविड-19 महामारी से जूझ रही दुनिया को इस साल कोरोनारोधी वैक्सीन के आने से उम्मीद बंध गई थी कि अब कोरोना वायरस से लड़ाई जीती जा सकती है। कई देशों में कोरोना वायरस के चलते लोगों पर लगाए गए प्रतिबंध खत्म किए जाने लगे थे। लेकिन, कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया के करीब 140 से ज्यादा देशों में फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारत की बात करें, तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उपजे बुरे हालातों पर किसी तरह से काबू पा लिया गया। लेकिन, कोरोना की दूसरी लहर का पीक निकल जाने के साथ ही एक्सपर्ट ने तीसरी लहर को लेकर आशंका जतानी शुरू कर दी थी। तमाम एक्सपर्ट्स का कहना था कि अक्टूबर या नवंबर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी ने लोगों में भरोसा बढ़ाया था कि शायद कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो चुकी है। लेकिन, बीते दो दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी ने तीसरी लहर की आशंकाओं को और बल दे दिया है।

भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का पीक गुजर जाने के बाद से लेकर अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। केरल राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। बीते दिन देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 46,164 पहुंच गया है। जो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला कहा जा सकता है। इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन के एक बयान ने भारत के लिए चिंताओं को बढ़ा दिया है। डॉ. स्वामीनाथन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत में कोरोना महामारी स्थानिकता में चरण में प्रवेश कर रही है। हो सकता है कि भारत से कोरोना महामारी कभी खत्म न हो। सौम्या स्वामीनाथन ने ये भी कहा कि देश के कई हिस्सों की जनसंख्या में विविधता और अलग-अलग प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से कोरोना संक्रमण के मामलों में लंबे समय तक उतार-चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलती रहेंगी। भारत में कोरोनारोधी टीकाकरण की गति में कुछ तेजी आई है।

स्थानिकता यानी एंडेमिसिटी के दौरान आबादी में बीमारी या संक्रामक रोग की लगातार लोगों की बीच बना रहता है और उसका सामान्य रूप से फैलाव होता रहता है। बीमारी या संक्रामक रोग का ये फैलाव निम्न और मध्यम स्तर पर लोगों के बीच जारी रहता है। भारत जैसे देश की बात करें, तो यहां की विशाल आबादी विभिन्न इलाकों में फैली हुई है। हर व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता भी अलग-अलग है, तो संभावना बढ़ जाती है कि वायरस लोगों के बीच कई महीनों तक रह सकता है। हालांकि, इस दौरान संक्रमण के मामलों में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। लेकिन, वायरस लोगों के बीच से खत्म नहीं होगा। सौम्या स्वामीनाथन ने उम्मीद जताई है कि इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर जैसे घातक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि जिन जगहों पर पहली और दूसरी लहर के दौरान पीक नहीं दिखे, वहां कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं।

देश के तमाम एक्सपर्ट्स और सीरो सर्वे में भी इस बात की संभावना जताई गई थी कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बच्चों के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा कहने की वजहें भी सही नजर आती हैं। दरअसल, भारत में अभी तक बच्चों का टीकाकरण शुरू नहीं किया जा सका है। 18 साल से कम उम्र के किशोरों और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना की तीसरी लहर किसी खतरे से कम नहीं मानी जा रही है। बिना टीकाकरण के कोरोना वायरस से बचाव संभव नहीं है और भारत में बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन, तीसरी लहर को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी न होने की वजह से खतरा लगातार बना हुआ है। डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने भी चिंता जताते हुए कहा कि यह संभव है कि बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में महामारी के लक्षण बहुत हल्के दिखाई दिए हैं। संभावना इस बात की ज्यादा है कि वे और संक्रमण फैलने की वजह बन सकते हैं। लेकिन, हमें हर तरीके से तैयारी करनी होगी।

● राकेश ग्रोवर

धीमा टीकाकरण चिंता का कारण

भारत में कोरोनारोधी टीकाकरण की गति में कुछ तेजी आई है। देश में अब तक करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। लेकिन, इनमें से 46 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की केवल एक ही डोज लगी है। वैक्सीन की एक डोज की वजह से इन लोगों पर कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। 60 करोड़ टीकाकरण की संख्या को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सभी कोरोना वायरस से बच सकते हैं। वहीं, हाल ही में ये आंकड़ा भी सामने आया है कि 1.6 करोड़ लोगों ने कोरोनारोधी वैक्सीन के दूसरी डोज की समयसीमा निकल जाने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। ये सभी चीजें देश में कोरोना वायरस के फिर से कहर बरपाने की ओर काफी हद तक इशारा कर रही हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। माना जा रहा है कि केरल में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के पीछे डेल्टा वेरिएंट का ही हाथ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में लोगों को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को देखते हुए फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना न भूलें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीकाकरण ही बचाव का तरीका है।

अधर में श्रीराम वन गमन मार्ग

मप्र सरकार ने 2007 में श्रीराम वन गमन पथ बनाने की घोषणा की थी। इसको लेकर कागजी घोड़े भी खूब दौड़ाए गए। समय-समय पर योजना का खाका भी तैयार किया गया। लेकिन आज तक श्रीराम वन गमन पथ बनाने का काम शुरु नहीं हो पाया है। लोगों को लग रहा है कि सरकार की अघोषणा कागजी न बनकर रह जाए।

चुनावी फायदों के लिए सरकारें हों या फिर राजनीतिक दल लोगों को लुभाने के लिए तमाम वायदे व घोषणाएं करने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन जब उनके क्रियान्वयन की बात आती है तो उससे हाथ खींच लेती हैं। ऐसा ही कुछ मामला है मप्र में बनने वाले राम वनगमन पथ की। डेढ़ दशक बाद भी इस मार्ग को लेकर अब तक सिर्फ मौखिक व कागजी जमा खर्च करने का काम जारी है। हालत यह है कि अब तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि इसके लिए राशि का इंतजाम कहां से होगा। इस योजना के हाल यह तब हैं जबकि प्रदेश में 15 माह की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय से न केवल भाजपा की ही सरकार है, बल्कि इसकी घोषणा करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके उलट पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में इस परियोजना पर महज दो साल में ही काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद जब प्रदेश की इस मामले में बदनामी होना शुरू हुई तो अब जाकर इस पर काम शुरू करने की तैयारी शुरू की जा रही है।

इसके लिए हाल ही में संबंधित विभागों के आला अफसरों की बैठक की गई है, जिसमें मंथन के दौरान पूरा मामला एक बार राशि के इंतजाम पर आकर अटक गया। हालांकि इस दौरान आला अधिकारियों ने तय किया है कि इसके लिए अब **एनएचएआई** की मदद ली जाए। यह संस्था मदद देगी या नहीं यह तो अभी तय नहीं है, लेकिन यह जरूर तय हो गया है कि यह काम मप्र रोड डेवलपमेंट द्वारा किया जाएगा। इसे नोडल एजेंसी बनाने का तय कर लिया गया है। इस बैठक में पर्यटन, अध्यात्म, लोकनिर्माण व पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदि विभागों के आला अफसर शामिल हुए हैं। इस दौरान यह भी तय किया गया कि इसके निर्माण के लिए आर्किटेक्ट की मदद लेकर सही तरह से प्रस्ताव तैयार कराया जाए। जिसमें इसकी लागत राशि का भी उल्लेख किया जाए। फिलहाल इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। अब तक की तैयारी के हिसाब से श्रीराम वन गमन पथ के तहत छह जिलों में चिन्हित 13 स्थलों के लिए 30 मार्गों का निर्माण किया जाना है। 140 किमी लंबाई वाले इन मार्गों के निर्माण पर 77.21 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्टूबर, 2007 में चित्रकूट में राम वन गमन पथ के निर्माण की घोषणा की थी। तब उनके द्वारा कहा गया था कि वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण मप्र के जिन-जिन रास्तों से होकर निकले थे, उसे राम पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। इन जगहों पर स्मृति संग्रहालय, रामलीला केंद्र, गुरुकुल आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने राम वन पथ गमन मार्ग का पता लगाने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन अवधेश प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में किया था। इस समिति ने वर्ष 2010 में रिपोर्ट सरकार को सौंपी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर इसी 15 अगस्त को चित्रकूट से अमरकंटक तक राम वन गमन पथ बनाने की घोषणा की है, जिसके द्वारा तीन सालों में इस पर शोधकर इसके विकास के लिए वर्ष 2011 में 33 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंप दिया गया था। इसके बाद से इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। उस समय इस काम पर तीन करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दरअसल माना जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान चित्रकूट में रुकने के बाद सतना, पन्ना, शहडोल, जबलपुर, विदिशा के वन क्षेत्रों से होते हुए दंडकारण्य इलाके में चले गए थे।

राम वनगमन पथ के विकास के लिए ट्रस्ट का गठन किया जा चुका है। इसके तहत चित्रकूट से अमरकंटक तक कुल 370 किमी मार्ग पर पड़ाव स्थलों का विकास कर जगह-जगह दोहों के साइनेज लगाए जाना हैं। इस पूरी परियोजना पर कुल 700 करोड़ रुपए खर्च की संभावना है। इसी तरह से नासिक में पंचवटी से 56 किमी दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान को भी तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित है। मंदिर और अवशेष संरक्षित हैं। यहां भी विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। मप्र में करीब 375 किमी का हाईवे प्रस्तावित है जो अयोध्या से चित्रकूट तक बनेगा। प्रदेश में चित्रकूट, कामतानाथ मंदिर, सती अनुसुईया, सलेहा मंदिर (पन्ना), बड़वारा (कटनी), रामघाट (जबलपुर), शहपुरा राम मंदिर, सीतामधि (शहडोल), अनुपपुर, अमरकंटक प्रस्तावित पथ में शामिल हैं।

● **नवीन रघुवंशी**

कांग्रेस भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाई

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव-2018 के वचन पत्र में श्रीराम वन गमन पथ निर्माण का वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चित्रकूट लाकर इसे मुद्दा बनाया गया। सत्ता में आने के बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में वन गमन पथ के लिए बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। सरकार ने इसका निर्माण कार्य दो चरणों में पूरा किए जाने की योजना बनाई थी। पहले सरकार ने पीपीपी मोड पर श्रीराम वन गमन पथ के निर्माण की तैयारी की थी, लेकिन बाद तय किया गया कि सरकार खुद ही इसका निर्माण करेगी। इसके निर्माण पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होना थे। धर्मस्व विभाग ने इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसके अनुसार राम वन पथ गमन की लंबाई करीब 350 किलोमीटर है। यह पथ चित्रकूट से शुरू होकर अमरकंटक तक बनाया जाना प्रस्तावित है। इससे पहले कि पथ का निर्माण कार्य शुरू हो पाता, कांग्रेस सरकार गिर गई।

प्रदेश की बदहाल अर्थव्यवस्था को जल्द ही कोयले की कमाई का संबल मिलने वाला है। दरअसल, ऊर्जाधानी सिंगरौली की दो कोल खदानों का आवंटन हाल ही में किया गया है। इन खदानों से सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई होगी।

कोयले से भरेगा खजाना

कोविड-19 के कारण चरमराई देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र को मौका देने केंद्र भी अब कमर कस चुका है। ऐसे में हमारा सिंगरौली औद्योगिक जगत को न केवल राहत दे सकता है बल्कि रोजगार के नए अवसरों को सृजन भी करेगा। इसके लिए सरकार ने दो कोल ब्लॉक्स अमेलिया कोल माइंस और सुलियारी कोल माइंस को मंजूरी दे दी है। संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों कोल माइंस से सरकार को हर साल 1200 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इसी तरह माना जा रहा है कि यदि शासकीय स्वीकृतियों के इंतजार में फाइलों में कैद 11 कोल ब्लॉक्स को ओपन किया जाए और तीन स्वीकृत कोल ब्लॉक के काम में तेजी लाएं तो अकेले सिंगरौली में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और हजारों करोड़ की पूंजी का निवेश होगा। भारी मशीनरी और भारी वाहनों की आवश्यकता बढ़ने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी नई ऊर्जा का संचार होगा।

उल्लेखनीय है कि सुलियरी कोल ब्लॉक आंध्रप्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हैदराबाद को, अमिलिया कोल ब्लॉक टिहरी को एलॉट हो चुका है। इन कॉल ब्लॉक से जहां सरकार को बड़ा राजस्व मिलेगा, वहीं हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आंध्रप्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीएमडीसी) को आवंटित सुलियरी कोल ब्लॉक में खनन के लिए जिला प्रशासन ने माइनिंग लीज जारी कर दी है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक कोयला खनन को लेकर उनकी ओर से पहले ही पूरी तैयारी कराई जा चुकी है। कोयला खनन का कार्य अडानी ग्रुप के माध्यम से कराया जाएगा। इसके बाद धिरौली में खनन कार्य शुरू होगा।

आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन मंडल सिंगरौली के कक्ष क्रमांक आरएफ 338, 358 व 359 एवं पीएफ 315 की वन भूमि 226.349 हैक्टेयर तथा 32.89 हैक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल रकबा 259.239 हैक्टेयर में कोयला उत्खनन हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक 8-02/2020-एफसी दिनांक 15.06.2021 से अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अनुक्रम में राज्य शासन वन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1227/1720/2021/10-3 दिनांक 17.06.2021 से भारत सरकार के अंतिम अनुमोदन पर सहमति प्रदान की गई है। सुलियरी कोल ब्लॉक के विस्थापितों के लिए एपीएमडीसी अडानी ग्रुप के माध्यम से खनुआ में कालोनी तैयार करा रहा है, लेकिन अभी वहां प्लांटिंग के साथ सड़क व नाली जैसी आधारभूत सुविधाओं को लेकर कार्य चल रहा है। एपीएमडीसी ने इसकी जिम्मेदारी भी अडानी ग्रुप को ही दी है। अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अभी कॉलोनी तैयार होने में महीनों लगेंगे।

वहीं अमेलिया कोल माइंस टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड गढ़वाल उत्तराखंड को आवंटित हुई है। भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा पूर्व में अमेलिया कोल ब्लॉक के अंतर्गत मप्र राज्य खनिज निगम लिमिटेड भोपाल के पक्ष में 1627.300 हैक्टेयर क्षेत्र पर कोयले के खनिपट्टा की स्वीकृति का पूर्व अनुमोदन दिनांक 15.05.2017 को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(1) के अधीन प्रदान किया गया था। परंतु टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा नॉमिनेटेड अथॉरिटी भारत सरकार, कोयला मंत्रालय से उक्त कोल ब्लॉक आवंटन पश्चात दिनांक 11.07.2018 को अमेलिया कोल माइन अंतर्गत 1627.300 हैक्टेयर के स्थान पर 1591 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए खनिपट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। अब इसका आवंटन टीएचडीसी को कर दिया गया है। जल्द ही इन दोनों खदानों में कोयला खनन शुरू हो जाएगा और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा।

● **बृजेश साहू**

1200 करोड़ की आय

सिंगरौली जिले में दो और नई कोल खदानों के आवंटन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जानकारी के अनुसार सुलियरी और अमेलिया कोल माइंस से एजेंसियां कोयला निकालने के एवज में राज्य सरकार को करीब 1200 करोड़ का राजस्व प्रति वर्ष देंगी। उसके बाद के वर्षों में तय शर्तों के अनुरूप राजस्व में बढ़ोत्तरी होती जाएगी। देश के अलग-अलग राज्यों में कोल खदानों के आवंटन की प्रक्रिया के तहत मप्र के सिंगरौली जिले में दो खदानों का आवंटन किया गया है। इससे पहले दो और खदानें आवंटित हुई थीं। इनमें से बंधा में कोल खनन के बदले चयनित कंपनी राज्य शासन को 799.82 करोड़ रुपए वार्षिक का राजस्व देगी। जबकि धिरौली में खनन के लिए चयनित कंपनी से प्रत्येक वर्ष 398.27 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। गौरतलब है कि इन दोनों खदानों की बोली में अडानी इंटरप्राइजेज और अरविंदो रियालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हुई थी। बताया गया कि बंधा में भूगर्भीय भंडारण 441 मैट्रिक टन और धिरौली में 586.39 मैट्रिक टन है।

चहकेगी सोन चिरैया

सोन चिरैया की वापसी नए हैबिटेट में कराने की तैयारी है। वन विभाग एक हजार हैक्टेयर में सोनचिरैया का प्राकृतिक वास तैयार करेगा। अब यह प्रोजेक्ट लेट हो सकता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में विशेष प्रयास करने वाले डीएफओ अभिनव पल्लव का तबादला हो चुका है। अब नए डीएफओ इस प्लान को लेकर कितनी रूचि दिखाएंगे, यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। यह पूरा हैबिटेट फेंसिंग से कवर होगा और कूनो नेशनल पार्क से नए हैबिटेट के लिए घास भी लाई जाएगी। इस नए हैबिटेट को तिघरा, सुजवाया, पवा से आगे के क्षेत्र में तैयार किया जाएगा। इस क्षेत्र को पैच बतौर तैयार किया जाएगा, जिसमें मार्किंग भी कराई जाएगी।

वन विभाग का दावा है कि इसका हैबिटेट इस तरह तैयार किया जाएगा कि सोनचिरैया अपने वास के लिए यहां मौजूदगी दर्ज कराएगी। वहीं सोनचिरैया को लेकर विभाग को मिलने वाले हर साल 75 लाख रुपए के बजट में से आधा ही खर्च हो पाता है। इस साल 35 लाख का बजट भी सरेंडर करना पड़ा है। ग्वालियर की घाटी गांव स्थित 512 वर्ग किलोमीटर में फैला अभयारण्य मप्र का एकमात्र सोनचिरैया का अभयारण्य है।

ज्ञात रहे कि सोनचिरैया अभयारण्य घाटीगांव को 1981 में अधिसूचित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 512 वर्ग किलोमीटर था लेकिन अब डी-नोटिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद यह घट गया है। यह एरिया सिर्फ ग्वालियर जिले का है। 2008 में घायल अवस्था में सोनचिरैया को देखा गया था। इसके बाद 2011 में सोनचिरैया को देखा गया, इसे वन विभाग ने अपने रिकार्ड में भी दर्ज किया है। 2011 से लेकर अब तक इस अभयारण्य में सोनचिरैया की उपस्थिति नहीं देखी गई। इस अभयारण्य में सोनचिरैया के साथ साथ हिरण, चीतल, नीलगाय आदि जानवर भी हैं।

ग्वालियर और शिवपुरी जिले में आने वाले सोनचिरैया अभ्यारण्य के डी-नोटिफिकेशन की प्रक्रिया कुछ समय पहले ही की गई है। यहां सालों से सोनचिरैया नहीं दिखी और इसके बाद गांवो व उनके आसपास विकास कार्य रुक रहे थे। इसमें अधिकारों का विनिश्चयन किया गया और डी-नोटिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद विकास कार्य व जमीनों का क्रय-विक्रय शुरू हो गया। इससे खनन कारोबार, औद्योगिक क्षेत्र विकास, तिघरा फोरलेन, स्थानीय निर्माण कार्य और दूसरे विभागों के कार्य के रास्ते खुल गए। डी-नोटिफिकेशन में सोनचिरैया अभ्यारण्य के कुल 512 वर्ग किमी के क्षेत्र में से 111 वर्ग किमी क्षेत्र डी-नोटिफाई हो गया।

सोनचिरैया की ऊंचाई एक मीटर होती है और इसका वजन करीब 15 किलो होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार सोनचिरैया विलुप्त होने की कगार पर है। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे वजनदार है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है जो बेहद शर्मीला माना जाता है। सोनचिरैया राजस्थान में 150 की संख्या में है।

प्रदेश के एकमात्र घाटी गांव में स्थित सोनचिरैया अभयारण्य में फिर से चहक सकती है। सोनचिरैया की बसाहट देखने के लिए वन विभाग ने एक प्लान तैयार किया है। जिसके मुताबिक अंडों की हैचिंग (अंडे की सेना) की जाएगी। यह अंडे जैसलमेर से लाए जाएंगे। हैचिंग देवरी के घड़ियाल प्रजनन केंद्र में तैयार होगी। प्रदेश से सोनचिरैया का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया था। जिस पर ध्यान देते हुए वन विभाग राजस्थान के जैसलमेर से सोनचिरैया के अंडे लाकर उनकी हैचिंग कराएगा। यह हैचिंग सेंटर मुरैना की देवरी स्थित घड़ियाल प्रजनन केंद्र की तरह तैयार होगा। इसमें घास लगाई जाएगी। साथ ही वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग ने बाकायदा प्लान तैयार कर मंजूरी के लिए मुख्यालय भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस प्लान को मंजूरी देकर इसी साल से लागू कर देगी।

ग्वालियर की घाटी गांव स्थित 512 वर्ग किलोमीटर में फैला अभयारण्य मप्र का एकमात्र सोनचिरैया का अभयारण्य है। 2011 के बाद इस अभयारण्य से सोनचिरैया का अस्तित्व खो गया है। उसके बाद यहां पर सोनचिरैया देखने को नहीं मिली हैं। इसका कारण यह है कि कई उद्योग स्थापित हो गए हैं। शोरगुल के साथ लोगों की चहल-पहल अधिक हो गई है। यही कारण है कि सोनचिरैया इस अभयारण्य से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में वापस सोनचिरैया लाने के लिए प्रयास हो रहे हैं।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

सोनचिरैया को विलुप्ति से बचाने की मुहिम तेज

हमारी किस्से-कहानियों और गीतों में शामिल (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) यानी सोनचिरैया पिछले कुछ दशकों में विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बड़े पक्षी होते हैं। जिनके सिर पर अद्वितीय काली टोपी होती हैं, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। ये देश के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षी हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। वन्यजीव विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सोनचिरैया की संख्या भारत में मात्र 150 है और ये राजस्थान में ही सिमटकर रह गई हैं। सोनचिरैया की संख्या कम होने की एक वजह ये भी है कि ये पक्षी एक साल में सिर्फ एक ही अंडा देती है। जिसमें 50 फीसदी अंडे समय से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। 80 के दशक तक देश के 11 राज्यों में करीब 1500-2000 तक सोनचिरैया मौजूद थीं। बिजली के तारों का विस्तार, अवैध शिकार और घास के मैदानों का कम होना इन चिड़ियों को खतरे की जद में ले आया। अगर सोनचिरैया को बचाना है, तो इसके लिए प्रयास तेज करना होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो चीता के बाद देश से विलुप्त होने वाली ये दूसरी बड़ी जीव प्रजाती होगी।

लहसुन से मालामाल किसान

एक बीघे में 21 क्विंटल लहसुन की पैदावार

विकासखंड सुमेरपुर के पत्योरा गांव निवासी किसान ब्रजराज सिंह बताते हैं कि अभी तक वह पारंपरिक खेती करते थे, जिसमें सालभर के खाने के अलावा कुछ भी नहीं बचता था। इस बीच पिछले वर्ष केवीके वैज्ञानिक डॉ. चंचल से मुलाकात हुई। जिन्होंने लहसुन व प्याज की खेती करने की सलाह दी। उन्हीं की प्रेरणा से गत वर्ष एक बीघे में एक क्विंटल 'जी 11' बीज लाकर लगवाया। इसमें करीब 20 से 25 हजार रुपए की लागत आई होगी। हालांकि, फसल तैयार होने के बाद करीब 21 क्विंटल लहसुन का उत्पादन हुआ, जो इस समय 70 से 80 रुपए किलो के भाव में बिक रही है। उन्होंने बताया कि ये फसल किसानों के लिए बिल्कुल सुरक्षित फसल है। मवेशियों से त्रस्त किसानों के लिए लहसुन व प्याज की खेती करना बिल्कुल सही साबित हुआ है। जमीन के अंदर पैदा होने के कारण दैवीय आपदा से बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि इस बार वो दो बीघे में लहसुन की खेती करेंगे। वहीं महिला किसान फूला देवी ने बताया कि गत वर्ष उद्यान विभाग से 16 किलो लहसुन का बीज निशुल्क मिला था, जिसमें करीब 4 क्विंटल लहसुन का उत्पादन हुआ है। उन्होंने बताया कि बिना किसी रखवाली व मेहनत के ये फसल तैयार हो गई। अबकी बार अधिक क्षेत्रफल में इसकी खेती कराउंगी।

सूखे की मार के लिए चर्चित और बरसात पानी-पानी हो जाने वाले बुंदेलखंड में एक जिला ऐसा भी है जो इस समय सफेद चांदी के नाम से जानी जाने वाली लहसुन की खेती से चर्चा में है। यहां बात हो रही है बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के बारे में जहां के किसानों को लहसुन की खेती खूब रास आ रही है। यही कारण है कि बीते वर्ष लहसुन व प्याज का उत्पादन कर यहां के किसान अपनी आमदनी को दोगुनी करने में सफल रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड में हमीरपुर जिला लहसुन व प्याज उत्पादन में अव्वल रहा है। यहां के करीब 300 किसानों ने लगभग 160 हैक्टेयर में लहसुन की खेती की थी, जिसमें करीब 24 हजार क्विंटल लहसुन का उत्पादन हुआ है। किसानों की इस मेहनत को देखते हुए सरकार एमआईडीएस परियोजना के तहत कृषि विश्व विद्यालय बांदा एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लहसुन उत्पादन में लगे किसानों को मुफ्त में बीज उपलब्ध करा रही है। साथ ही समय-समय पर किसानों को कृषि तकनीक व फसल से कैसे अधिक उत्पादन निकल सके, उसके गुण भी सिखाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष करीब 500 हैक्टेयर में किसान लहसुन व प्याज की खेती कर सकेंगे।

लहसुन की खेती से किसानों में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों का डर भी खत्म हो गया है। क्योंकि लहसुन को कोई भी मवेशी व **जंगली सूअर खाना पसंद नहीं करते।** यही कारण है कि किसान लहसुन की खेती जमकर कर रहे हैं। इन फसलों को धरातल में लाने में कृषि विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉ. भानु प्रसाद मिश्रा एवं विज्ञान केंद्र कुरारा के को पीआई डॉ. प्रशांत की अहम भूमिका रही है। इनसे किसानों को समय-समय पर तकनीकी जानकारी मिलती रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों का खेती के प्रति विश्वास जगाया है। यही कारण है कि 60 हजार क्विंटल लहसुन व प्याज का उत्पादन कर हमीरपुर के किसान पूरे बुंदेलखंड में टॉप पर हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रशांत सिंह ने कहा कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परियोजना के अंतर्गत किसानों को गत वर्ष करीब 170 किलो बीज निशुल्क वितरित किया गया। जिसमें करीब 24 हजार क्विंटल लहसुन का उत्पादन किसानों ने किया है। उन्होंने बताया कि प्रति हैक्टेयर 150-160 क्विंटल लहसुन का उत्पादन होता है। लहसुन की मुख्य प्रजातियों में यमुना सफेद, जी 5, जी 11 आदि शुमार हैं।

प्रशांत सिंह ने कहा कि खरीफ के सीजन में प्याज की खेती भी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बीते वर्ष किसानों ने करीब 150 हैक्टेयर में प्याज की खेती की थी, जिसमें करीब 35 हजार क्विंटल प्याज का उत्पादन हुआ था। इस कामयाबी को देखते हुए इस बार दोगुने क्षेत्रफल में प्याज लगाए जा रहे हैं। प्रशांत ने बताया कि सबसे पहले लहसुन की नर्सरी तैयार कराई जाती है। जो जुलाई के आखिरी पखवाड़े एवं अगस्त के पहले सप्ताह तक लगाई जाती है। इसके बाद अक्टूबर एवं नवंबर महीने तक फसल तैयार हो जाती है। इसमें प्रति हैक्टेयर 250-300 क्विंटल तक उत्पादन किया जा सकता है। इससे किसानों की आमदनी भी अच्छी हो रही है।

बुंदेलखंड इलाके में यमुना, बेतवा और केन नदियों सहित तमाम नदियों में आई भीषण बाढ़ और भारी बारिश से खरीफ की पूरी फसलें बर्बाद और तबाह हो गई है। जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सूखे की मार से बेहाल रहने वाला बुंदेलखंड अब पानी-पानी होने के कारण लाखों हैक्टेयर की तलहनी और तिलहनी फसलें बाढ़ और बारिश के चलते तबाह हो गई है। खेतों में कई फुट जल भराव से खड़े-खड़े फसल सड़ गई है। ऐसे हालात में किसान एक बार फिर भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। इस बार सिर्फ हमीरपुर जिले में खरीफ की बुआई 1 लाख 9 हजार हैक्टेयर में हुई थी। तलहनी फसलो में मूंग, अरहर, मसूर जैसी फसलें और तिलहनी फसलों में तिली, मूंगफली जैसी फसलें बहुतायत में बोई गई थी। तिली के तो कटने का समय भी आ गया था। लेकिन, फिर कुदरत रूठ गई और सभी फसलें खेत में ही सड़ गई और अभी तक 70 प्रतिशत से अधिक फसले नष्ट हो चुकी हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक भी कुछ फसलों के पूरी तरह खराब होने की बात स्वीकार रहे हैं। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी की **बाढ़ और बारिश** ने ऐसी तबाही मचाई, जिससे अन्नदाता खुद दाने-दाने को मोहताज हो गया है। इस बाढ़ और बारिश की चपेट में आकर सैकड़ों मकान जमीदोश हो गए हैं। 100 से अधिक गांवों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में यहां के किसानों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। ऊपर से फसलों के खोने का गम किसानों को कर्ज के बोझ तले दबकर जीने को मजबूर कर रहा है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

साम्राज्यों के कब्रिस्तान के नाम से ख्यात अफगानिस्तान में फिर से तालिबानी राज कायम हो गया है। करीब दो दशक तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। 30-31 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजते ही आखिरी अमेरिकी सैनिक ने काबुल की धरती को अलविदा कहा। इसी के बाद अब तालिबान का अफगानिस्तान पर एकछत्र राज स्थापित हो गया है। अब देखना यह है कि वैश्विक ताकतों की हसरतों से लहूलुहान अफगानिस्तान में तालिबान किस तरह राज कर पाता है।

● राजेंद्र आगाल

तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका को 31 अगस्त तक पूरी तरह अफगानिस्तान को छोड़ देना था। लेकिन अमेरिका 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया। जैसे ही अमेरिका के चार सैन्य परिवहन विमानों सी-17 ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, तालिबान के लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अब आतंक का राज ही चलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका। अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 में हुए हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के तालिबानी राज पर हमला किया था और तालिबानियों को खदेड़ दिया था। लेकिन अब 20 साल बाद जब उसने अफगानिस्तान को छोड़ा तो फिर से वहां तालिबानियों का राज कायम हो गया। ऐसे में वैश्विक स्तर पर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया क्या? अमेरिका अफगानिस्तान का दर्द और बढ़ा गया।

अफगानिस्तान में इस समय भयावह स्थिति है। अमन-चैन से रह रही जनता किसी भी कीमत पर देश छोड़ना चाह रही है। उधर, तालिबानी लूटपाट और हत्या में जुट गए हैं। जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के भाग्य में साम्राज्यों का कब्रिस्तान बनना ही लिखा हुआ है। लड़ाकों के इस देश को जिसने चाहा रौंदा, कभी कोल्ड वार, कभी टेरर वार तो कभी जिहाद, यानी दुनियाभर की साजिशों का जंग-ए-मैदान बना रहा अफगानिस्तान। एक बार फिर से अफगानिस्तान लहूलुहान हो गया है। लहूलुहान अफगानिस्तान के हालात बता रहे हैं कि विश्व पर एक बार फिर से आतंक का खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह यह है कि विश्व के तमाम आतंकी संगठन तालिबानियों के साथ मिल गए हैं। इससे सबसे अधिक खतरा भारत को है। क्योंकि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। तालिबानियों के साथ जिन आतंकी संगठनों ने हाथ मिलाया है, उनके निशाने पर हमेशा से भारत रहा है।

अमेरिका का गुरूर ध्वस्त

अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होते ही अपने आपको सर्वशक्तिमान कहने वाले अमेरिका का गुरूर ध्वस्त हो गया। 31 अगस्त 2021, ये विश्व के इतिहास में ऐसा दिन हो गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को मॉर्डन वर्ल्ड का सरदार कहने वाले अमेरिका की मिलिट्री आतंकी तालिबान से परास्त होकर अपने देश वापस चली गई। गत 15 अगस्त को दुनिया ने अफगानिस्तान पर पुनः तालिबान का कब्जा होते हुए देखा। यह घटना अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 20 साल पहले शुरू किए गए युद्ध की विफलता का प्रतीक है। तालिबान के खिलाफ इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जान, माल और संसाधनों का नुकसान हुआ। इतने व्यापक स्तर पर छेड़ी गई इस मुहिम का जो नतीजा निकला उसकी कल्पना नहीं की गई थी। वर्ष 1929 में संक्षिप्त गृहयुद्ध को छोड़कर पहले और दूसरे विश्व युद्धों के दौरान भी अफगानिस्तान काफी हद तक शांतिपूर्ण था, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य से वहां की स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चले शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बन गया। वर्ष 1979 में तत्कालीन सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इसके उपरांत 1990 के बाद वहां गृहयुद्ध छिड़ गया जिसने अफगानिस्तान को एक असफल राज्य में बदल दिया। उसका संघीय ढांचा चरमराता चला गया और तालिबान की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। फिर 21वीं सदी की शुरुआत में एक बड़ी घटना घटी। अलकायदा नामक एक आतंकी संगठन ने अमेरिका पर बर्बर हमलों को अंजाम दिया। चूंकि अलकायदा अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए था, लिहाजा अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और उससे भी अधिक विस्थापित हुए।

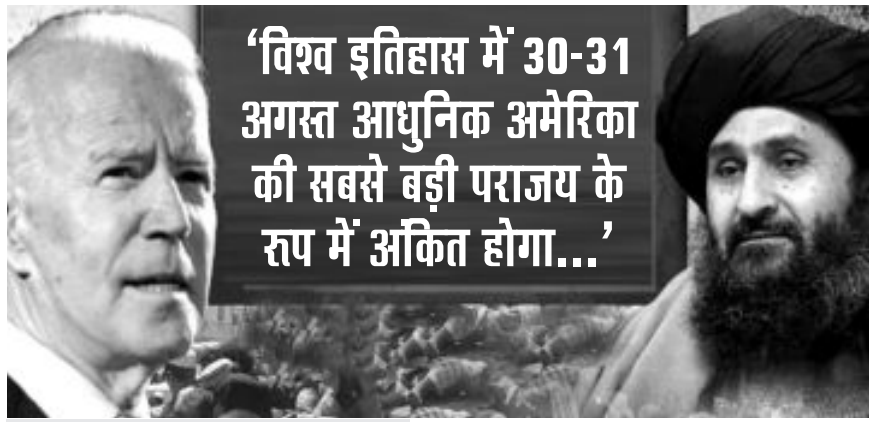

अमेरिका को ले डूबा अहंकार

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कुछ समय पहले जब यह घोषणा की थी कि वह 31 अगस्त तक अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटा लेंगे तभी से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि अमेरिका तालिबान को नियंत्रित किए बिना वहां से निकल रहा है और इसके दुष्परिणाम अवश्य सामने आएंगे। तालिबान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा के उपरांत ही अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। हैरानी यह रही कि अफगान सेना ने शायद ही कहीं पर तालिबान का प्रतिरोध किया हो। ऐसे हालात में भी अमेरिका का आंकलन यह था कि तालिबान के काबुल तक पहुंचने में करीब 90 दिन लग सकते हैं, लेकिन वे एक सप्ताह के अंदर ही वहां जा धमके। इसी के साथ अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी खुफिया तंत्र के आंकलन की पोल खुल गई। तालिबान के काबुल पर कब्जे के साथ ही हजारों अफगानी नागरिक जिस तरह देश छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर जमा होने लगे और इसके कारण जैसे हालात पैदा हुए, वे दिल दहलाने वाले रहे। कई लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए हवाई जहाज के बाहर ही लटक गए और अपनी जान गंवा बैठे। कई माताएं अपने बच्चों को अमेरिकी सेनाओं को सौंपने लगीं कि उनकी जान बचा लो। अफगान सेना ने तालिबान के सामने जिस तरह हाथ खड़े किए, उससे स्पष्ट है कि वह एक खोखला सैन्य बल था। देश छोड़कर भागे अशरफ गनी ने सफाई दी कि उन्हें अपनी जान का भी खतरा था, क्योंकि इसी तालिबान ने 25 साल पहले अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्ला को मारकर लैंपपोस्ट पर लटका दिया था। उनकी आशंका सही भी हो सकती है, लेकिन यह भी देखना होगा कि उन्होंने अमेरिका को अंधेरे में रखा और खुद अमेरिकी अधिकारी भी यह नहीं देख सके कि अफगान सेना किस हाल में है?

अमेरिका के संयुक्त चीफ आफ स्टाफ के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार कार्टर मल्कासियन ने अपनी एक किताब में तालिबान के बारे में बताया है कि '2019 में कंधार में तालिबान के एक धार्मिक विद्वान से उनकी मुलाकात हुई। उसने उन्हें बताया कि तालिबानी अपनी आस्था के लिए लड़ते हैं, जबकि उनकी नजर में सेना और पुलिस पैसे के लिए लड़ती हैं। तालिबानी अपनी आस्था के लिए अपना सिर कटवाने को तैयार हैं तो ऐसे में सेना और पुलिस उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं?' वह आगे लिखते हैं कि 'तालिबान ने कुछ ऐसा निदर्शन दिया है, जिसने उसके लोगों को प्रेरित कर दिया है। जिसने उन्हें युद्ध में शक्तिशाली बना दिया है। उन्हें एक अफगान होने का मतलब बता दिया है।' जाहिर है तालिबान की विचारधारा के प्रसार का कारण तो अमेरिका को पता था, पर उसका प्रभावी प्रत्युत्तर देना उसे समझ नहीं आया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तालिबान की हिंसा का मुकाबला हिंसा से करने का रास्ता चुना। उन्होंने इस अनुमान के आधार पर एक युद्ध छेड़ दिया कि वे अफगानिस्तान पर आक्रमण करेंगे और तालिबान का सफाया कर देंगे। 9/11 के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि 'तालिबान इसकी कीमत चुकाएगा', लेकिन हजारों सैनिकों, अरबों डॉलर, तकनीक और दूसरे संसाधन झोंकने के बावजूद परिणाम अमेरिकी सोच के उलट निकला। दरअसल अमेरिका और उसके साथी इंसानी लक्ष्य पर प्रहार करते रहे, इस बात से

भारत के दरवाजे पहुंच चुका है खतरा

पिछले साल गलवान घाटी में संघर्ष के बाद से चीन संग तनाव है, ऊपर से अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड में भारत की भागीदारी को लेकर भी चीन ने आंखें तरेरी। 2019 में अनुच्छेद-370 के प्रावधान खत्म करने के बाद से पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ उबल पड़ा है। तालिबान के साथ पिछले अनुभव को देखते हुए भारत के लिए साफ खतरा मालूम होता है। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईसी 814 का अपहरण सबको याद होगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 1990 में जम्मू और कश्मीर के भीतर हर पांचवां आतंकी अफगान लड़का था। ऐसे में तालिबान चाहे जितना बदलने का दावा करे, खतरा भारत के दरवाजे पर है और आजादी के बाद से इतना बड़ा खतरा नहीं आया है।

बेखबर रहे कि वास्तविक समस्या एक कट्टर विचारधारा थी। यह वही अमेरिका है जिसने लगभग तीन दशक पहले साम्यवाद की बड़ी दीवार गिरा दी थी। फिर तालिबान के खिलाफ वह नाकामयाब कैसे हो गया?

अमेरिकी धोखे की कीमत

अमेरिकी इतिहास में सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने जो बाइडन के कुछ फैसले दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को शर्मसार कर रहे हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के साथ ही बाइडन वैश्विक कोप के भाजन बन गए हैं। असल में यह तभी तय हो गया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सैन्य अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों की राय को दरकिनार कर जमीनी हकीकत की परवाह किए बिना ही अफगानिस्तान से जल्दबाजी में सैन्य बलों की वापसी का ऐलान कर दिया था। इसके लिए कोई कारगर योजना भी नहीं बनाई। ऐसे में विदेश नीति के मोर्चे पर ऐसा अनर्थ होना ही था। अफगानिस्तान पर आतंकी शिकंजे से अमेरिका की जो अंतरराष्ट्रीय फजीहत हो रही है, उसके दोषी बाइडन ही हैं। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में निकलने को लेकर बाइडन के सामने कोई रणनीतिक या घरेलू मजबूरी भी नहीं थी। जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब अफगानिस्तान में अमेरिका के केवल 2,500 सैनिक तैनात थे। फिर भी बाइडन को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने सैन्य बलों की संपूर्ण वापसी पर मुहर लगा दी।

माना जाता है कि अमेरिका उकता गया था, जबकि गत 20 वर्षों के दौरान गैलप सर्वेक्षणों में अमेरिकी इस सैन्य सक्रियता के विरोध से अधिक समर्थन में ज्यादा नजर आए। अमेरिकी इतिहास की इस सबसे लंबी लड़ाई को इतने सतत स्तर पर मिला समर्थन कोरिया, वियतनाम और इराक जैसे अन्य जंगी अखाड़ों से उलट था, क्योंकि अधिकांश जनता एक स्तर पर आकर उन युद्धों के खिलाफ हो गई थी। 1 जुलाई को बगराम एयरबेस खाली करने के साथ ही बाइडन ने जब अफगानिस्तान से कदम पीछे खींचने की शुरुआत कर दी, तब से जनता की राय में भी विभाजन आरंभ हो गया। 6 जुलाई से 21 जुलाई के बीच हुए गैलप सर्वे में 47 प्रतिशत अमेरिकियों (अधिकांश डेमोक्रेट) ने यह माना कि अफगान युद्ध एक गलती थी, जबकि 46 प्रतिशत की राय इसके विपरीत थी।

तालिबान दुर्दांत आतंकी संगठन

पाकिस्तानी पिट्ठू तालिबान दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकी संगठनों में से एक है। चूंकि तालिबान ट्रंप के साथ हुए समझौते का खुलेआम उल्लंघन करता रहा, इसलिए बाइडन के उस पर टिके रहने का कोई तुक नहीं था। अगर अमेरिका अफगानिस्तान में सीमित सैन्य मौजूदगी रखता

कई देशों में महाशक्ति अमेरिका ने दिखाई पीठ

करीब 20 बरस बाद अमेरिका अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ है। अमेरिका के पीछे हटने के मामलों में सबसे ज्यादा चर्चित है वियतनाम का किस्सा। अफगानिस्तान से पांच गुना सैनिक और 19 साल की भीषण बमबारी के बावजूद अमेरिका कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम को झुका नहीं सका। घरेलू दबाव के आगे 1969 में राष्ट्रपति बने रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम से बाहर निकलने का मन बना लिया। जनवरी 1973 में पेरिस में अमेरिका, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम और वियतकॉन्ग के बीच शांति समझौता हुआ। 17 अप्रैल 1961 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलटने के लिए अमेरिका ने सीआईए के जरिए पिग्स की खाड़ी के रास्ते हमला किया। जमीनी हमले से पहले पांच अमेरिकी विमानों से बमबारी की गई। इनमें तीन विमानों को क्यूबा ने मार गिराया। योजना के मुताबिक हमलावरों की मदद के लिए अमेरिका को दूसरे चरण की बमबारी करनी थी, मगर हमला फेल होता देख अमेरिका मुकर गया और उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 3 अक्टूबर 1993 को सोमालिया की राजधानी मोगादिशू में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए जाने की घटना को भी अमेरिका की हार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 3-4 अक्टूबर 1993 की रात को ये लड़ाई यूएन समर्थित अमेरिकी सेनाओं और मोहम्मद फराह अदीदी वाली सोमालियाई विद्रोही सेना के बीच लड़ी गई। जनवरी 1991 में अफ्रीकी देश सोमालिया में कई विरोधी कबीलों की मिलिशिया, यानी सशस्त्र विद्रोही गुटों ने राष्ट्रपति मोहम्मद सियाद बरे का तख्ता पलट दिया। सोमालिया की राष्ट्रीय सेना के सैनिक अपने-अपने कबीलों के सशस्त्र गुटों में शामिल हो गए। पूरे सोमालिया में सत्ता हथियाने के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। राजधानी मोगादीशू में मुख्य विद्रोही गुट यूनाइटेड सोमालिया कांग्रेस भी दो गुटों में बंट गया था। इनमें एक गुट का नेता अली मेहदी मुहम्मद राष्ट्रपति बन गया। दूसरे गुट को मोहम्मद फराह अदीदी चला रहा था। मानवीय संकट बढ़ने पर यूनाइटेड नेशन्स ऑपरेशन इन सोमालिया-2 के तहत आम लोगों को खाने-पीने और डॉक्टरी मदद शुरू की गई, मगर अदीदी का गुट इसमें आड़े आ रहा था। ऐसे में अमेरिका ने 3 अक्टूबर को मोगादीशू में एक घर से अदीदी के दो करीबी साथियों को पकड़ने के लिए सेना की टास्क फोर्स भेजी। यह हमला अमेरिका के लिए बड़ा मुसीबत बन गया। जैसे-तैसे अमेरिकी सैनिक वहां से निकाले गए। अब अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली।

तो इससे बहुत ज्यादा खर्च नहीं बढ़ता और अमेरिकी लोगों के लिए जोखिम भी घटता। 2014 में अमेरिका की युद्धक भूमिका खत्म होने के साथ ही अमेरिकी वित्तीय खर्च और सैनिकों को पहुंचने वाली क्षति नाटकीय रूप से कम हो गई थी। तबसे अमेरिकी या नाटो फौजें नहीं, बल्कि अफगान सुरक्षा बल ही अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे। पिछले करीब साढ़े सात वर्षों के दौरान जहां अफगान सुरक्षा बलों के दस हजार से अधिक जवानों को जान गंवानी पड़ी, वहीं अमेरिका के 99 सैनिकों ने बलिदान दिया। अगर बाइडन 2,500 सैनिक भी अफगानिस्तान में नहीं रखना चाहते थे तो कम से कम इतने सैनिक तो तैनात कर ही सकते थे जो आवश्यकता पड़ने पर अफगान बलों को महत्वपूर्ण हवाई सुरक्षा सहयोग मुहैया करा पाते। ऐसा करने से उस विपदा को रोका जा सकता था, जो अब भयावह रूप से आकार ले रही है।

अगर तालिबानी अपनी मुहिम में सफल रहे तो अमेरिका के अघोषित सहयोग से। अमेरिका ने पिछले वर्ष से ही इस आतंकी समूह को एक प्रकार की मान्यता देनी शुरू कर दी थी। इससे अफगान सरकार की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ। अमेरिका अपनी सहयोगी अफगान सरकार को दरकिनार कर दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकी संगठन से गलबहियां करने लगा। अमेरिकी विश्वासघात का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसने अफगान सरकार की पीठ पीछे फरवरी 2020 में तालिबान के साथ समझौता किया। इसके बाद काबुल पर 5,000 तालिबानी कैदियों को रिहा करने के लिए दबाव बनाया। उनकी संख्या अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों के बराबर थी। ये तालिबानी रिहा होकर रक्तपात में लग गए। यह कमोबेश ऐसा ही था जैसे 2019 में अमेरिका ने सीरिया में अपने कुर्दिश साथियों का साथ छोड़ दिया था। अमेरिकी विश्वासघात ने अफगान सेना के पैरों तले जमीन खिसका दी।

अमेरिका की बड़ी पराजय

नि:संदेह तालिबान की वापसी से सबसे अधिक नुकसान अमेरिका को पहुंचा है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को एक आतंकी गुट के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। दो दशक लंबी अमेरिकी लड़ाई का परिणाम प्रतिद्वंद्वी खेमे की पुन: सत्ता में वापसी के रूप में निकला है। अफगानिस्तान में अमेरिकी हार के भू-राजनीतिक निहितार्थ उसकी वियतनाम में हुई पराजय से कहीं अधिक व्यापक प्रभाव वाले हैं। अमेरिका को खदेड़ने में तालिबान को मिली कामयाबी से वैश्विक जिहादी मुहिम से जुड़े अन्य धड़ों को नई ऊर्जा मिलेगी। अफगान धरती उनकी ऐशगाह बन सकती है। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी ने भारत की चुनौतियां बहुत बढ़ा दी हैं। खासतौर से पाकिस्तान के पहलू को देखते हुए, जो तालिबान का इस्तेमाल भारतीय हितों पर आघात करने के लिए कर सकता है। वैसे भी अमेरिकी पराभव के साथ भारत के खिलाफ चीन-पाकिस्तान रणनीतिक गठजोड़ और मजबूत ही होगा।

सैन्य वापसी से जुड़ा बाइडन का फैसला घातक प्रभाव डालने वाला रहा। इससे नाटो गठबंधन के 8,500 सैनिक और करीब 18,000 अमेरिकी सैन्य कांट्रेक्टरों की वापसी की राह खुल गई। इन कांट्रेक्टरों की अफगान वायुसेना और अमेरिकी आपूर्ति वाले आयुध तंत्र के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अमेरिका ने अफगान सैन्य बलों को स्वतंत्र रूप से भूमिका निभाने के लिए न तो जरूरी हथियारों से लैस किया और न ही पर्याप्त प्रशिक्षण दिया। वे अमेरिकी और नाटो के समर्थन पर ही निर्भर थे। इस यकायक वापसी ने अफगान सैन्य बलों को निस्तेज कर दिया। कांट्रेक्टरों की वापसी ने भी अफगान वायुसेना की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उन पर निर्भर थी। सीआईए के पूर्व निदेशक जनरल डेविड पेत्रोस का कहना है कि जब तक अमेरिका ने अचानक अपना समर्थन पीछे नहीं खींचा, तब तक अफगान सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़ते और अपनी शहादत देते रहे। अमेरिकी फैसले ने उन्हें बड़ा मानसिक आघात दिया और अफगान सुरक्षा आवरण भरभराकर ढह गया।

इतिहास की बात करें, तो जिस ब्रिटेन के साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, 1842 में उस ब्रिटेन को अफगानिस्तान में नाकों चने चबाने पड़ गए थे। उसके 4500 जवान बर्फ से ढकी हिंदूकुश की पहाड़ियों पर मार दिए गए, ब्रिटेन की मदद करने वाले 12,000 अन्य लोग भी मारे गए थे। अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिका आज उसी इतिहास को जीवंत कर गया जिसे 1989 में तत्कालीन सोवियत रूस ने दोहराया था जब 1979 से 89 तक चले 10 साल के भीषण संघर्ष के बाद सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने भारी मन से अफगानी जमीन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के समझौते पर दस्तखत किए। कोल्ड

अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए इतना टकराव क्यों?

आखिर अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर इतना टकराव क्यों है? न उद्योग, न धंधे, न स्किल्ड मैन पावर, न ही विलासितापूर्ण जीवन की उम्मीद। दरअसल, अफगानिस्तान तो अभी भी मध्य युग में जी रहा एक अनमना सा ऊंघता हुआ देश है। तकनीक और विज्ञान से दूर। मजहब के विकृत रूपों को ढोने पर मजबूर। आप कह सकते हैं अफगानिस्तान एक अविकसित देश है। फिर उसके लिए जंग क्यों? प्राचीन इतिहास की बात करें तो सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, चंगेज खान, तैमूर लंग, बाबर और न जाने कितने लड़ाकू कबीले इसे लांघकर गए हैं। अफगानिस्तान वो जमीन है जिस पर गुजरे बिना किसी शासक का विश्व विजेता का सपना मुकम्मल नहीं होता है। क्योंकि मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का दरवाजा तो अफगानिस्तान ही है। दरअसल पृथ्वी की सतह पर अफगानिस्तान नाम के भूखंड की बनावट और बसावट ऐसी है कि दुनिया के लिए वह दुरुह और लुभावना दोनों है। अफगानिस्तान से होकर आप आसानी से पश्चिम एशिया जा सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के लिए रास्ता सुगम है। अफगानिस्तान की सीमा चीन से लगती है। वाखान गलियारे से होकर आप चीन जा सकते हैं। ईरान उसका पड़ोसी है। यहां से होकर आप फारस में जाकर यूरोप पहुंच सकते हैं। पूर्व में पाकिस्तान से उसकी लंबी सीमा मिलती है।

वार के उस दौर में मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा के अगुवा और इस्टर्न ब्लॉक के प्रमुख यूएसएसआर को इस युद्ध में अपने 15,000 जवानों को गंवाना पड़ा था।

भारत के लिए खतरा!

अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से इस बात को लेकर डर बना हुआ है कि भारत पर हमले के लिए आतंकियों को यहां पर शरण मिल सकती है। वहीं, ये डर सच साबित होते हुए भी नजर आ रहा है। दरअसल, एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान में आतंकी गठजोड़ का एक नया नेटवर्क बन रहा है। इसका नाम 'तहरीक-ए-तालिबान अमीरात' है। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर काम करने वाला है। हाल के दिनों में जैश-ए-मोहम्मद सबसे ताकतवर आतंकवादी संगठन के रूप में उभरा है। वहीं, जैश के मुखिया मसूद अजहर और मोहम्मद इब्राहिम अजहर को अफगान ऑपरेशन तालमेल का मुखिया बनाया गया है। दरअसल, जैश-ए-मोहम्मद की योजना आतंकियों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देने की है। वह अपने ट्रेंड आतंकियों के जरिए तालिबान के दूसरे नए कैडरों को ट्रेनिंग देने में मदद करेगा। इस बात की जानकारी मिली है कि जैश-ए-मोहम्मद के अनेक सीनियर आतंकियों को अफगानिस्तान ऑपरेशन के तहत भेजा गया है। गौरतलब है कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि हक्कानी नेटवर्क के इस्लामिक स्टेट के साथ भी संबंध हैं। ऐसे में हक्कानी नेटवर्क की वजह से भारत को चिंता में होना चाहिए। बताया गया है कि अफगानिस्तान में सरकार गठित करने की कवायद तेज है और इसमें हक्कानी नेटवर्क को भी जगह मिल सकती है। हक्कानी नेटवर्क ने कई आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया है। इसमें आम नागरिकों से लेकर विदेशी जवानों को जान गंवानी पड़ी है। हालांकि, इन सबके बाद भी हक्कानी नेटवर्क तालिबान सरकार में बड़ा पावरफुल प्लेयर बनकर उभर सकता है। इसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई संग भी

रिश्ते हैं। इस बात का पहले से अंदेशा था कि तालिबान की वापसी भारत समेत पूरे उपमहाद्वीप के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। दरअसल, पाकिस्तान के भी तालिबान के साथ संबंध हैं और वो इसे भारत के खिलाफ कार्रवाईयों के लिए भुनाने की कोशिश करेगा। वहीं, इस बात का भी डर है कि पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकी अब अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हालांकि, तालिबान ने कहा है कि वह अफगानिस्तान की जमीन को आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा और जल्द ही इस्लामिक स्टेट के हमलों पर नकेल कसी जाएगी।

खतरनाक चौकड़ी

अफगानिस्तान में तालिबानी राज से भारत पर खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है तालिबान से बढ़ती चीन, पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती। यह चौकड़ी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। काबुल ढहने के अगले दिन ही, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनइंग ने कहा, तालिबान ने बार-बार चीन के साथ अच्छे रिश्ते विकसित करने की उम्मीद जताई है और हम इसका स्वागत करते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान तो एक कदम आगे निकल गए। खान ने कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मानसिक गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली हैं। ईरान का नजरिया अलग रहा। अशरफ गनी सरकार के साथ अच्छे रिश्तों के बावजूद ईरान ने तालिबान के साथ संबंध खराब नहीं किए। तालिबान के टेकओवर पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की हार एक मौके में तब्दील की जानी चाहिए। रूस अपनी प्रतिक्रिया में बेहद सावधान था मगर उसने तालिबान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए काबुल में दूतावास खोले रखा है।

अमेरिका के हटने के बाद से खाली जगह भरने की होड़ अब और तेज और तगड़ी होती जाएगी। तालिबान को भी आगे का प्लान सामने रखा है। उसके सामने दो विकल्प हैं। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई या अब्दुल्ला अब्दुल्ला जैसे पुराने चेहरों को लेकर एक सरकार बनाए या फिर 1990 की तरह सिर्फ तालिबान का ही राज चले। अफगानिस्तान में जैसे भी सरकार बने, भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान बस मौका तलाशता है, चीन के साथ सीमा पर तनाव जारी है और ईरान पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे में भारत को बदलते हालात पर पैनी नजर रखनी होगी।

भारत की प्रतिबद्धता और लगाव अफगानी जनता के प्रति

अब भारत के सामने क्या विकल्प हैं? एक दूरदर्शी नेतृत्व कठिन परिस्थितियों में भी सफलता का रास्ता खोज लेता है। भारत को भी कुछ ऐसा ही करना होगा। सबसे पहले तालिबान से संपर्क कर यह बताना होगा कि हमारी प्रतिबद्धता और लगाव अफगानी जनता के प्रति रहा है और भविष्य में भी रहेगा। विकास के लिए हमने जो करोड़ों रुपए वहां लगाए हैं, वह अफगानी जनता की भलाई और प्रगति के लिए थे। हमें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखना पड़ेगा। अफगानिस्तान को बताना होगा कि उसकी भूमि का भारत में आतंक को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आश्वासन मिलता है तो अच्छी तरह परखने के बाद भारत अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता देने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा हमारी खुफिया एजेंसियों को पश्तून राष्ट्रवादी तत्वों से संपर्क कर उन्हें सशक्त करने का प्रयास करना होगा। डूरंड रेखा को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मतभेद हैं, इसका लाभ उठाया जा सकता है। चीन उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार कर रहा है उसकी सही तस्वीर भी अफगानिस्तान की जनता और सरकार के सामने रखने का प्रयास होना चाहिए। चीन और तालिबान की दोस्ती विशुद्ध अवसरवादी है। वैचारिक स्तर पर दोनों विपरीत ध्रुवों पर हैं। इन दोनों पक्षों का अप्राकृतिक तालमेल जितना बिगड़े, उतना विश्व शांति के हित में होगा।

सरकार को 6,800 करोड़ की चपत

रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में पिछले एक साल से नए प्रोजेक्टों का पंजीयन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। मजदूर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। यही नहीं अटके प्रोजेक्ट से सरकार को भी करीब 6,800 करोड़ की चपत लगी है। दरअसल, रेरा में सक्षम अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं होने से पूरा कामकाज ठप पड़ा है। नए प्रोजेक्टों का पंजीयन नहीं किया जा रहा है। पंजीयन आवेदन महीनों से लंबित पड़े हुए हैं।

कोरोनाकाल में कई सेक्टरों में काम तेजी से शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश के रियल इस्टेट सेक्टर में परेशानियां बरकरार हैं। प्रदेश के 451 प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए रियल इस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवल्पमेंट एक्ट (रेरा) ने अटका रखे हैं, हालांकि अब आवेदनकर्ताओं को सुनवाई के लिए रेरा की तरफ से पत्र आने लगे हैं, लेकिन मंजूरी के लिए तीन से ज्यादा महीने का समय लग सकता है। इस कारण डेवलपर प्लाटों को बेच नहीं पा रहे हैं और इसका असर प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है।

प्लाटों की खरीद और बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी, देरी को रोकने के लिए प्रदेश में रेरा तीन साल से लागू है, लेकिन रेरा के लिए बने प्राधिकरण में स्टाफ की कमी, समिति के गठन में देरी जैसे मामलों के कारण प्रोजेक्टों की मंजूरी नहीं हो पा रही है। बिल्डरों ने प्रोजेक्टों को जमीन पर लाने के लिए करोड़ों रुपए के निवेश कर रखे हैं, लेकिन रेरा में प्रोजेक्ट का पंजीयन नहीं होने की वजह से बिक्री नहीं हो पा रही है। कई बिल्डरों ने तो बैंक से भी तगड़ा लोन ले रखा है और अब उन्हें प्रोजेक्ट का काम बीच में ही रोकना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में 670 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मप्र रियल इस्टेट का बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग भोपाल, इंदौर और जबलपुर में प्रापर्टी खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन 451 प्रोजेक्टों को मंजूरी नहीं मिलने के कारण खरीददारों को भी विकल्प नहीं मिल पा रहे हैं। पिछले दिनों रेरा के अफसरों की बैठक हुई थी। तब यह आश्वासन दिया गया था कि अब पंजीयन की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

प्रदेश में रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का काम धीमा चल रहा है। इससे बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े क्षेत्रों में स्टील, सीमेंट, ईंट, बालू रेत की डिमांड कम हो गई है। खरीददारों को नए विकल्प नहीं मिल पा रहे हैं। सरकारी आवासीय प्रोजेक्टों को भी रेरा में पंजीयन अनिवार्य है। देरी के कारण विकास प्राधिकरणों, गृह निर्माण मंडल जैसे संस्थान नए प्रोजेक्टों के लिए कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं।

उधर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में हो रहा विलंब डेवलपर के साथ बैंक, सरकार, आम आदमी, व्यापारी और मजदूर सब पर भारी पड़ रहा है। रियल इस्टेट डेवलपर की संस्था क्रेडाई ने अनुमान लगाया है कि पिछले एक साल से मंजूरी अटकने से डेवलपर के पूरे प्रदेश में 32,600 करोड़ रुपए अटक गए हैं। इस राशि पर डेवलपर को हर माह 1200 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। अटके प्रोजेक्ट्स पर करीब 1.10 लाख घर बनाए जाने थे। 80 प्रतिशत लोग बैंकों से होम लोन लेकर घर खरीदते हैं। प्रोजेक्ट्स को मंजूरी न मिलने से संकटग्रस्त बैंकों ने 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अवसर गंवा दिया है।

पूरे प्रदेश में सभी डेवलपर्स से मिले फीडबैक के आधार पर क्रेडाई ने अनुमान लगाया है कि इन प्रोजेक्ट्स पर काम होने की स्थिति में करीब 50 हजार प्रवासी मजदूरों को एक साल तक लगातार काम मिलता। अब वे बेकार हो गए हैं। क्रेडाई का अनुमान कहता है कि प्रोजेक्ट्स को समय पर मंजूरी मिल जाती तो अब तक सरकार के खाते में 6,800 करोड़ रुपए आ चुके होते। क्रेडाई मप्र के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल का कहना है कि हमने यह अध्ययन हर सेक्टर से जुड़े लोगों के बीच किया है। रेरा और सरकार को स्थिति की भयावहता समझनी चाहिए।

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सिर्फ 6 प्रोजेक्टों को अनुमति देने योग्य पाया है। जबकि पिछले करीब 6 माह के अंदर 100 से अधिक बिल्डरों ने 256 नए प्रोजेक्टों को लांच करने के लिए रेरा से अनुमति मांगी थी। रेरा ने 250 प्रोजेक्टों में तमाम तरह की कमियां और शर्तों के अनुसार प्रोजेक्ट प्लान नहीं पाए जाने पर उन्हें ठंडे बस्ते में डालते हुए बिल्डरों को कमियों को पूरा करने के लिए कहा है।

सूत्रों का कहना है कि रेरा अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव ने जब नए प्रोजेक्टों के स्वीकृति के संबंध जुड़ी फाइलों की जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल में पाया कि कई ऐसे प्रोजेक्टों को तकनीकी शाखा से स्वीकृति दी गई गई थी, जो ले-आउट, भवन अनुज्ञा, प्रोजेक्ट प्लानिंग निर्धारित शर्तों और मानदंडों के अनुसार नहीं पाए गए थे। हालांकि अध्यक्ष की समीक्षा और जांच पड़ताल के बाद तकनीकी सदस्य और शाखा में इसका परीक्षण किया था और इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी थी।

● **विकास दुबे**

तैयार मकान, फ्लैट भी नहीं बेचे जा सकते

1 जून से निर्माण गतिविधियां फिर शुरू हो गई हैं। ऐसे में 451 प्रोजेक्ट का पंजीयन नहीं होने से इनकी खरीदी-बिक्री प्रभावित हुई है। क्योंकि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के कोई भी प्रोजेक्ट में खरीदी-बिक्री नहीं हो सकती है। ऐसे में ग्राहक को मकान, फ्लैट का सौदा करना भी हो तो भी वह बिक नहीं सकता। प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं होने से बिल्डर के पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए राशि भी नहीं आती है, जबकि नंबर होने पर निर्माण की विविध चरणों में वह खरीदार से राशि लेकर प्रोजेक्ट को पूरा करता है। इससे प्रोजेक्ट भी तेजी से पूरा होता है। बिल्डर के पास जब तक खर्च करने की स्थिति होती है वह निर्माण कराता है। इसके बाद बुकिंग नहीं होने से प्रोजेक्ट रुकता है। ऐसे में लागत बढ़ती है, क्योंकि श्रमिकों को भुगतान देना होता है, माल महंगा होता है।

विकल्प की तलाश

मोदी सरकार के खिलाफ पिछले दिनों 19 दलों के नेताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई। विपक्ष को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को एकजुटता से हराया जा सकता है। क्योंकि मोदी की लोकप्रियता निरंतर कम हो रही है।

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जितने भी आंकलन किए गए हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज हुई है। विपक्ष इसे बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। इसके लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट भी होने लगी हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को इतनी आसानी से मात देना संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव-भाव जिस तरह बदले नजर आ रहे हैं, उससे विपक्ष विकल्प की तलाश में जुट गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जो गलतियां की हैं, उसका अहसास उन्हें होने लगा है। इस कारण उनकी मनोदशा बदलने लगी है।

दरअसल, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के मन की जो दशा थी उसे पूरे देश ने महसूस किया। 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री की घबराहट उनकी देह-भंगिमा से छिपाए ना छिप रही थी। उनमें पिछली बार की अपेक्षा कम जोश और जुनून नजर आया। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं, वे चिंताजनक हैं। वे सर्वे 100 टंच खरे भले ही न हों फिर भी 6 माह के अंतराल से नियमित रूप से हो रहा देशव्यापी सर्वे नेताओं और पार्टियों की लोकप्रियता के आंकलन का एक मजबूत आधार बना हुआ है। सर्वेक्षण की नवीनतम कड़ी सत्ताधारी दल के आत्मविश्वास के गुब्बारे की हवा निकालने के लिए काफी है लेकिन विपक्ष ने अगर कोई आस लगा रखी है तो फिर यह सर्वे उस आस को भी खामख्याली साबित करने के लिए काफी है।

लोकसभा के चुनाव अभी हो जाएं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसे लेकर सर्वे में जो अनुमान लगाए गए हैं, यहां मुराद उससे कत्तई नहीं। सच कहा जाए तो मध्यावधि ओपनियन पोल की सूरत में भी ऐसे अनुमानों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया और जहां तक इस सर्वे में सीटों के बारे में लगाए गए अनुमान का सवाल है, उसे लेकर गंभीरता से सोचने-विचारने के कारण और भी कम हैं क्योंकि सर्वे के इस चरण के लिए लोगों से जो साक्षात्कार लिए गए हैं उनमें से आधे तो टेलीफोन के जरिए संपन्न हुए।

दरअसल, जितने भी सर्वे आए हैं, उनमें नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता ने भाजपा को असमंजस में डाल दिया है। उधर, सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, तो अभी भी अधिकांश की पसंद मोदी है। ये सवाल जब साल 2020 के अगस्त में पूछा गया था तो 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मोदी का नाम लिया था। इस साल के जनवरी में ऐसा कहने वालों की तादाद घटकर 38 प्रतिशत पर पहुंची और इस साल के अगस्त में मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखने वालों की संख्या सरककर 24 फीसदी पर जा पहुंची है। ओपिनियन पोल करने में बिताए अपने बीसेक बरसों में, कभी ऐसा होते नहीं देखा गया कि किसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस तेजी से घटी हो। सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग 74 प्रतिशत से कम होकर 54 प्रतिशत पर आ गई है। अब इसमें कोई शक नहीं कि मोदी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से बाकियों की तुलना में दौड़ में दोगुना आगे हैं लेकिन अब ये फासला इतना नहीं रहा कि उसे पाटा ही नहीं जा सके। अगर बंगाल के चुनाव से ये जाहिर हुआ था कि मोदी की लोकप्रियता को भुनाकर राज्य के चुनाव नहीं जीते जा सकते तो ओपिनियन पोल के इस चरण से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ही सवालों के घेरे में आ गई है।

लोकप्रियता के घटने की वजह क्या हो सकती है? वह वजह तो नहीं ही है जो मोदी-आलोचक चाहेंगे कि हो। मोदी की लोकप्रियता के घटने की वजह ये नहीं कि सेक्युलरिज्म, संघवाद या लोकतंत्र पर हमला हुआ है। सच तो ये है कि धारा 370 को हटता देखना चाहने वाले और अयोध्या को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पसंद करने वालों की तादात बीते एक साल में बढ़ी ही है। हां, सरकार जो लोकतांत्रिक अभिव्यक्तियों पर लगाम कस रही है, उसे लेकर लोगों में बेचैनी शुरू हुई है। सर्वे के केवल 40 फीसदी उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें विरोध करने की आजादी है जबकि 51 प्रतिशत ऐसा नहीं मानते। लोकतंत्र खतरे में है- ऐसा सोचने वालों की तादात कमोबेश उतनी ही है जितनी कि इससे असहमति जताने वाले लोगों

विपक्ष में दमदार चेहरा नहीं

अगर सर्वे के ये निष्कर्ष प्रधानमंत्री के लिए ठहरकर सोचने का इशारा हैं तो विपक्ष के लिए भी। वजह ये कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में तो अच्छी-खासी कमी आई है लेकिन इसकी तुलना में विपक्ष के किसी नेता की लोकप्रियता में नाटकीय ढंग से इजाफा नहीं हुआ है। अगर आप सोनिया-राहुल और प्रियंका गांधी को कोई एक हस्ती मानकर चलें तो भी नजर यही आता है कि उनकी रेटिंग (साख) एक साल के भीतर 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत पर पहुंची है। अगर 2019 के चुनावों से तुलना करें इस ओपनियन पोल में एनडीए के वोट शेयर में 5 प्रतिशत की कमी आई है लेकिन कांग्रेस के खाते में कुछ हासिल नहीं हुआ। नेता और पार्टी दोनों ही के लिहाज से जो भी बढ़त हासिल हुई है वह पूरे विपक्षी खेमे में के अलग-अलग हिस्सों के बीच बंटी दिखती है।

नाउम्मीदी का आलम

लोगों में मोदी सरकार को लेकर अगर बेचैनी बढ़ रही है तो उसकी असली वजह है आर्थिक संकट जो महामारी के शुरू होने के तुरंत पहले से लेकर महामारी के दौरान और महामारी के उतार के बाद भी जारी है। कुछ आंकड़े तो पहले से ही बता रहे हैं और उन आंकड़ों में इस सर्वे के तथ्यों से ये बताने वाले साक्ष्यों में इजाफा हुआ है कि लोग नौकरियां ही नहीं गंवा रहे बल्कि उनकी आस भी टूट रही है। सर्वे के 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके परिवार ने जीविका का साधन गंवाया है या फिर उनकी आमदनी घटी है। सर्वे के केवल 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आगे के दिनों में उनके परिवार की आमदनी बढ़ सकती है जबकि 34 फीसदी उत्तरदाताओं का कहना है कि भविष्य में उनके परिवार की आमदनी और भी कम होगी। छह माह पहले देश के आर्थिक भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया था तो आशावादियों की संख्या निराशावादियों की तुलना में दोगुना थी। लेकिन अब निराशावादियों की संख्या आशावादियों से ज्यादा हो गई है। अपनी आर्थिक दशा को लेकर लोगों में जो नकारात्मक धारणा पैठ बना रही है, उसकी छाया के दायरे में मोदी सरकार के पूरे सात साल हैं। सर्वे में जितने उत्तरदाताओं ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी आर्थिक दशा बिगड़ी है लगभग उतनी ही तादात यह कहने वालों की है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी आर्थिक दशा सुधरी है।

की। सर्वे के 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि हां, लोकतंत्र खतरे में है जबकि 47 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते। हमें इस रुझान पर बेशक नजर रखनी चाहिए लेकिन जहां तक अभी के वक्त का सवाल है, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि लोकतंत्र को खतरे में मानने के कारण लोगों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है।

लचर और हद दर्जे की नुकसानदेह साबित हो रही विदेश नीति, जिसमें लद्दाख की भारत-चीन सीमा पर पलटबाजी करना शामिल है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के घटने की वजह नहीं। चीन के सीमा-अतिक्रमण को मोदी सरकार ने अच्छे से निपटाया, ऐसा मानने वालों की तादात उन लोगों की तुलना में लगभग दोगुनी है जो मानते हैं कि सीमा-अतिक्रमण का निपटारा मोदी सरकार ने खराब या फिर बहुत खराब तरीके से किया। जाहिर है, सरकार ने अपने प्रचार-तंत्र के जरिए बड़ी कामयाबी से लोगों के बीच एक झूठ को फैलाया है। कम से कम अभी तक तो ये झूठ अपना काम करता दिख रहा है। लेकिन कोविड से निपटारे को लेकर सरकार का जो रुख रहा, वह एक अलग ही कहानी बयान करता है। अब सच्चाई को छिपाने के लिए सरकार चाहे जितना जोर लगा ले लेकिन जिन लोगों ने अपने प्रियजन को मरते देखा और महामारी की चोट अपने दिल पर सहा है, उनके अनुभवों को झुठलाया नहीं जा सकता। अचरज नहीं कि सर्वे के 71 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि कोरोना महामारी से मरने वालों की तादात सरकार के बताए आंकड़े से कहीं ज्यादा है। इसका दोष देने के मामले में भी उत्तरदाताओं की इमानदारी झलकती है। कुल 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को कोविड से निपटारे में हुए गड़बड़झाले के लिए दोषी माना है जबकि केवल 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके लिए अकेले केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया और 10 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो सिर्फ राज्य सरकार को दोषी मानते हैं। इनका ये भी कहना है कि विपक्ष ने महामारी के दौरान गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव किया। फिर भी, सर्वे के इन तथ्यों के आधार पर इतना तो मानना ही होगा कि कोविड महामारी से निपटारे को लेकर प्रधानमंत्री का जो रवैया रहा उसके बारे में लोगों में बीते एक साल में नकारात्मक धारणा बनी है। अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लोग कहने लगे हैं कि कोविड महामारी और इस महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने में मोदी सरकार लचर या फिर बहुत ज्यादा लचर साबित हुई बनिस्बत उन लोगों के जो अब भी कहते हैं कि कोविड ये कोविड के कारण पैदा आर्थिक संकट से उबारने के लिए मोदी सरकार ने क्या खूब काम किया।

लोगों में व्याप्त ना-उम्मीदी की इस दशा के कारणों की पड़ताल करने पर दो बातें नजर आती हैं। इसमें पहला है कीमतों में इजाफा। अब यहां दो चीजों यानि लोग जिसे महंगाई कहते हैं और अर्थशास्त्री जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं, उसको एक मानकर चलने की जरूरत नहीं। अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर देखें तो देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है लेकिन बढ़वार के बावजूद वह अब भी 6 फीसदी के आसपास है मतलब इसे बुरा कहा जाएगा लेकिन बहुत बुरा नहीं। लेकिन जब लोग महंगाई कहते हैं तो अक्सर उनका आशय चीजों की खरीदारी की क्षमता के घटने यानि तुलनात्मक रूप से अपनी गरीबी के बढ़ने से होता है। आश्चर्य नहीं कि सर्वे के पिछले तीन चरणों से लगातार ये तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि ये सरकार मंहगाई रोकने के मोर्चे पर नाकाम हुई है। दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी। अभी 59 प्रतिशत लोगों का मानना है कि जीविका की हानि उनकी सबसे बड़ी चिंता है।

क्या लोग इन आर्थिक समस्याओं के लिए मोदी सरकार को दोषी मानते हैं? हां, इस सर्वे से ये उत्तर जाहिर होता है। सर्वे के 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार ने महंगाई (मतलब लोगों की गरीबी) रोकने के लिए कुछ खास जोर नहीं लगाया। अर्थव्यवस्था को चलाने का जो राह-रवैया सरकार ने अपना रखा है उसे लेकर लोगों में नकारात्मक धारणा बन रही है। मोदी सरकार के लिए इससे भी बुरी खबर ये है कि ऐसे लोगों की तादात अब बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई है जो मानते हैं कि इस सरकार की आर्थिक नीतियों से सिर्फ बड़े व्यापारियों को फायदा हो रहा है। मतलब सरकार में 'हम दो' और व्यापार में 'हमारे दो' की सच्चाई अब लोग समझने लगे हैं।

● **इन्द्र कुमार**

कांग्रेस का हाल इस समय ऐसा हो गया है कि मजबूत स्थिति वाले राज्यों को हाथ के पंजे की पांच उंगलियों पर गिना जा सकता है। अन्य राज्यों में पार्टी के नेता तेजी से भाजपा सहित दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। वहीं, राज्यों में छोटी-बड़ी टूट पर कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नजर नहीं आती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को लगातार दो बार केंद्र की सत्ता से बाहर रहने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन, राज्यों में पार्टी अपनी आंतरिक गुटबाजी और आलाकमान के फैसलों में देरी की वजह से कमजोर होती जा रही है।

बनने से पहले बिखर रही टीम राहुल...

बीते करीब दो साल देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं गुजरे हैं। और, फिलहाल जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, ऐसा लगने लगा है कि भविष्य में भी उसकी दशा सुधरने वाली नहीं है। दरअसल, बीते कुछ समय में कांग्रेस से युवा नेताओं की रवानगी में काफी तेजी आई है। इसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात ये रही है कि इन सभी नेताओं को परंपरागत कांग्रेसी माना जाता रहा है। हिमंता बिस्व सरमा को छोड़ दिया जाए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे बड़े नाम वाले नेताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की ही रही है। इसी क्रम में अब एक नाम और जुड़ गया है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिलचर से पूर्व सांसद सुष्मिता देव का। उन्होंने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके पिता भी पुराने कांग्रेसी और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते समय इस बात पर जोर दिया कि वो पार्टी से नाराज नहीं हैं। लेकिन, अगर वो नाराज नहीं थीं, तो कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या रही, इस पर उन्होंने कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। लेकिन, बीते दो सालों में युवा नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के सिलसिले में तेजी आई है और ये कहीं न कहीं पार्टी के साथ ही गांधी परिवार के लिए भी खतरे की घंटी है।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष नेता ही कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हों। पार्टी से महिला कांग्रेस नेताओं की रवानगी भी काफी बढ़ी है। पूर्व लोकसभा सदस्य सुष्मिता देव की कांग्रेस से विदाई पर शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ होगा। पार्टी छोड़कर जाने वाले युवा नेताओं की बढ़ती सूची में यह जो नया नाम जुड़ा है वह इस स्वीकृत सच्चाई का एक और प्रमाण है कि भारत की 'ग्रैंड ओल्ड पार्टी' तूफान के आगे ताश के पत्तों के महल की तरह ढह और बिखर रही है।

प्रियंका चतुर्वेदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रद्योत माणिक्य देववर्मा, जितिन प्रसाद के बाद पार्टी छोड़ने वालों में नया नाम सुष्मिता देव का जुड़ गया है। वे 'बिना कोई सैद्धांतिक समझौता किए' तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उधर, चिर असंतुष्ट सचिन पाइलट, अनिश्चित दीपेंदर हुड्डा और रहस्यमय मिलिंद देवड़ा भी हैं, और ये सब इसी धारणा को मजबूत कर रहे हैं कि कांग्रेस भारी संकट में है। इनका कथित असंतोष एक गहरे ढर्रे को उजागर करता है। ये सब उस नई टीम के तेज-तर्रार, सुलझे हुए नेता माने जाते थे, जिसे राहुल गांधी तैयार कर रहे थे। लेकिन पार्टी से उनका मोहभंग कांग्रेस के भविष्य के बारे में अलग ही कहानी कहता है, एक युवा कांग्रेस के सपने के टूटने की कहानी।

सब्र और वफादारी जैसे गुणों को राजनीति में बेशक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व इन महत्वाकांक्षी युवाओं की उम्मीदों और अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में जिस तरह अक्षम साबित हो रहा है उसके बारे में भी कुछ कहना पड़ेगा। ये युवा नेता सत्ता से दूर रहकर थक चुके हैं और अपनी उंगलियां चटखाते हुए यही इंतजार कर रहे हैं कि राहुल कब कमान संभालते हैं। असम के लोकप्रिय नेता रहे संतोष मोहन देव की बेटी और राज्य की प्रखर आवाज मानी गईं सुष्मिता देव ने उस पार्टी से, जिसके प्रति उनका परिवार काफी वफादार रहा, संबंध क्यों तोड़ा इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं दूसरे कई नेताओं की तरह सुष्मिता भी इंतजार करते-करते सब्र खो चुकी थीं, जबकि उनके राज्य और देश में पार्टी एक के बाद एक चुनाव में बुरा प्रदर्शन कर रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे नागरिकता

राहुल का डरपोक नेताओं के लिए स्पष्ट संदेश

राहुल गांधी ने बीते महीने ही कांग्रेस के डरपोक नेताओं को पार्टी से बाहर जाने का आदेश दे दिया था। दरअसल, राहुल गांधी ने पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देने वालों को सीधे बाहर निकलने को कह दिया था। राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा में बदलाव के समर्थक नजर नहीं आते हैं। उनके इस बयान से तो मतलब यही निकलता है। कांग्रेस की विचारधारा की बात करें, तो आज के हिसाब से ये धारा 370, राम मंदिर, नरेंद्र मोदी के विरोध और हिंदुत्व जैसे मुद्दों को साइडलाइन कर सेकुलर रहते हुए सत्ता की ओर बढ़ने की है। लेकिन, राज्य स्तर पर कई बार ये चीजें ठीक उलट हो जाती हैं। इन मुद्दों पर राहुल गांधी जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रहे हैं। राहुल गांधी का ये बेबाक संदेश कांग्रेस के असंतुष्ट जी-23 नेताओं के लिए भी है और भविष्य को आशंकित नेताओं के लिए भी। इस स्थिति पर विचार करें, तो सामने आता है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का मामला जल्दी नहीं सुलझा, तो सचिन पायलट को भाजपा हिमंता बिस्व सरमा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। दरअसल, राहुल गांधी के साथ मूल समस्या ये है कि जिन मुद्दों का वो विरोध कर कांग्रेस को पाक साफ जताने की कोशिश कर रहे हैं।

संशोधन कानून (सीएए) पर कांग्रेस के रुख के कारण अपने पारिवारिक गढ़ और चुनाव क्षेत्र से हार गईं। बराक घाटी में उनके क्षेत्र में बंगालियों का बहुमत है। इस साल के शुरू में विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में उम्मीदवारों के चयन में उनसे सलाह-मशविरा नहीं किया गया, जिससे भी वे नाराज थीं। इसके अलावा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा था। इसलिए, कांग्रेस छोड़ने वाले दूसरे नेताओं की तरह उनके सामने भी यही सवाल मुंह बाये खड़ा था कि 'अब मेरे लिए क्या है?'

यह सवाल उन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है, जो पार्टी के अंदर कथित 'बागी गुट' जी-23 के सदस्य माने जाते हैं, क्योंकि सक्रिय राजनीति में उनका समय लगभग पूरा हो चला है। लेकिन युवा तुर्कों (जिनमें से अधिकतर 'कांग्रेस परिवार' से हैं) का पार्टी छोड़ना बड़े संकट का संकेत है। यह पीढ़ी पार्टी का वर्तमान भी है और भविष्य भी। जबकि इस पीढ़ी के प्रमुख चेहरे बाहर निकल चुके हैं, पहले से ही भविष्य को लेकर अनिश्चित कांग्रेस की हालत और बुरी नजर आती है।

इस मोहभंग और पलायन की जड़ में है कांग्रेस के धूमिल भविष्य और पार्टी के कई नेताओं में उपेक्षित किए जाने के एहसास के मद्देनजर अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता। सिंधिया, सुष्मिता, प्रसाद और दूसरे नेताओं को वरदान के रूप में मिली विरासत के चलते राजनीति में सीढ़ियां चढ़ने में बेशक आसानी हुई, लेकिन राजनीति जितना जनसेवा का काम है उतना चुनाव जीतने और सत्ता हासिल करने का भी है। इन तमाम नेताओं को लगता है कि अगर विपक्ष में ही बने रहना है और अपनी पार्टी में भी कोई सत्ता नहीं मिलनी है तो राजनीति में होने का मतलब क्या है। 'पलायन' करने वालों में से कोई भी बोझ नहीं है। वे सब चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले स्पष्टवादी नेता हैं और संकट में पड़ी पार्टी के प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण चेहरे हैं।

कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या यह नहीं है कि आज वह सत्ता से बाहर है, बल्कि यह है कि वह गहरे से गहरे गर्त में फिसलती जा रही है और उबरने के कोई संकेत नहीं हैं। यह तथ्य पार्टी के युवा, तेज-तर्रार, महत्वाकांक्षी नेताओं को अच्छी तरह पता है। फिर भी, सुष्मिता का दलबदल अपने कुनबे को संभालने और प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने की पार्टी नेतृत्व की अक्षमता को ही उजागर करता है। गांधी परिवार अपनी आत्ममुग्धता के चलते इन पलायनों को अपनी इस धारणा की पुष्टि मानता है कि उन लोगों में नैतिकता की कमी है। इसी वजह से यह परिवार अपने भीतर नहीं झांक पाता और यह विचार नहीं कर पाता कि आखिर गलत क्या हो रहा है। इन अहम पलायनों के साथ, राहुल की कांग्रेस बनने से पहले ही बिखर रही है। कांग्रेस के पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया में उसके कुछ अहम खंभे लापता हैं। बचे रह गए हैं 'ओल्ड गार्ड', जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति का मुकाबला करने की क्षमता या रणनीति से वंचित नजर आते हैं। आज हकीकत यह है कि तीन साल बाद ये तीनों पार्टी में नहीं हैं, और यह बहुत कुछ कहता है। फिर भी, कांग्रेस आलाकमान ऐसे काम कर रहा है मानो असली चीज सिर्फ यह है कि पार्टी में हर कोई परिवार के प्रति वफादारी की कसम खा रहा है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि पार्टी ने 'अपनी आंखें पूरी तरह बंद' कर रखी हैं। दुर्भाग्य से, हालत इससे भी बुरी है। कांग्रेस 'सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा' वाले खतरनाक और फिसलन भरे सोच की गिरफ्त में फंसी हुई है।

किसी समय राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के युवा तुर्क नेताओं में गिने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जैसे नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर अटकलें लगना शुरू हो गई थीं कि अब अगला नंबर किसका होगा? दरअसल, सिंधिया और प्रसाद के अलावा राहुल गांधी की पसंदीदा चौकड़ी में शामिल सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा भी लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष नेता ही कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हों। पार्टी से महिला कांग्रेस नेताओं की रवानगी भी काफी बढ़ी है। कांग्रेस की पूर्व कद्दावर महिला नेता रीता बहुगुणा जोशी भी पार्टी का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गई थीं। रीता बहुगुणा जोशी फिलहाल प्रयागराज से भाजपा सांसद हैं। करीब 10 सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी प्रवक्ता रहीं प्रियंका चतुर्वेदी भी शिवसेना के खेमे में शामिल हो गई थीं। शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया। इस लिस्ट में कांग्रेस की पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी राम्या और खुशबू सुंदर का नाम भी शामिल है। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि कांग्रेस में नेता अब प्रसाद पॉलिटिक्स की ओर बढ़ गए हैं। दरअसल, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए तकरीबन सभी नेताओं को किसी न किसी बड़े पद या सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर उपकृत किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और हिमंता बिस्व सरमा इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। कांग्रेस की उपस्थिति भले ही हर राज्य में हो, लेकिन वो लगातार सिमटती जा रही है।

● **रजनीकांत पारे**

फैसले लेने में फिसड्डी

वैसे, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार फैसले लेने की हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहा है। दरअसल, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कहने को तो इस्तीफा दे दिया है। लेकिन, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सभी फैसलों में उनकी छवि नजर आती है। सोनिया गांधी जहां कांग्रेस के असंतुष्ट वरिष्ठ नेताओं के जी-23 गुट को मनाने की कोशिशें कर रही हैं। वहीं, राहुल गांधी उनके खिलाफ कड़े एक्शन के संकेत दे रहे हैं। कपिल सिब्बल भी गांधी परिवार को संदेश देने के लिए अपने घर पर विपक्षी दलों की डिनर पार्टी का आयोजन कर लेते हैं। वैसे, कांग्रेस आलकमान काफी हद तक खुद से ही समस्याओं को बढ़ा रहा है। अब अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से राज्य स्तर पर दो फाड़ की व्यवस्था कर दी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत और विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह के बीच तनातनी अभी से सामने आने लगी है। लेकिन, ऐसी तमाम समस्याओं पर कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से खामोश है।

ढाई साल का फॉर्मूला फेल

छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं, इसका फैसला अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। राहुल गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार टीएस सिंहदेव और राज्य प्रभारी पीएल पुनिया के साथ 3 घंटे बैठक की। गौरतलब है कि सिंहदेव खेमा यह दावा करता है कि राज्य में सरकार गठन के समय उनसे ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। हालांकि बैठक के बाद सभी नेताओं ने नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा से इनकार किया। चर्चा जोरों पर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री के ढाई साल पूरे होते ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है।

ये चर्चा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खेमे की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावे के बाद शुरू हुई। सिंहदेव खेमा ये दावा करता है कि ढाई साल बाद उनको मुख्यमंत्री बनाने का वादा अलाकमान ने किया था। हालांकि, अब तक किसी गुट ने या कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं दिया है। इस मसले को सुलझाने के लिए गत दिनों राहुल गांधी ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और पीएल पुनिया के साथ लगभग 3 घंटे मंथन किया लेकिन किसी फैसले की घोषणा नहीं हुई। बैठक के बाद सभी नेताओं ने छत्तीसगढ़ पर चर्चा की बात कही। बैठक के बाद राज्य प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सभी ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई बल्कि चर्चा का केंद्र छत्तीसगढ़ था। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद पार्टी ने कई विकल्पों पर चर्चा शुरू कर दी है। फैसला सोनिया गांधी लेंगी।

वहीं कांग्रेस आलाकमान ने ढाई साल के फॉर्मूले पर कभी भी कुछ खुलकर बात नहीं की। न ही इस संबंध में कोई भी बयान जारी किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पीएल पुनिया ने इस बात को सिरे से नकारते हुए कहा था कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। ढाई-ढाई साल का कोई फॉर्मूला प्रदेश में नहीं है और न ही लागू किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस संबंध में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई फॉर्मूला है तो उसकी जानकारी या तो दिल्ली को, मुख्यमंत्री को या फिर स्वास्थ्य मंत्री को होगी। उन्होंने कहा कि सभी बातें केवल और केवल कयासों पर ही निर्भर हैं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद के बीच राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो राजनीतिक अस्थिरता की कोशिश कर रहे हैं, वे इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा- मैंने पहले भी कहा था कि उनका (सोनिया गांधी और राहुल गांधी) का जब तक आदेश है मैं इस (मुख्यमंत्री) पद पर हूं। जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। जो ढाई-ढाई साल का राग अलाप रहे हैं, वो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे।

बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद, बघेल की टीम राजनीतिक और प्रशासनिक कदमों के जरिए सिंहदेव को हाशिए पर लाने में जुट गई। पिछले ढाई वर्षों में सियासी मोर्चे पर सिंहदेव के आधार को खत्म करने के कई प्रयास हुए। 2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के 19 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सिंहदेव की थी। कांग्रेस ने सभी 19 सीटों पर जीत दर्ज की और विधायकों को सिंहदेव का वफादार माना जाता था। सिंहदेव के वफादारों में बृहस्पति शामिल थे, अब वे बघेल के वफादार बन गए हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक अन्य विधायक अमरजीत भगत को मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सियासी पंडितों का कहना है कि ऐसा उत्तरी छत्तीसगढ़ में सत्ता का एक और केंद्र बनाने के लिए किया गया है। कहा जाता है कि प्रशासनिक रूप से सिंहदेव को कमजोर करने के लिए बघेल उन्हें अपनी टीम में मनपसंद अधिकारियों को रखने से वंचित करते रहे हैं।

साल 2018 में कांग्रेस 15 साल के इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता में फिर से लौटी थी तो सरकार गठन के दौरान पेच फंसा था। कांग्रेस में उस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भूपेश बघेल के अलावा टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी थे। ऐसे में राहुल गांधी ने तीनों नेताओं को दिल्ली में बुलाकर सत्ता की भागीदारी का फॉर्मूला तय कर दिया और बघेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा मिला। वहीं अब मामले को तूल पकड़ता देख विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। भाजपा के अनुसार ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला कयास नहीं है और ये तय है कि ऐसा निर्णय लिया गया था। भाजपा ने प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार की प्राथमिकता विकास करना नहीं है, इस सरकार की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ नहीं है। इस सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना और कुर्सी बचाना ही है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

समाधान का फॉर्मूला ये हो सकता है

माना जा रहा कि छत्तीसगढ़ के विवाद को सुलझाने के लिए पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। हो सकता है कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए और टीएस सिंहदेव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष या फिर केंद्र में बड़ी भूमिका दी जाए या उनको कुछ और महीने की यथास्थिति के लिए मना लिया जाए। भूपेश बघेल को हटाकर सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और बघेल को केंद्र में लाया जाए। और अगर झगड़ा न निपटे तो दोनों की बजाय राहुल के विश्वासपात्र ताम्रध्वज साहू को राज्य की कमान दे दी जाए यानि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पंजाब, राजस्थान संकट अभी हल भी नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में बवाल शुरू हो गया है। जाहिर है कांग्रेस नेतृत्व के सामने चुनौतियों का पहाड़ है।

राणे महज एक मोहरा

महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा को एक ऐसे नेता की जरूरत थी, जो उद्धव ठाकरे को उनकी ही भाषा में जवाब दे सके। नारायण राणे उस पर खरे उतर रहे हैं।

नारायण राणे भाजपा-शिवसेना के झगड़े में महज एक मोहरा हैं। राणे को केंद्रीय मंत्री बनाकर भाजपा नेतृत्व ने एक सोची समझी चाल चली थी। फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पलटवार में शह देने की कोशिश की है, लेकिन अब ये एक नए खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। नारायण राणे को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और पुलिस हिरासत में 8 घंटे रहने के बाद वो जमानत पर छूट सके वो तमिलनाडु पुलिस के एक्शन रिप्ले जैसा ही लग रहा था। 20 साल पहले जे जयललिता मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ऐसे ही पेश आई थीं। संयोग की बात रही कि 2001 में भी केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार थी और जैसे अभी-अभी राणे शिकार बने हैं, तब वाजपेयी सरकार के दो मंत्री मुरासोली मारन और टीआर बालू की गिरफ्तारी हुई थी, कानून की धाराएं भले ही दोनों मामलों में अलग लगी हों, लेकिन राजनीतिक मंशा तो बिलकुल एक जैसी ही है।

अगर राणे की गिरफ्तारी को हाल के कंगना रनौत प्रकरण और अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के इर्द-गिर्द के राजनीतिक माहौल से जोड़ कर देखें तो ये ऐसी घटनाओं की तीसरी कड़ी लगती है और ये तीनों ही वाकये एक ही तरह के टकराव और उकसावे की राजनीति का नतीजा लगते हैं, जिनके जरिए भाजपा के बिछड़े साथी शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे सबक सिखाने वाले अंदाज में एक खास तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत, अर्णब गोस्वामी और अब नारायण राणे, ये तीनों ही मामले ऐसे हैं जिनको लेकर भाजपा नेता खून का घूंट पीते नजर आए हैं और सीधे-सीधे पल्ला झाड़ते देखे गए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे को लेकर थप्पड़ वाले बयान से पूरी तरह दूरी बनाते हुए खूब सोच समझकर बयान दिया है। भाजपा नेताओं ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार को आड़े हाथों तो लिया है, लेकिन ये भी जोर देकर कहा है कि वो केंद्रीय मंत्री के बयान से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते। थप्पड़ तो नहीं, लेकिन चप्पल और डंडे मारने वाली बातें तो उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी हुई हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं ने ऐसा रिएक्शन तो कभी नहीं दिया, क्या उद्धव ठाकरे से जुड़े मामले भाजपा-शिवसेना के राजनीतिक झगड़े से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत वैमनस्य की परिणति हैं?

महाराष्ट्र के ताजा सियासी समीकरणों की तस्वीर तो तभी साफ हो गई थी जब नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, वो नारायण राणे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। और ये कोई अभी-अभी की बात नहीं है, जब शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने एक बार मनोहर जोशी को हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नारायण राणे को बिठा दिया तब भी उद्धव ठाकरे को कुछ भी हजम नहीं हो पाया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच पड़ताल के दौरान नारायण राणे और और उनके विधायक बेटे नितेश राणे ने जिस तरीके से ठाकरे परिवार को पेग्विन कह कर टारगेट किया, वो तो तकरीबन ताजा घाव ही है।

राजनीति की शुरुआत बतौर शिवसैनिक करने वाले नारायण राणे ने किसी खास राजनीतिक मकसद से ही शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम बनाया होगा, क्योंकि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में सीधे-सीधे तो इसका कोई मतलब बनता नहीं। हो सकता है नारायण राणे ने ये तो बिलकुल नहीं सोचा होगा कि मेमोरियल से उनके निकलते ही शिवसैनिक गोमूत्र का छिड़काव कर उस जगह को पवित्र करने में जुट जाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे को थप्पड़ जड़ देने की बात करते हुए निश्चित तौर पर उनके मन में क्रिया-प्रतिक्रिया जैसी चीजें तो आई ही होंगी। ये ठीक है कि नारायण राणे कांग्रेस से होते हुए भाजपा में पहुंच गए हैं, लेकिन हाव-भाव अब शिवसैनिक वाले ही लगते हैं। शिवसेना नेता रहते नारायण राणे टास्क फोर्स के अगुवा की तरह नजर आते रहे, जो आलाकमान के बयानों को हकीकत का रूप देता नजर आता रहा, और वो भी शिवसेना के पुराने नैसर्गिक अंदाज में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो काफी बदल चुकी है। ये बात अलग है कि रह-रहकर उद्धव ठाकरे के अंदर का शिवसैनिक जाग जाता है और अभी-अभी जो हुआ है, या कुछ पहले जो हुआ, होने लगता है।

उद्धव ठाकरे को लेकर नारायण राणे ने जो कुछ भी कहा था वो भी फिल्म स्टार कंगना रनौत के वीडियो बयान जैसा ही रहा। जैसे तू-तड़ाक करती हुई कंगना रनौत वीडियो में बोल रही थीं, नारायण राणे का लहजा भी मिलता-जुलता ही रहा, 'ये कैसा मुख्यमंत्री है जिसको अपने देश का स्वतंत्रता दिवस पता नहीं... मैं वहां होता तो कान के नीचे थप्पड़ लगा देता।' नारायण राणे खफा थे कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ठाकरे को अपने सेक्रेट्री से पूछना पड़ा कि इस बार डायमंड जुबली है या अमृत महोत्सव?

● **बिन्दु माथुर**

ये ट्रेंड काफी खतरनाक है

हाल फिलहाल महाराष्ट्र में जब भी ऐसा कोई बवाल होता है तो शरद पवार का रुख जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर इसलिए भी क्योंकि यहां तक कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे सरकार का रिमोट एनसीपी नेता अपने पास ही रखते हैं। नारायण राणे को लेकर मचे बवाल पर शरद पवार से सवाल हुआ तो बोले, नारायण राणे अपने संस्कारों के मुताबिक आचरण कर रहे हैं... मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता... मैं इस मुद्दे को कोई महत्व नहीं देता। पवार ने नारायण राणे पर तो अपनी बात कह दी है, लेकिन मुद्दे को महत्व न देने की बात द्विअर्थी है। राणे की गिरफ्तारी का मुद्दा या उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार के एक्शन का मुद्दा?

60 फीसदी वोट का टारेगट

उप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का औपचारिक बिगुल भले ही नहीं बजा हो, लेकिन सभी सियासी दलों ने खुद को चुनावी मोड में सेट कर लिया है। सूबे की सभी पार्टियां 2022 के चुनावी जंग फतह करने के लिए जातीय के बिसात पर अपने सियासी समीकरण सेट करने में जुटे हैं। भाजपा उप्र की सत्ता पर काबिज रहने के लिए 60 फीसदी वोटों को हासिल करने के टारगेट को लेकर चल रही है। ऐसे में आखिर भाजपा के 60 फीसदी वोट में उप्र की कौन-कौन सी जातीय को भाजपा अपना मानकर चल रही है।

भाजपा नेता व उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों कहा था कि उप्र में 100 में से 60 फीसदी वोट हमारा है। बाकी 40 फीसदी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। 40 फीसदी वोटों से क्या मतलब है? इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यह ना समझें कि यादव उनका बंधुवा मजदूर है और मायावती ना समझें कि जाटव उनको ही वोट देगा। यदवंशी और रैदासवंशी भी हमारे (भाजपा) साथ हैं।

केशव मौर्य ने भले ही भाजपा के 60 फीसदी वोट समीकरण के फॉर्मूले को सार्वजनिक न किया हो, लेकिन उन्होंने विपक्ष के 40 फीसदी वोट को जरूर इशारों-इशारों में बता दिया है। माना जा रहा है कि विपक्ष के वोट में उनका इशारा 18 फीसदी मुस्लिम, 10 फीसदी यादव और 12 फीसदी जाटव पर है। इसके अलावा बाकी 18 फीसदी सवर्ण, गैर-जाटव दलित 10 फीसदी और बाकी 32 फीसदी गैर-यादव ओबीसी को अपना वोटबैंक मानकर भाजपा चल रही है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के 40 फीसदी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। यहां बंटवारे का आशय सपा और बसपा के बीच है। यादव सपा का परंपरागत वोट माना जाता है तो जाटव बसपा का कोर वोटबैंक है। इसके अलावा 18 फीसदी मुस्लिम वोटर सपा और बसपा के बीच बंटता रहा है। यह बात इसीलिए भी प्रमाणित हो रही है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उप्र में 50 फीसदी वोट मिले थे जबकि एनडीए को 51 को फीसदी। ऐसे में अगर वो यादव और जाटव समुदाय का कुछ हिस्सा जोड़ने में सफल रहते हैं तो 60 फीसदी का टारगेट आसानी से हासिल हो सकता है। वहीं, दूसरी तरफ देखें तो 2017 के चुनाव में सपा को 22 फीसदी और बसपा को 18 फीसदी वोट मिले थे, जिन्हें मिलाकर 40 फीसदी हो रहा है और इस इसमें से भी वोट मिलने की उम्मीद भाजपा लगा रखी है। हालांकि, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीएसडीएस की रिपोर्ट के मानें तो यादव समुदाय का करीब 27 फीसदी के आसपास वोट भाजपा को मिला है।

दरअसल, भाजपा ने उप्र में तीन यादव समुदाय को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। योगी कैबिनेट में गिरीश यादव मंत्री हैं। केशव ही नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि भाजपा बहुत जल्द ही यादव समुदाय को लेकर एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें यादव समाज के बड़े नेता भाजपा में शामिल होंगे। इससे जाहिर होता है कि भाजपा की नजर अखिलेश यादव के कोर वोटबैंक में भी सेंधमारी करने की है, वहीं, जाटव समुदाय से आने वाले कांता कर्दम को भाजपा ने उप्र में पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया और अशोक जाटव को योगी कैबिनेट में मंत्री के रूप में जगह दे रखी है। इसके अलावा उप्र अनुसूचित जाति आयोग की कमान भी डॉ. रामबाबू हरित को सौंपी गई है, जो जाटव समुदाय से आते हैं। इससे जाहिर होता है कि भाजपा की नजर उप्र में गैर-जाटव दलित के साथ-साथ जाटव वोटबैंक पर भी है।

उप्र में 22 फीसदी दलित मतदाता है, जिसमें 12 फीसदी जाटव और 10 फीसदी गैर-जाटव दलित हैं। 2017 में भाजपा को 85 दलित आरक्षित सीटों में से 69 सीटों पर जीत मिली थी और 39 फीसदी वोट मिले थे, जबकि सपा को इनमें से सात सीटें मिली थीं। बसपा को सिर्फ दो सीटें हीं मिल पाई थी। मोदी सरकार ने उप्र के गैर-जाटव दलित समुदाय के तीन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी है। कौशल किशोर (जाति से पासी), एसपी बघेल (गडेरिया-धनगर) और भानु प्रताप वर्मा (कोरी)- को शामिल किया है, जिसके जरिए 2022 के चुनाव में दलित वोटों का साधने की भाजपा रणनीति है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उप्र के दौरे पर साफ तौर पर पार्टी नेताओं को दलित बस्तियों में जाने और उनकी समस्याओं को हल करने का आदेश दिया है। इससे जाहिर होता है कि भाजपा दलित वोटबैंक को लेकर गंभीरता के काम करना शुरू कर दिया।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

इस समय भाजपा का पूरा फोकस उप्र विधानसभा चुनाव पर है। जानकारों का कहना है कि ओबीसी आरक्षण का मामला इसीलिए उछाला जा रहा है।

उप्र का जातीय समीकरण

बता दें कि उप्र के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो इस राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में सवर्ण जातियां 18 फीसदी हैं, जिसमें ब्राह्मण 10 फीसदी हैं। वहीं, पिछड़े वर्ग की संख्या 40 फीसदी है, जिसमें यादव,10 कुर्मी, सैथवार आठ फीसदी, मल्लाह पांच फीसदी, लोध तीन फीसदी जाट तीन, विश्वकर्मा दो फीसदी, गुर्जर दो फीसदी और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7 फीसदी है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 22 फीसदी हैं और मुस्लिम आबादी 18 फीसदी है। भाजपा यादव को छोड़कर बाकी पिछड़ी जातीय को अपना वोटबैंक मानकर चल रही है। 2014 के चुनाव से ही भाजपा ने उप्र में ओबीसी वोटों को साधने के लिए गैर-यादव ओबीसी को फॉर्मूला बनाया था, जिसे अमित शाह ने और बाद में केशव मौर्य ने 2017 में जमीन पर उतारा था। इसी का नतीजा है कि भाजपा ने गैर-यादव ओबीसी से मौर्य समाज से आने वाले केशव मौर्य को उपमुख्यमंत्री बना रखा है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान कुर्मी समुदाय से आने वाले स्वतंत्रदेव सिंह के हाथ में है। उप्र में सवर्ण वोट भाजपा का कोर वोटबैंक माना जाता है। 18 फीसदी सवर्ण समुदाय से देखे तो मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को सौंप रखी है, जो क्षत्रीय समुदाय से आते हैं और उनकी उप्र में भागेदारी 6 फीसदी के करीब है। ऐसे ही ब्राह्मण समुदाय से आने वाले दिनेश शर्मा को उपमुख्यमंत्री बना रखा है। इस तरह से भाजपा सवर्ण समुदाय के साथ-साथ गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव को अपना वोटबैंक मानकर चल रही है। इसके अलावा सपा के यादव और बसपा के जाटव पर भी उसकी नजर है।

इंतजार खत्म!

राजस्थान कांग्रेस में कलह की सुलह मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ ही होने की संभावना है। 9 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होना है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि सत्र से पहले नए मंत्रियों को भी तैयारी के लिए कम से कम एक हफ्ते का समय तो चाहिए ही, लिहाजा अगस्त के महीने का अंत कांग्रेस की कलह का अंत माना जा रहा है।

राजस्थान में कांग्रेस संगठन और सरकार में होने वाला संभावित फेरबदल सभी की सहमति से हो रहा है। इसका प्रमाण ये है कि ना तो गहलोत और ना ही पायलट कैंप की ओर से कोई बयानबाजी हो रही है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहले ही कह चुके हैं कि इस शांति का श्रेय तो पार्टी के आलाकमान को दिया जाना चाहिए। सरकार और संगठन में होने वाले संभावित बदलाव में दोनों खेमों, वर्गों, जातियों और क्षेत्रों के हितों, संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाएगा। क्योंकि किसी को खुश करने के लिए किसी के साथ अत्याचार नहीं किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल का शपथग्रहण समारोह सितंबर में कभी भी करवाया जा सकता है। इसमें अगर पंचायत चुनाव को ध्यान में रखा गया तो संभवत: 1 सितंबर के बाद ही शपथ ग्रहण होना तय माना जा रहा है। विधानसभा सत्र को देखते हुए मंत्रियों को विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए कम से कम 7 दिन का समय तो दिया ही जाएगा। वरना बिना तैयारी के अगर मंत्री विधानसभा सत्र में उतरेंगे तो उनकी और सरकार की **फजीहत होना तय माना जा रहा है।** अब इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो शपथग्रहण समारोह विधानसभा सत्र के बाद तक टलना तय है। क्योंकि बीच सत्र में मंत्रिमंडल पुनर्गठन करना रणनीतिक मायनों में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। हालांकि इसकी संभावना .1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है।

सूत्रों की मानें और मंत्रिमंडल पुनर्गठन की बात करें तो मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच सहमति होने की खबर है। पायलट खेमे के 4 सिपहसालारों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह दी जाना तय माना जा रहा है। इसके बाद क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के आधार पर मंत्री बनाए जाने हैं। एक सूत्र का तो कहना है कि हो सकता है किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाए और लेकिन खाली सीटों पर ही मंत्री बनाए जाएं। इसके बाद पायलट कैंप के अन्य विधायकों और समर्थकों को संगठन, निगम, और बोर्डों की राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जाएगा। जैसा कि सचिन पायलट हमेशा कहते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं उन्हें सम्मान दिया जाए। पायलट की इस मांग को आलाकमान और मुख्यमंत्री गहलोत ने जायज मानते हुए उन्हें सम्मान देने का निर्णय कर लिया है। वहीं बात कि जाए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर भी दो फॉर्मूले तय किए गए हैं। पहला तो यह है कि पायलट को फिर से पीसीसी की कमान सौंप दी जाए और यहीं उनके लिए सम्मानजनक पद भी माना जा रहा है। क्योंकि इसके बाद सभी विधायकों पर पायलट की पकड़ बढ़ेगी साथ ही पदाधिकारियों की जिम्मेदारी वो अपने हिसाब से तय कर सकेंगे। ये फॉर्मूला आलाकमान पंजाब में लागू कर चुका है। काफी कश्मकश के बाद पंजाब में सत्ता और संगठन में तालमेल बैठता दिख रहा है। वहीं दूसरा फॉर्मूला यह है कि पायलट को दिल्ली केंद्रीय संगठन में महासचिव बनाकर गुजरात का प्रभार दिया जाए। क्योंकि गुजरात में जल्द ही चुनाव होने हैं और इस राज्य में कांग्रेस को संभावनाएं दिख रही है। ऐसे हालात में गुजरात में किसी दमदार प्रभारी को भेज आलाकमान अपनी जीत को तय करना चाहता है। सचिन पायलट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अपनी भूमिका तय करने का अधिकार उन्होंने आलाकमान को दे रखा है। आलाकमान जो भी भूमिका तय करेगा वो पायलट को मंजूर होगी।

इधर पीसीसी में भी बदलाव तय माना जा रहा है। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बनाया जाता है तो वो अपनी टीम अपने हिसाब से मुख्यमंत्री गहलोत कैंप के साथ मिलकर बना ही लेंगे। अगर पायलट पीसीसी चीफ नहीं बनते हैं तो राजस्थान में 1+4 का फॉर्मूला जो की पंजाब और उत्तराखंड में लागू किया गया है वो आजमाया जाना तय है। अगर 1+4 फॉर्मूला तय होता है तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और पूर्व चिकित्सा मंत्री दुरू मियां को मिल सकता है कार्यकारी अध्यक्ष का पद, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष बने रह सकते हैं। साथ ही दो चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। जिसमें एक महिला नेत्री जो मीडिया सेल की जिम्मेदारी निभाती रही हैं उनका नाम प्रायोरिटी पर है। वहीं एक नाम आदिवासी इलाके से भी आ सकता है। ये नेता पहले सांसद रह चुके हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

जादूगर के गढ़ में पायलट का शक्ति प्रदर्शन

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने मारवाड़ में शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री गहलोत के गढ़ जोधपुर में पायलट के पहुंचने पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्पण को देख पायलट अभिभूत नजर आए। पायलट अपने खास सिपहसालार और वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक हेमाराम चौधरी के गांव बालोतरा पहुंचे और उनके भाई के निधन पर शोक जताया। इसके बाद पायलट आसोतरा गए और ब्रह्मधाम आसोतर मंदिर में शीश नवाया। पायलट के मारवाड़ दौरे पर उनके स्वागत के लिए उमड़े जनसैलाब को देख सभी चकित हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक ने तो टिप्पणी की- लोकप्रियता के लिए पद की जरुरत नहीं है। वहीं पायलट को पूर्वी राजस्थान का नेता मानने वालों के लिए भी यह मैसेज है। इससे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पायलट के एयरपोर्ट से बाहर आते ही समर्थकों में स्वागत को लेकर होड़ मच गई, जिससे एक बारगी धक्कामुक्की जैसी नौबत भी हो गई। जोधपुर एयरपोर्ट पर हुए पायलट के स्वागत में गहलोत कैंप का कोई नेता नहीं पहुंचा था। जोधपुर में पायलट की अगवानी उनके समर्थक माने जाने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने की।

जातीय जनगणना सियासी शस्त्र

जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अब यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं। जहां तक देश में जनगणना की बात है तो यह एक औपनिवेशिक देन है। जब अंग्रेजी उपनिवेशवाद ने भारत में सत्ता स्थापित की तो 'जिन्हें शासित करना है, उन्हें जानो' की अपनी नीति के तहत उसने पहली बार भारत में एक वृहत जनगणना की परियोजना प्रारंभ की। जनगणना, आंकड़े, अभिलेख और कठोर नियंत्रण के माध्यम से ही ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने आधिपत्य को मजबूत किया। इसी के तहत उन्होंने जातीय जनगणना भी शुरू की। जब अंग्रेजी शासन ने भारत में जातीय जनगणना की परंपरा प्रारंभ की तो अपनी जातीय अवस्थिति को कुछ ने ऊंचा करना चाहा तो कुछ ने उनके ऊंचा करने के प्रयास का विरोध भी किया। फलतः समाज में जातीय अवस्थिति को लेकर तनाव, टकराव, हिंसा और मुकदमे होने लगे। आगे चलकर अंग्रेजों ने 'जातीय जनगणना' को विभिन्न कारणों से बंद कर दिया। फिर अनुसूचित जाति जैसी अनेक दमित जातियों की सामाजिक कोटि बनाई।

देश में बिहार और उप्र दो ऐसे राज्य हैं, जहां जातिवाद चरम पर रहता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इसका खूब फायदा उठाती हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश में अब जातीय जनगणना की मांग उठ रही है।

यह जानना रोचक है कि भारत में अंग्रेजी जनगणना प्रारंभ होने के पहले जातीय अवस्थिति में गतिशीलता पाई गई थी। अनेक इतिहासकारों ने अपने शोध में यह पाया कि जनगणना में एक बार दर्ज हो जाने पर लोगों की जातीय अवस्थिति जड़ एवं रूढ़ हो गई। अर्थात् अब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं रहा। उसके पूर्व भारत में जातीय अवस्थिति कई बार गतिशील होती दिखाई पड़ी थी, किंतु इसी औपनिवेशिक जनगणना ने हमें वे आंकड़े दिए, जो आज जनतंत्र में हमारी हिस्सेदारी की चाह को निर्मित करते हैं। ये आंकड़े आज भी चुनावी गोलबंदी में प्रयोग किए जाते हैं।

यहां हम भारत में जनगणना के इतिहास को इसलिए याद कर रहे हैं, क्योंकि अतीत हमें वर्तमान में क्या करें, क्या न करें की सीख भी देता है। कोई भी जनगणना सत्ता एवं शासन को वह आंकड़े देती है, जिसके आधार पर विकास की नीतियां बनाने में हमें मदद मिलती है, लेकिन क्या आज के संदर्भ में जातीय आंकड़े हमें नीतियां बनाने में मदद कर पाएंगे? भारत में करीब 3,000 जातियां एवं उपजातियां हैं। जनतांत्रिक स्रोतों एवं विकास योजनाओं का समायोजन इतनी बड़ी जातीय इकाइयों में कैसे संभव है? फिर तो अगड़ी जातियों, ओबीसी एवं अनुसूचित जातियों की गणना ही शायद इस जटिलता का समाधान कर पाए।

यह ठीक है कि जाति आधारित जनगणना के आधार पर देश में जनतांत्रिक चुनावी अवसरों एवं विकास परक योजनाओं का वितरण संख्या बल के आधार पर करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन यहां कुछ नैतिक प्रश्न भी खड़े होते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिल भी गई तो जिनकी संख्या कम है, उनका क्या होगा? कोटियों में विभाजित सामाजिक समूहों में जो कुछ जातियां ज्यादा सक्षम हो चुकी हैं, वे उसी समूह की अन्य जातियों के अवसरों पर क्या पूर्व की तरह कब्जा नहीं करती रहेंगी? हम जानते हैं कि आज सामाजिक कोटियों में अनेक जातियां हैं, जिन तक जनतांत्रिक लाभ उन्हीं कोटियों की प्रभावी जातियों की तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं।

संभव है कि जातीय जनगणना अति उपेक्षित एवं अति पिछड़े समूहों का संख्या बल एवं अन्य आंकड़े हमें प्रदान करेगी, जिनसे हम उनके तुलनात्मक पिछड़ेपन अथवा विकास को समझ पाएंगे। हालांकि यह तभी संभव है जब जनगणना की दिशा एवं दृष्टि में सामाजिक-आर्थिक अवस्थिति पर आधारित प्रश्नों को ज्यादा महत्व मिले। यह महत्व न केवल जनगणना के वक्त, बल्कि उसकी व्याख्या करते समय भी दिया जाए। ऐसा न हो कि बस संख्या बल के आधार पर चुनावी जनतंत्र एवं सत्ता की शक्ति के वितरण में ही अपनी हिस्सेदारी का दावा किया जाए। यह ध्यान ही न दें कि संख्या बढ़ने या घटने के साथ ही सशक्तीकरण एवं विकास की प्रक्रिया कितनी बढ़ी या घटी है। भारतीय जनतंत्र से अपेक्षा की गई थी कि उसके प्रसार के बाद देश में जाति भाव कमजोर होगा। डॉ. अंबेडकर ने जाति उन्मूलन का स्वप्न देखा ही था, किंतु ऐसा हम सबने लगातार महसूस किया है कि जहां आधुनिकता कई अर्थों में हमारी जातीय जकड़न को कमजोर करती रही है, वहीं चुनावी जनतंत्र के विमर्श 'जातीय बोध' को बढ़ाते रहे हैं।

● **विनोद बक्सरी**

सामाजिक न्याय के संतुलित वितरण का माध्यम बने

कुछ राजनीतिज्ञ मान रहे हैं कि जातीय जनगणना से भारत में समरसता आएगी, लेकिन गहरे अर्थों में देखें तो इतनी बड़ी संख्या में जातियों को जातीय इकाई के आधार पर संतुलित विकास एवं हिस्सेदारी देना आसान नहीं होगा। अगर कोई जनगणना संख्या बल के साथ ही सामाजिक-आर्थिक अवस्थिति एवं विकास के स्रोतों का आंकलन करती है तो वह हमें अपने गवर्नेंस को समावेशी बनाने में मदद करेगी। वहीं यदि हम मात्र संख्या ही गिनने में लिप्त रहेंगे और उसके समाजशास्त्र को विमर्श में नहीं लाएंगे तो संख्या का सियासी खेल समाज में भयानक असंतुलन को जन्म देगा, जिसे साधना हमारे लिए कठिन होगा। बहरहाल जाति आधारित जनगणना अगर होती भी है तो इसे सामाजिक न्याय के संतुलित वितरण का माध्यम बनाना चाहिए। हमें इसे ऐसे उपादान में बदलना चाहिए कि यह समाज के अनेक इकाइयों में विभाजन के रहते हुए भी इनमें संतुलित एवं सम्मानजनक संबंध विकसित करने में हमारी मदद कर सके। ऐसी जनगणना ही हमारे शासन, देश एवं समाज में सही अर्थों में जनतांत्रिक मूल्यों के प्रसार में सहयोगी हो सकेगी।

चीन का नया दांव

भारत-चीन सीमा पर तनाव अभी खत्म नहीं

लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद भी अभी तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई पीछे हटने को लेकर कोई सर्वसम्मत समझौता नहीं हुआ है। इसका असर दोनों देशों के सामरिक और आर्थिक संबंधों पर भी पड़ा है। अरुणाचल के पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन, उत्तर पूर्व में तिब्बत और पूर्व में म्यांमार है। अब इन क्षेत्रों में भारत की सामरिक स्थिति बहुत मजबूत है। भारत अपनी पूरब की नीति के तहत सीमाई क्षेत्रों का व्यापक विकास कार्य कर रहा है। चीन की चिंता का एक कारण यह भी है। जाहिर है, जिनपिंग तिब्बत की धरती से दलाई लामा, भारत और अमेरिका पर दबाव बढ़ा कर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। सीमा समस्या को लंबे समय तक उलझाकर चीन का विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका रहा है और जिनपिंग भी इसे आजमाते नजर आ रहे हैं।

तिब्बत पर कब्जे के सात दशक बाद भी चीन की उस पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं हो पाई है, जितना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। इसी कारण जिनपिंग प्रशासन अब तिब्बत में धर्म का कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बहुलता है, जबकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती है। इसलिए यहां के लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए जिनपिंग अपना उदार चेहरा दिखाने चाहते हैं। तिब्बत को चीन ने 1951 में अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने अनुयायियों के साथ भारत में शरण ले ली थी। तब से वे भारत में ही रहते हैं और तिब्बत को स्वायत्ता देने के लिए चीन की सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। दलाई लामा के प्रभाव को तिब्बत के लोगों में कम करने के लिए चीनी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

चीन तिब्बत की धार्मिक संस्कृति को खत्म कर उसे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए व्यापक योजनाओं पर काम कर रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि दलाई लामा की बढ़ती उम्र को आधार बनाकर चीन अपनी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति को दलाई लामा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठावान हो। अमेरिका ने चीन की इस नीति का विरोध किया है। पिछले साल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई तिब्बत नीति को मंजूरी देते हुए बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के चयन में चीनी हस्तक्षेप को रोकने की बात कही थी। इसमें तिब्बत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने और तिब्बत मसले पर एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात की गई थी। इस साल मार्च में बाइडेन प्रशासन ने भी इस अमेरिकी प्रतिबद्धता को दोहराया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीनी सरकार का कोई हाथ नहीं होना चाहिए।

तिब्बत सामरिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस मार्ग का उपयोग नेपाल से रिश्ते मजबूत करने के लिए कर रहा है। तिब्बत यात्रा में जिनपिंग न्यिंग्ची रेलवे स्टेशन भी गए। इसे उनकी भारत पर सामरिक दबाव बनाने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। यह इलाका सामरिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से कुछ दूर पर ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। जिनपिंग चीन के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने कई दशकों बाद भारत और चीन की सीमा के पास बसे इस शहर का दौरा किया है। गौरतलब है कि ब्रिटिश राज में 1914 में बनी मैकमोहन रेखा को खारिज कर चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद बदलते राजनीतिक परिदृश्य में ब्रिटेन की दक्षिण एशिया से बिदाई के बाद माओ ने इस इलाके को कब्जे में लेने की साजिश को बेहद चुपके से अंजाम दिया था। माओ ने सबसे पहले 1949 में तिब्बत को अपना निशाना बनाया। चीन ने भारत से लगती सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत की और 1957 में कराकोरम राजमार्ग भी बना लिया। इसके बाद चीन ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा भी कर दी कि भारत और चीन सीमा का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ है। चीन ने मैकमोहन रेखा को भी मानने से इंकार कर दिया और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताने लगा। चीन अरुणाचल प्रदेश के नब्बे हजार वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत कहता है। वह अरुणाचल में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा पर भी आपत्ति करता रहा है। उसने अपनी विस्तारवादी आकांक्षाओं को तेज करते हुए अरुणाचल प्रदेश के छह जगहों के नाम अवैधानिक रूप से बदल कर वोग्यैनलिंग, मिला री, काईनदेन गाब री, मेन क्यू का, बूमो ला और नामका पुब री रख दिए हैं। चीनी विशेषज्ञ इसे चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बता चुके हैं।

ल्हासा से न्यिंग्ची रेलमार्ग नेपाल से चीन के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से भी बेहद अहम है। यह रेल योजना कुल एक हजार सात सौ किलोमीटर की है। इसे सिचुआन-तिब्बत रेल खंड का सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण भाग माना जा रहा है। चीन हमेशा से ही नेपाल के साथ विशेष संबंधों का पक्षधर रहा है। तिब्बत पर कब्जे के बाद उसकी सीमाएं नेपाल से जुड़ गई हैं। चीन की नेपाल नीति का मुख्य आधार यह था कि नेपाल में बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव न जमा सकें और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की सुरक्षा हो सके। दूसरा नेपाल में भारत के प्रभाव को कम किया जाए। उसने नेपाल में अनेक परियोजनाएं आक्रामक ढंग से शुरू कर तिब्बत से सीधी सड़क भारत के तराई क्षेत्रों तक जोड़ी और नेपाल की कुदारी सीमा तक रेल मार्ग बना लिया।

● **राजेश बोरकर**

योग्य लोगों की तलाश

सरकार के जंग लगे दफ्तरों में खाली पद पड़े हुए हैं और कुर्सियों पर धूल जमी हुई है। कुछ कुर्सियों को झाड़ पोंछ कर चमका दिया गया है, ताकि उन पर अपने लोग आराम से बैठ सकें, लेकिन दूसरे बड़े और महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड, पार्टी, सतर्कता आयोग, न्यायपालिका, सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं, इन सब जगहों में पद वैसे ही खाली पड़े हुए हैं जैसे चाटुकारों का दिमाग खाली होता है। पूर्व में राजनीतिक मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों ने कहा है कि आसमान साफ रहेगा, बादल नहीं होंगे न ही बारिश की कोई संभावना है। सतर्कता आयोग एक बहुत ही ताकतवर संस्थान है, लिहाजा, केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों का कोई व्यक्ति उस पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक आयोग स्वयं उनके नाम को हरी झंडी नहीं दिखाता है।

1.3 अरब जनसंख्या वाले देश में प्रतिभा का अकाल है। हालांकि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसका सत्ताधारी दल, इसकी न्यायपालिका और इसकी जरूरत से ज्यादा लोगों वाली अफसरशाही को इन खाली जगहों को भरने के लिए पर्याप्त योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अगली बार में यकीन नहीं करती, क्योंकि इसके दर्जनभर मंत्रियों के पास दो या उससे ज्यादा मंत्रालय हैं। इसकी वजह यह है कि भाग्यशाली लोगों में योग्य लोग नहीं हैं।

भाजपा संसदीय बोर्ड में कई पद खाली पड़े हैं, जिन पर पिछले पांच साल से धूल जमी हुई है और मकड़े के जाले लटक रहे हैं। पिछले मानसून सत्र में भाजपा के अंदर के लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे और 11 सदस्यों वाले बोर्ड में खाली पड़े पांच पदों को भरेंगे। नड्डा अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा कर चुके हैं, पर उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। संसदीय बोर्ड के सात सदस्य हैं-नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और महासचिव बीएल संतोष जो मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं और भाजपा में डेपुटेशन पर भेजे गए हैं। भाजपा के संसदीय बोर्ड का पिछली बार गठन 2014 में हुआ था, जब अमित शाह ने राजनाथ सिंह से अध्यक्ष पद का कार्यभार लिया था। उन्होंने बोर्ड का पुनर्गठन किया था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे पुराने व अनुभवी सदस्यों को निकाल बाहर किया था और शिवराज सिंह चौहान व जेपी नड्डा को इसमें शामिल किया था। एम वेंकैया नायडू जब उपराष्ट्रपति बन गए तो बोर्ड की एक और कुर्सी खाली हो गई। इसके बाद अनंत कुमार, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मृत्यु हो गई। हाल ही में एक और पुराने नेता व राज्यसभा में भाजपा के नेता थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। अमित शाह ने अपनी गूढ़ बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इन पदों को नहीं भरने का फैसला किया। नड्डा को जनवरी 2020 में जब अध्यक्ष पद मिला, वे उस समय से ही नए नामांकन को लेकर ध्यान की मुद्रा में हैं। भाजपा के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि वह आधी क्षमता पर काम कर रही है। यह संसदीय बोर्ड ही है जो नीतियां बनाता है, मुख्यमंत्रियों का चुनाव करता है, विधानसभाओं के नेता, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करता है।

भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक बीते दो साल में एक बार भी नहीं हुई है। इस पर अंतिम बार दौड़-धूप 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले की गई थी। केसरिया पार्टी के नेताओं के मुताबिक, शाह और मोदी अभी भी विश्वसनीय और साफ छवि वाले नेताओं की तलाश में हैं, जो तटस्थ निर्णय ले सकें। वे महिलाएं, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी तलाश रहे हैं ताकि पुरुष सत्ता को नया रूप दिया जा सके। अभी तो संसदीय बोर्ड में एक भी महिला सदस्य नहीं है। इसकी वजह शायद यह है कि मोदी-शाह के नेतृत्व में पार्टी इतनी कुशलता से काम कर रही है कि पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र उस समय एकदम सख्त हो जाता है जब शीर्ष पर आम सहमति नहीं बन पाती है। और यह कब हो सकेगा, यह तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है।

● **ऋतेंद्र माथुर**

सम्मान की पुनर्बहाली, लेकिन पूरी नहीं

लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका भी इस बात पर दुखी है कि उसके यहां सारे पद भरे हुए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट को 9 खाली पदों को भरने में लगभग तीन साल लग गए। न्यायपालिका में वह दिन ऐतिहासिक बन गया जब एक दिन में सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जजों ने शपथ ली। सभी हाईकोर्ट अपनी क्षमता के 60 प्रतिशत जजों के साथ ही काम कर रहे हैं। विधि मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, हाईकोर्टों में जजों के 1,080 स्वीकृत पदों में से 400 पद खाली पड़े हुए हैं। निचली अदालतों में जजों के 24,247 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 4,928 पद खाली हैं। अर्द्ध न्यायिक और पंचाटों में भी बड़े पैमाने पर पद खाली पड़े हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सरकार से कहा कि देश के पंचाटों में अध्यक्षों, तकनीकी सदस्यों व न्यायिक सदस्यों के 240 पद खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने खुलेआम कहा है कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जजों की अध्यक्षता में बनी सेलेक्शन कमेटियों की सिफारिशों के बावजूद ये पद खाली हैं।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी

केरल की एक वरिष्ठ नन सिस्टर लूसी ने अपनी साथी नन के साथ एक बिशप द्वारा किए दुष्कर्म के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया। इसके बाद सिस्टर लूसी को वेटिकन की अनुमति से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और पुस्तक प्रकाशित करने जैसे कारण बताकर, चर्च की अवज्ञा करने के लिए न केवल बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षिका के रूप में प्राप्त वेतन से भी वंचित कर दिया गया। देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की बेला पर न केवल एक नन, बल्कि एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश भी एक भारतीय महिला के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। इस राष्ट्र की सामूहिक चेतना को अंतरावलोकन कर समाज में समान अधिकारों को बहाल करने का आह्वान करना होगा, जो हमारी विरासत के साथ संविधान में भी निहित है।

एक बहुलवादी समाज के रूप में भारत हमेशा समावेशी रहा है, जहां सभी विविधता में सह-अस्तित्व का सम्मान करते हैं। हालांकि बदलते सामाजिक परिवेश में समाज के कई समुदाय स्वयं दमनकारी, रूढ़िवादी प्रथाओं और रीति-रिवाजों पर मंथन कर उन्हें त्यागने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक ऐसी सामाजिक संरचना विकसित हो जो समान मौलिक व नागरिक अधिकारों में विश्वास करती हो। महिलाओं और समाज सुधारकों ने बार-बार आगाह किया है कि धार्मिक प्रथाओं की आड़ में, कई रीति-रिवाज लैंगिक भेदभाव करते हैं और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखतें हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों की 1911 की जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय हिंदू कानूनी रूप से बहुविवाह कर सकते थे, लेकिन व्यवहार में यह असामान्य था। हिंदू समुदायों में वैदिक विरासत और रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक संबंधों की पवित्रता जीवनोपरांत भी मानी जाती है।

वैवाहिक जीवन में तलाक एक असंभव विकल्प था। बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं ने विवाह में अलग होने का वैध अधिकार दिए जाने की मांग वर्ष 1930 में ही उठाई थी। भारत की संसद ने वर्ष 1950 के बाद हिंदू कोड बिल के द्वारा हिंदू महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए। इस संदर्भ में 19वीं और 20वीं सदी में प्रतिक्रियावादी ताकतों को दरकिनार करते हुए सामाजिक परिवर्तनों ने भारतीय समाज को रूढ़िवाद से मुक्त किया। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत किए गए संवैधानिक प्रविधान सभी भारतीय नागरिकों को समानता के अधिकार, भेदभाव और शोषण से संरक्षण प्रदान करते हैं। विडंबना यह है कि हमारा संविधान अभी भी सिस्टर लूसी जैसी महिलाओं के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। भारतीय संदर्भ में एक पंथनिरपेक्ष राज्य सर्वधर्म समभाव का पालन करता है, परंतु सभी समुदायों की महिलाओं को समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में शासन की सीमाएं हैं।

समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर कानूनों का सीमांकन वास्तव में एक राष्ट्र के पंथनिरपेक्ष होने पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान सभा में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा भी यह प्रश्न उठाया गया है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे एचसी मुखर्जी जो ईसाई मत के अनुयायी थे, उन्होंने अल्पसंख्यक होने के आधार पर विधानमंडल में सीटों के आरक्षण प्रस्ताव का विरोध किया। संविधान सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले तजामुल हुसैन ने कहा था कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए हैं और अब 'अल्पसंख्यक' शब्द को हमारे शब्दकोश से हटा देना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में समान नागरिक अधिकारों पर विचार करते हुए कहा था कि वर्ष 1937 तक उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत जैसे हिस्सों में उत्तराधिकार के मामले में एक ही कानून हिंदुओं और मुसलमानों को शासित करता था। बाबा साहब ने सदन को यह भी बताया था कि केरल के उत्तरी मालाबार में मातृ सत्तात्मक मरुमक्कथायम कानून हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमानों पर भी लागू होता था। परंतु रूढ़िवादी सोच और आस्था की ढाल के पीछे छिपकर सभी समुदायों को समान सामाजिक व नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया और समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

सुरक्षा की नई चिंताएं भी

यद्यपि वर्तमान सरकार ने तलाक कानूनों में असमानता को दूर करने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक लाकर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की ओर कदम उठाया है, लेकिन बहुविवाह और हलाला जैसे रीति-रिवाज अभी भी लैंगिक न्याय पर हावी हैं। बहुविवाह की स्थिति में, हिंदू से विवाहित महिला के लिए कानून उसके अधिकारों की रक्षा करता है, परंतु मुस्लिम से विवाह करने पर वही कानून लाचार है। पारसी समुदाय की महिलाओं ने भी 1936 के पारसी विवाह और तलाक अधिनियम पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अधिनियम के अनुसार पारसियों के वैवाहिक मुद्दों को विशेष पारसी अदालतों द्वारा निपटाया जाता है जहां न्यायाधीश के साथ पारसी समुदाय से प्रतिनिधि सदस्य भी होते हैं जो न्यायाधीश को सुझाव देते हैं। इसी संदर्भ में पारसी महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और संहिताबद्ध कानूनों के अधीन पारिवारिक अदालतों के तंत्र को लागू करने की अपील की है। राष्ट्रीय अस्मिता व एकता को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में दिए सार्वभौमिक सिद्धांत, जिनकी परिकल्पना बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं द्वारा की गई थी, उन्हें जीवंत करना आवश्यक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि में आस्था और पंथ से परे मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों के समान कानून राष्ट्रीय अस्मिता के सूत्रधार बनेंगे।

मंगल करनि कलि मल हरनि

गोस्वामी तुलसीदास अनन्य रामभक्त होने के साथ ही साथ लोककल्याणकारी भावना से ओतप्रोत कवि भी थे। अतः उन्होने धर्म और मुक्ति की प्राप्ति के साधन रूप श्रीराम की भक्ति की जो निर्मल अजस्र धारा प्रवाहित की वह नितांत रूप से लोकमंगलकारी सिद्ध हुई। गोस्वमी तुलसीदास की धारणा थी कि –

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित दुःख भागभवेत।।

अर्थात् सभी सुखी रहें, सभी सांसारिक माया मोह से दूर रहें, सभी सतकल्याणमय कार्यों के अभिलाषी रहें और किसी को कभी कोई दुख न हो। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के आरंभ में ही पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि –

मंगल करनि कलि मल हरनि
तुलसी कथा रघुनाथ की।
इसे इन्होंने मानस के अंत में और भी स्पष्ट कर दिया है कि –
कलि मलि हरनि विषय रस फीकी।
सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की।।
दलनि रोग भव मूरि अमी की।
तात मात सब विधि तुलसी की।।

इस प्रकार श्रीराम की कथा कलियुग के पापों को नष्ट करने वाली और समाज का कल्याण करने वाली है क्योंकि इस कथा में सर्वत्र विषय रस अर्थात् सांसारिक भोगों की प्रचुरता का फीकापन ही व्याप्त है। भाव यह है कि इस कथा में कहीं भी भौतिक भोगों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बात नहीं कही गई है। श्रीराम की कथा वह संजीवनी है जो शरीरस्थ और मनस्थ सभी प्रकार के रोगों को दूर कर देती है। जिसे लोग मधुर के स्थान पर कटु समझ कर त्याग देते हैं। परंतु जब मनुष्य अंधकार, क्लेश, हताशा, निराशा, अस्थिरता में डूब जाता है, ऐसे समय में रामकथा ही एकमात्र ऐसा रामबाण है जो प्राणिमात्र को इन विषम परिस्थितियों से उबार कर नई प्राणशक्ति का संचार कर रसाबोर कर देती है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, समरसता, समन्वय, मुक्ति, सदाचार जैसे उद्दात्त तत्व पूर्ण रूप में विद्यमान हैं।

मानस की कथा को तुलसी ने कलियुग के पापों को नष्ट करने वाली, लोक और परलोक में सुख देने वाली, विषय विकारों को नष्ट करने वाली और अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा उसमें उद्दात्त मानवीय तत्वों का समावेश करके 'वसुधैव कुटुंबकम,' 'आत्मवतसर्वभूतेषु',' 'बहुजनहिताय बहुजनरताय,' तथा 'सर्वभूतहितरेता,' के रूप में प्रस्तुत करके पूर्णतया लोकमंगलकारी बना दिया। इसका मूल रस शांत है।

मानस की कथा को तुलसी ने कलियुग के पापों को नष्ट करने वाली, लोक और परलोक में सुख देने वाली, विषय विकारों को नष्ट करने वाली और अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा उसमें उद्दात्त मानवीय तत्वों का समावेश करके 'वसुधैव कुटुंबकम,' 'आत्मवतसर्वभूतेषु',' 'बहुजनहिताय बहुजनरताय,' तथा 'सर्वभूतहितरेता,' के रूप में प्रस्तुत करके पूर्णतया लोकमंगलकारी बना दिया। इसका मूल रस शांत है। इसकी बुनियाद सदाचार, त्याग, तप संतोष, सदाचार, परोपकार जैसे सुदृढ़ साधना के ऐसे सोपान हैं जिन पर चढ़कर मनुष्य इस मायामय सागर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। रामचरितमानस का मूल उद्देश्य सत और असत को तथा उनके सद परिणामों को दिखाकर जीवन के प्रति आस्था तथा लोक और परलोक में सुख-प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। '(रामचरितमानस में सांस्कृतिक चेतना, दो शब्द)। तुलसी के अनुसार मनुष्य लोभ मोहादि जैसे विकारों में लीन रहकर अपने जीवन को व्यर्थ ही गवां देता है। तुलसीदास ने साधिकार इस मत की प्रतिष्ठा की है कि रामकथा ही एकमात्र ऐसा अमृत स्रोत है जिसकी अबाध धारा में लीन होकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन और समस्त सांसरिक रोगों से मुक्त हो जाता है।

तुलसीदास ने रामकथा का प्रणयन स्वान्तः सुखाय के लिए नहीं वरन परान्तः सुखाय हेतु ही किया था। तुलसी ने अपने सभी ग्रंथों में इसी लोकमंगल को दर्शाया है और समस्त प्राणियों को मंगलकारी भक्ति का सुलभ और सीधा मार्ग बताया है। इसीलिए उन्होंने इसे कलि मल हरण मंगल करन तुलसी कथा रघुनाथ कि कहा है। इससे यह स्वतः ही सिद्ध हो गया है कि गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में लोकमंगल की भावना का सागर यत्र तत्र उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

गोस्वामी तुलसीदास ने राम को नितांत रूप से ईश्वर मानते हुए कहा है कि वे मनुष्य नहीं ईश्वर हैं और मनुष्यों का कल्याण करने के लिए ही अयोध्या राजवंश में मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे। रावण के दरबार में अंगद द्वारा कही गई इस उक्ति से इस तथ्य कि पुष्टि हो जाती है–

राम मनुज कस रे सठ बंगा।
सुरभि कामधेनु सर गंगा।

इस प्रकार तुलसी कि दृष्टि राम के ईश्वरत्व पर केंद्रित रही है। तुलसी के राम निर्गुण का सगुण अवतार थे जो लोक कल्याण हेतु दुष्टों के विनाश और सज्जनों कि रक्षा हेतु ही पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हुए। अतः उन्होने जो मानव चरित लोक में प्रस्तुत किया था वह उनकी लीला थी। जिसका एकमात्र उद्देश्य संसार के कष्टों को दूर कर धर्म, भक्ति और मुक्ति की स्थापना ही था। इसकी पुष्टि करते हुए तुलसी ने कहा है कि–

बिप्र धेनु सुर संत हित।
लीन्ह मनुज अवतार।।
निज इच्छा निर्मित समूह।
माया गुन गोपाल।।

गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में स्थान स्थान पर श्रीराम के इसी लोक कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन करते हुए यही स्थापित किया है कि हमें निरंतर श्री राम के गुणों का गान और उनके नाम का जाप करते रहना चाहिए। तुलसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि –

राम जपु राम जपु राम जपु बावरे।
घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे।।

इस प्रकार तुलसीदास ने परम लोकमंगलकारी श्रीराम नाम के जाप को प्रथम स्थान दिया है और राम भक्ति का सही निर्वाह करने के लिए उन्होंने सदाचार पालन को अनिवार्य बताया है, जो लोक कल्याण का केंद्र बिंदु है क्योंकि बिना सदाचार पालन के न तो भक्ति ही सफल होती है और न ही वह मुक्तिफलदायक है।

● **ओम**

दरोगाजी की उदारता

दरोगा जी ने सरकारी गाड़ी रुकवा दी। अचानक से गाड़ी रुकने पर कांस्टेबल रामफल मुंह फाड़कर एक टक दरोगा जी को देखने लगा।

'मुंह बंद कर, दारू की बदबू आ रही है। ये ले मेरा फोन वीडियो प्लस फोटोग्राफी अच्छे से करना।' दरोगा जी ने रामफल को आदेश दिया।

फुटपाथ पर एक बीमार सा व्यक्ति फटे पुराने चीथड़ों में लिपटा हुआ पड़ा था। उसके पास आकर दरोगा जी ने प्यार से उसे उठाया और ढाबे से लाईं रोटियां बीमार आदमी को थमा दीं, साथ ही एक निवाला दरोगा जी ने उसके मुंह में अपने हाथ से दिया भी। 'धन्यवाद!' हाथ जोड़कर वापस दरोगा जी गाड़ी में आ विराजे।

'अरे वाह! सर जी आपका तो बहुत बड़ा हृदय है। पर जूठीं रोटियां तो आपने चौकी के कुत्तों के लिए ली थीं।' रामफल ने आश्चर्य भाव में डरते हुए सवाल किया।

'चल फोन दे, तू नहीं समझेगा, फोटो सही से लिए कि नहीं, जरा देखूँ।'

दूसरे दिन अखबारों में एक पुलिस ऑफिसर की उदारता की न्यूज देशभर के लोगों ने पढ़ी। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते दरोगा जी का वीडियो वायरल हो गया।

– मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

निमंत्रण

मेरी छुट्टी मंजूर हो गई उषा जी! आपकी हुई कि नहीं? काफी दिनों से मायके नहीं जा पाई थी, निमंत्रण मिलते ही आवेदन किया था। देखिए झटपट स्वीकृत हो गई, रंजना उत्साहित थी।

प्रत्युत्तर न मिलने से प्रश्न दुहराया। उषा जी के नयनों के कोर से जाने क्यों कुछ नमी सी झलक आई, जी! मैं रक्षाबंधन में नहीं जा रही हूं। अधिकतर शिक्षिकाएं छुट्टी पर जा रही हैं, कुछ लोगों का यहां होना भी जरूरी है।'

उषा जी! आपने भी खूब कही! सिर्फ चार घंटे का रास्ता है आपके मायके का। एक दिन की छुट्टी लेने से काम चल जाता। यूं तो हम मायके जाते ही रहते हैं, पर रक्षाबंधन में बात ही कुछ और होती है। मां-भाभी के हाथों के पकवान, भाई का प्यार और उपहार, रिश्तेदारों की आवा-जाही। वाह भाई वाह! रौनक होती है। भाभी का मायका उसी शहर में है, मुझसे मिलकर वह मायके चली जाती हैं।

मैं ही बड़बड़ाये जा रही हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं! कहीं मैं आपके निजी मामलों में दखलअंदाजी तो नहीं कर रही? रंजना खामोश हो गई।

ऐसा नहीं है रंजना जी! इस स्कूल में बारह सालों से हम साथ हैं, इंसान किसी के आगे अपना दिल खोलता ही है। हमने भी अपने सारे सुख दुख बांटे हैं। आपको अच्छे मूड में देखा तो उदासी घोलने का मन नहीं हुआ। मैंने छुट्टी का आवेदन नहीं दिया था। मेरा रक्षाबंधन में मायके जाने का प्रोग्राम नहीं है।

आपने पूछा है तो बताती हूं। मेरे बच्चे बढ़ती उम्र के साथ अब समझदार हो गए हैं। वहां मेरे और दीदी के बीच किए गए भेदभाव को समझने लगे हैं। दीदी बड़े व्यवसाई की पत्नी हैं, उनके परिवार को विशिष्ट आवभगत मिलती है। मैं और मेरे पति शिक्षक हैं, पहुंचते ही रसोई में धकेल दी जाती हूं। रसोई ही मायका बन जाता है।

शिकायत नहीं करती; यूं तो वर्ष भर जाने कितनी बार आना-जाना लगा रहता है। दीदी से भी मुलाकातें होती हैं, पर कुछ वर्षों से रक्षाबंधन पर हम दोनों बहनें बारी-बारी जा पाती हैं।, स्वर में दर्द प्रतिध्वनित हुआ।

रंजना विचारों में डूब गई, क्या धनाभाव मां-बाप के प्यार में अंतर ला सकता है? सारे नहीं, पर कुछ मां-बाप अपवाद स्वरूप अवश्य ऐसे होते होंगे, तभी तो ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं।'

– नीना सिन्हा

आचमन

मीत ने गीत का आचमन जो किया,
तार वीणा के फिर झनझनाने लगे!
स्याह सूनी अमावस के जैसा हृदय,
रात पूनम की बनकर रिझाने लगे!
मीत ने गीत का आचमन जो किया।
शब्द हैं पुष्प और अर्चना गीत है,
प्रार्थना आरती, वंदना दीप है!
पुष्पमाला को लेकर समर्पण की हम,
थाल पूजा का फिर से सजाने लगे!
मीत ने गीत का आचमन जो किया।
सूखी तपती धरा सा, ये जीवन मेरा,
मेघ बन कर वो बरसे इला खिल उठी!
सोंधी मिट्टी से फिर मन मयूरी हुआ,
गीत सावन के हम गुनगुनाने लगे!
मीत ने गीत का आचमन जो किया।
राग छेड़ो अगर, रागनी बनके तुम ,
बनके सुर साज तुझमे समां जाऊंगा!
प्रीत का गीत बनकर के मनमीत फिर
ताल सरगम की हम तो बजाने लगे!
मीत ने गीत का आचमन जो किया।
रंग भरकर के जीवंत जीवन किया,
भाव बिखरे छटा इंद्रधनुषी खिली!
यूं उदासी भरा था अभी चित्रपट,
उगते सूरज को अब हम बनाने लगे!
मीत ने गीत का आचमन जो किया।
कूकी कोयल सुरभि मन बसंती हुआ।
फूली सरसों फुटित मन की कलियां हुई।
आगमन है तुम्हारा या ऋतुराज का,
खेत खुशियों के फिर लहलहाने लगे।
मीत ने गीत का आचमन जो किया।

– पंकज त्रिपाठी

पैरालिंपिक में दिखा भारत का दम

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती; नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है; मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है; आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती...सोहनलाल द्विवेदी की कविता की ये पंक्तियां पैरालिंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर सटीक बैठती हैं। टोक्यो पैरालिंपिक खेलों में सातवें दिन तक भारत ने 2 गोल्ड सहित कुल 10 मेडल जीत लिए। भारत ने पहली बार किसी पैरालिंपिक या ओलिंपिक में 10 मेडल जीते हैं। भारत के लिए एथलीट अवनि लेखरा, सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल, देवेंद्र झाझरिया, योगेश कथुनिया, भाविनाबेन पटेल, निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलू ने सिल्वर और शरद कुमार, सुंदर गुर्जर, सिंहराज अधाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत को अभी कुछ और मेडल की उम्मीद है। मेडल जीतने वाले हर खिलाड़ी की अपनी सक्सेज स्टोरी है।

टोक्यो पैरालिंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने पहला पदक दिलवाया। टोक्यो में भारत के निषाद कुमार ने देश को दूसरा पदक दिलाया है। निषाद कुमार ने पुरुषों की टी 47 ऊंची कूद में 2.06 मीटर की कूद लगाई और दूसरा स्थान हासिल किया। दूसरे प्रयास की इस कूद के साथ उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड की भी बराबरी की। इस प्रतियोगिता में अमेरिका के टाउनसेंड रोडेरिक ने विश्व रिकॉर्ड 2.15 मीटर की कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता। तीसरे स्थान पर भी अमेरिका के विसे डलास रहे जिन्होंने 2.06 मीटर की कूद लगाई। आपको बता दें कि पैरालिंपिक्स में यह भारत का दूसरा पदक है। निषाद से पहले भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने रजत पदक अपने नाम किया था। निषाद ने पैरालिंपिक खेलों की शुरुआत से पहले बेंगलुरु के कोचिंग कैंप में महीनों तक कड़ी मेहनत की थी। इस अहम मुकाबले से पहले उनके गांव में उनके लिए लगातार दुआएं मांगी जा रही थीं। मेडल जीतने के बाद गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। टोक्यो में पुरुषों को ऊंची कूद में निषाद कुमार के रजत पदक (सिल्वर मेडल) जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली 19 वर्षीय शूटर अवनि लेखरा टोक्यो पैरालिंपिक खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास एसएच1 में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को गर्व का एहसास कराया है। इतना ही नहीं पैरालिंपिक में गोल्ड जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। उन्होंने 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। यह पैरालिंपिक खेलों का नया रिकॉर्ड है। उन्होंने फाइनल में चीन की रियो पैरालिंपिक की गोल्ड मेडल विनर झांग कुइपिंग को हराया है, जिन्होंने 248.9 अंक प्राप्त किए। अब अवनि मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन एसएच1, 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन एसएच1 और मिक्स्ड 50 मीटर राइफल प्रोन में भी हिस्सा लेंगी। एसएच1 राइफल वर्ग में वे निशानेबाज शामिल होते हैं, जो बंदूक थाम सकते हैं, लेकिन पांवों में विकार होता है।

8 नवंबर 2001 को जयपुर में जन्मीं अवनि लेखरा की जिंदगी में साल 2012 में एक बहुत खराब मोड़ आया। वो जब 11 साल की थीं, तब एक कार हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। उनको पैरालिसिस हो गया था। इसके बाद वो हमेशा-हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गईं। इस हादसे ने अवनि को बुरी तरह तोड़ दिया। वो अक्सर चुप रहने लगीं। किसी से बात नहीं करती थी। पूरी तरह डिप्रेशन में चली गईं। इतनी कमजोर हो गई थी कि कुछ कर नहीं पाती थी।

बेटी की हालत देख पिता इस बात की चिंता में रहते थे कि कैसे उसे सदमे से बाहर निकाला जाए। उनको लगा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है, जिससे स्वस्थ शरीर और मन दोनों मिल सकता है। उन्होंने अवनि को खेल की तरह आकर्षित किया। लेकिन समस्या ये थी कि वो इतनी कमजोर हो गई थी कि एथलेटिक्स में नहीं जा सकती थी। तीरअंदाजी में कोशिश की, लेकिन वहां प्रत्यंचा ही नहीं खींच पाई। इसके बाद पिता शूटिंग रेंज ले गए। वहां पहली बार तो गन तक नहीं उठा पाई, लेकिन आज पैरालिंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। अवनि लेखरा के पिता राजस्थान सरकार में रेवेन्यू अपील अधिकारी हैं। बेटी को इस मुकाम तक लाने में उन्होंने बहुत मेहनत और त्याग किया है। यहां तक कि जब अवनि को जयपुर के जगतपुरा में स्थित शूटिंग रेंज प्रैक्टिस के लिए जाने के लिए परेशान का सामना करना पड़ा, तो पिता ने जगतपुरा में ही घर खरीद लिया। उसके बाद पूरे परिवार के साथ शूटिंग रेंज के पास ही शिफ्ट हो गए। इसके बाद अवनि को प्रैक्टिस के लिए सुविधा मिल गई।

अवनि खेल के साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार हैं। उनको किताबें पढ़ने का काफी शौक है। हर दिन खेल के साथ पढ़ने में भी काफी वक्त बिताती है। उनकी शूटिंग चुनने की एक वजह देश के जाने-माने शूटर अभिनव बिंद्रा भी हैं, जिनकी बायोग्राफि अ शॉट एट हिस्ट्री पढ़ने के बाद वो शूटिंग के प्रति ज्यादा गंभीर हो गईं। इतना ही नहीं वह आरजेएस की तैयारी भी कर रही हैं, ताकि वह जज बन सके और इंसाफ के लिए भटक रहे लोगों को न्याय दिला सके।

● आशीष नेमा

ये आदमियों की दुनिया है, बराबर वेतन मिलने वाली चर्चा का कोई मतलब नहीं : नीना गुप्ता

बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक लंबे समय से चर्चा जारी है कि आखिर क्यों एक्टर्स को एक्ट्रेसेस से ज्यादा फीस दी जा रही है। इस मामले में अब सीनियर एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपनी राय सामने रखी है। एक्ट्रेस का कहना है कि महिलाओं और पुरुषों के वेतन में हमेशा से बड़ा अंतर रहा है, लेकिन ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर सेक्टर में होता है।

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, वेतन समता का सवाल मुझे पसंद है। मुझे बताइए कि किस प्रोफेशन में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिला है। देखिए एक हाउस वाइफ कितना काम करती है। क्या कभी उसे इसका वेतन मिलता है। नहीं। उसे घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ लेने के लिए उसे अपने पति से इजाजत लेनी पड़ती है।

पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं महिलाएं

आगे एक्ट्रेस ने कहा, आपको पसंद हो या ना हो लेकिन ये आदमियों की दुनिया है। तो चाहे ये घर हो या दफ्तर पुरुष हमेशा काम करता है। एक महिला, पुरुष से काफी ज्यादा काम करती है। आप कह सकते हैं कि अरे उस आदमी को काम में कितना स्ट्रेस है लेकिन महिलाओं का तो काम ही कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो घर की सफाई हो, खाना बनाना हो या घर का किराया देना हो। और इन सबके लिए कोई शुक्रिया अदा भी नहीं करता। एक्ट्रेस का मानना है कि आदमियों को हमेशा से ही महिलाओं से आगे रखा जाता है। एक्ट्रेस ने कहा, ये वेतन समता वाली चर्चा का तो कोई मतलब ही नहीं होता। पहले आदमी हैं और उसके बाद औरतें। ये सब कुछ हमेशा से ही ऐसा रहा है।

कबीर खान मुगलों को फिल्मों में गलत तरीके से दिखाने पर नाराज, बोले- वो तो असली राष्ट्र-निर्माता थे...

बजरंगी भाईजान के निर्देशक कबीर खान का कहना है कि उनके लिए मुगलों को बदनाम करने वाली फिल्में देखना काफी निराश करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की फिल्में सिर्फ 'वर्तमान लोकप्रिय सोच और विचारों' को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं और इनका कोई 'ऐतिहासकि साक्ष्य' नहीं है। 'न्यूयॉर्क' और 'ट्यूबलाइट' जैसी फिल्में बना चुके कबीर खान का कहना है कि 'मुगल असली राष्ट्र-निर्माता' थे।

एक इंटरव्यू में कबीर खान ने कहा, मुझे इस तरह की फिल्मों से बहुत परेशानी है और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह है ये फिल्में सिर्फ इस समय पॉपुलर सोच को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि जब एक फिल्ममेकर रिसर्च करता है और अपनी फिल्म के जरिए अपना एक पॉइंट रखना चाहता है। बेशक किसी भी चीज को दिखाने के अलग-अलग नजरिए हो सकते हैं। अगर आप मुगलों को गलत दिखाना चाहते हैं, प्लीज उसे किसी रिसर्च के आधार पर करिए और बताइए कि आखिर ऐसा क्यों है समझाइए कि वो आखिर विलेन क्यों हैं और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप इतिहास सच में पढ़ेंगे तो आपके लिए ये समझना मुश्किल होगा कि आखिर उन्हें विलेन क्यों बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि वह तो असली राष्ट्र-निर्माता थे।

सैफ एक मैच्योर पर्सन और एक अच्छे पिता हैं: शर्मिला टैगोर

बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बेटे, एक्टर सैफ अली खान में चेंजिस के बारे में बात की है और कहा कि वो एक मैच्योर पर्सन बन गए है। शर्मिला के मुताबिक, सैफ, जो हाल ही में अपने चौथे बच्चे के पिता बने हैं, एक अच्छे पिता हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सैफ को अब खाना पकाने और पढ़ने जैसे नए शौक डेवलप हुए हैं।

शर्मिला ने सैफ को बताया मैच्योर पर्सन

शर्मिला कहती हैं, मैंने ये दिल्लगी देखी और यहां तक कि उनके पुराने इंटरव्यू भी बहुत मजेदार थे। वो एक मैच्योर पर्सन बन गए हैं। वो चार बच्चों के पिता हैं और एक बेहतरीन शेफ बन गए हैं। उन्होंने पढ़ने जैसे अच्छे शौक डेवलप किए हैं। वो एक अच्छे पिता हैं और अच्छा खाना बनाते हैं।

कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से शर्मिला, सैफ से नहीं मिल पाईं हैं... शर्मिला ने यह भी बताया कि कैसे वो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सैफ और उनकी फैमिली से नहीं मिल पाई हैं। हेल्थ इश्यूज के कारण शर्मिला लंबी दूरी तक ट्रैवल करने में असमर्थ हैं। वो अभी तक सैफ के नवजात बेटे जहांगीर अली खान को भी नहीं देख पाई हैं।

पप्पू पास हो गया

आज कॉलोनी में सुबह-सुबह जैसे ही एक प्रश्न गूंजा- 'पप्पू पास हो गया?' प्रत्युत्तर में मानो कॉलोनी में कोरस सा छा गया- 'हमारा भी पप्पू पास हो गया। हमारा भी पप्पू पास हो गया।' बाद में पता चला ये मेरी कॉलोनी का ही नहीं पूरे देश का हिट गीत है 'हमारा पप्पू भी पास हो गया।' सालों से पप्पू के बेहूदा प्रश्नों और तर्कों से परेशान मां को सहसा विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका पप्पू इस बार पंच्यानबे प्रतिशत अंक लेकर पास हो गया है, क्योंकि उनके पप्पू की बात सुनकर रिक्शावाला भी हंसने लगता था। उनके अनुसार पप्पू सबका मनोरंजन तो कर सकता था लेकिन पास कभी नहीं हो सकता था।

पर यह सच था कि पप्पू पास हो गया था। जो काम सालों से हजारों की ट्यूशन, कोचिंग और बुद्धिजीवी शिक्षक नहीं कर सके, वह एक छोटे से अदृश्य कीटाणु ने कर डाला। बेलाइन पप्पू आज ऑनलाइन पढ़ाई की पटरी पर चलकर पास हो गया था। पप्पू की मां सोच रही थी कि यदि इस कोरोना की फोटो मिल जाती तो सरस्वती जी की फोटो की जगह लगा देती। सोने की मूर्ति बनाकर पांच टाइम उसकी आरती उतारती।

अध्यापक महोदय दिल मसोसकर रह गए। यह वही पप्पू था जिसके पास हो जाने पर वे अपनी मूंछे तक मुढ़वाने की सार्वजनिक घोषणा कर चुके थे। बेचारे मुंह छिपाए घूम रहे थे कि पप्पू कहीं चौराहे पर उन्हे भीष्म प्रतिज्ञा याद न दिला दे। वह पप्पू जो घर से स्कूल के लिए निकलने बाद कक्षा में कम और सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाता हुआ टॉकीज-होटलों में लैलाओं की जुल्फों से खेलता हुआ ज्यादा मिलता, वह पप्पू बिना कक्षा में गए पास हो गया। यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा चमत्कार है। इस कोरोना नाम के जीव ने भले ही लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दी लेकिन हजारों पप्पुओं को आत्महत्या करने से बचा लिया। हे कोरोना! तुम धन्य हो। तुम्हारी प्रतिमा नगर के हर मुख्य चौराहे पर लगाने का प्रस्ताव मैं शिक्षामंत्री को देता हूं। भविष्य में जब आरक्षण की बैसाखी पर लटक कर करोड़ों पप्पू देश का भविष्य गढ़ेंगे तो तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

पप्पू को चीन हमेशा से भाता था। कभी-कभी तो वह घूमने भी चला जाता था। लगता था जैसे किसी पुरखे ने रिश्ता जोड़ दिया हो। चीन का थर्ड क्लास सामान पप्पू गले से लगाकर रखता था। सब समझाते रह गए 'मेड इन चायना-नो गारंटी।' आज पप्पू शान से कहता है कि चीन ने कोरोना का उत्पादन कर पप्पुओं को पास हो जाने की पूरी गारंटी दे दी है। पप्पू का नया नारा है- जब तक सूरज चांद रहेगा, कोरोना का नाम रहेगा।

कबीर बाबा होते तो सिर पीट लेते। कहते-कहते दुनिया से चले गए कि- करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात से सिल पर परत निसान।। आज पप्पू के पास, पास होने का आसान फॉर्मूला है। वो काहे रस्सी से पत्थर काटेगा। वह तो कहता है - करत-करत अभ्यास के कोई न होत सुजान। कोरोना माई की किरपा से हम हो गए विद्वान ।।

हमारे जमाने में पप्पू के लिए परीक्षा में पास होना परीक्षा हो जाने के बाद परिश्रम और शोध का विषय होता था। पप्पू परीक्षा के पर्चे देने के लिए पढ़ाई करने वाली मेहनत पर विश्वास नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वह कर्मयोगी था। घंटों टेबल लैंप के प्रकाश में बैठकर अध्ययन करना उसे अकर्मण्यता लगती थी। उसके पुरुषार्थ को ठेस पहुंचाती थी। वह पुरुषार्थी पेपर निपटते ही द्रोणाचार्य की तलाश में निकल पड़ता जो जो बिना अंगूठा मांगें कुछ नोटों में उसे पास कर देता था। पप्पू भी खुश होता था कि खानदान की नाक कटने से बच गई और द्रोणाचार्य भी खुश कि बिना अंगूठा कटवाए मोटी गुरू दक्षिणा मिल गई। कुछ द्रोणाचार्य तो परीक्षा संपन्न होने के कुछ महीने बाद अक्सर पूंजीपति से लगते थे। मैंने उस समय अनेक गणित-विज्ञान-अंग्रेजी के द्रोणाचार्यों को बैंक में नए खाते खुलवाना देखा है। पर आज इस नासपीटे कोरोना और ऑनलाइन पढ़ाई ने कई द्रोणाचार्यों की मुकेश अंबानी बनने की इच्छा पर पानी फेर दिया। आज पप्पू बिना किसी द्रोणाचार्य के सहारे पास हो गया।

पास होने पर पप्पू और मम्मी-पापा बहुत खुश हैं। लेकिन वह अर्जुन आंसू बहा रहा है जो दिन-रात साधना रत था और जिसका लक्ष्य सिर्फ चिड़िया की आंख थी।

● **शरद सुनेरी**

अध्यापक महोदय दिल मसोसकर रह गए। यह वही पप्पू था जिसके पास हो जाने पर वे अपनी मूंछे तक मुढ़वाने की सार्वजनिक घोषणा कर चुके थे। बेचारे मुंह छिपाए घूम रहे थे कि पप्पू कहीं चौराहे पर उन्हे भीष्म प्रतिज्ञा याद न दिला दे। वह पप्पू जो घर से स्कूल के लिए निकलने बाद कक्षा में कम और सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाता हुआ टॉकीज-होटलों में लैलाओं की जुल्फों से खेलता हुआ ज्यादा मिलता, वह पप्पू बिना कक्षा में गए पास हो गया।

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल

फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

Science House Medicals Pvt. Ltd.

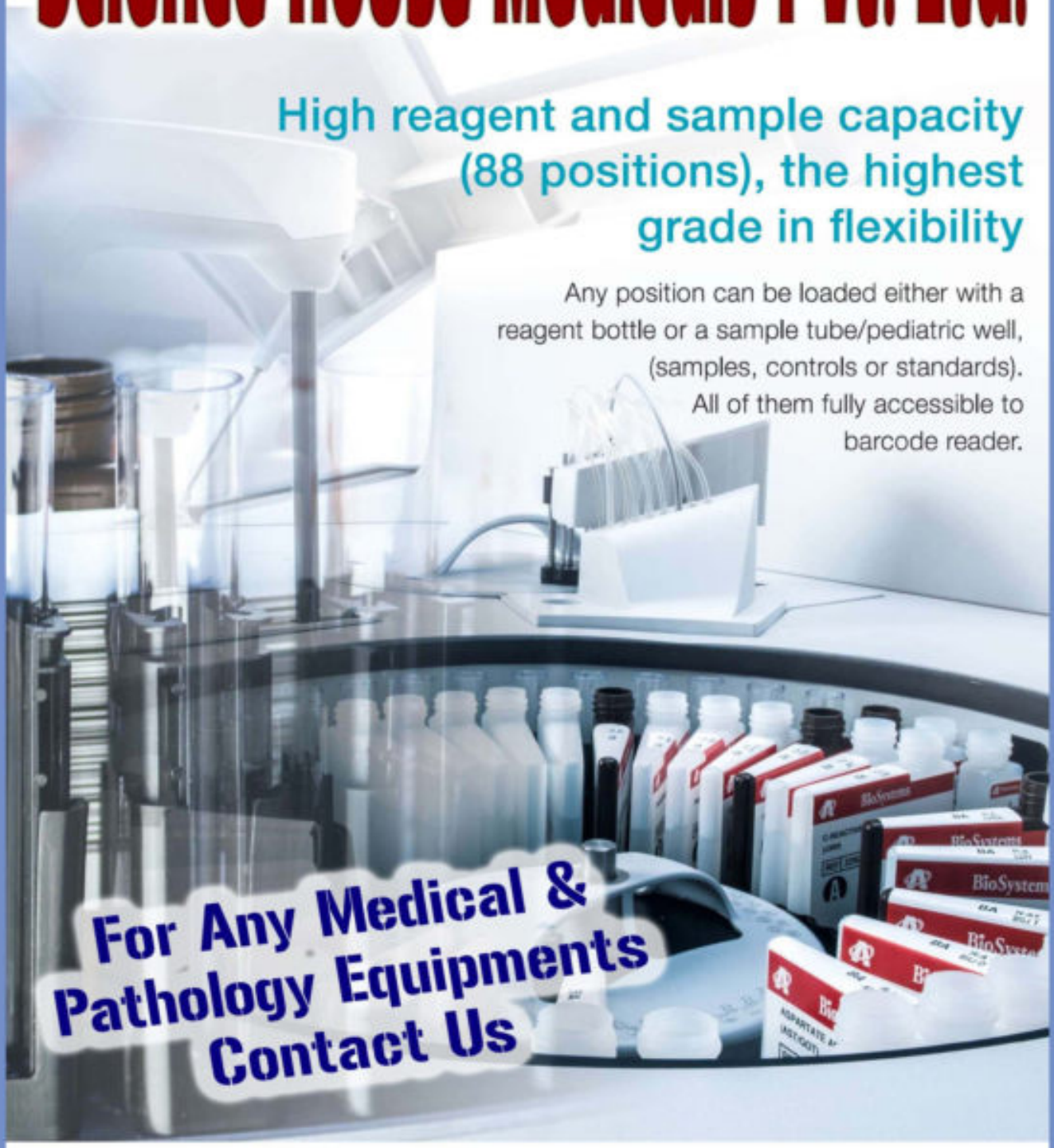

High reagent and sample capacity (88 positions), the highest grade in flexibility

Any position can be loaded either with a reagent bottle or a sample tube/pediatric well, (samples, controls or standards). All of them fully accessible to barcode reader.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com

Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687